राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

गौरवशाली भारत

दिल्ली से प्रकाशित

R.N.I. NO. DELHIN/2011/38334 वर्ष- 10, अंक- 199 पृष्ठ - 08, नई दिल्ली, शुक्रवार ,08 जनवरी 2021, मूल्य रु. 1.50

किसानों का शक्ति प्रदर्शन

छाया : सुरेन्द्र कुमार

नई दिल्ली (एजेंसी)। गुरूवार को भारत से लेकर अमेरिका तक आंदोलन और विद्रोह का ऐसा उबाल देखने को मिला जिसमें जनता का आक्रोश चरम पर रहा। भारत में कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने दिल्ली के चारों तरफ ट्रैक्टर मार्च निकाला। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के बाद जिस हिंसा की आशंका थी और ये हुई भी। जिद्दी डोनाल्ड ट्रम्प समर्थकों ने हिंसा कर चुनाव परिणाम बदलने का दबाव बनाया, लेकिन अंत में ट्रंप को झूकना पड़ा। उधर, शुक्रवार को किसानों और सरकार के बीच 9वें दौर की बातचीत होनी है। इसमें कौन मानेगी इस पर पूरे देश की नजर है।

कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन का गुरुवार को 43वां दिन था। किसानों ने दिल्ली के चारों तरफ ट्रैक्टर मार्च निकाला। मार्च में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। यह मार्च सिंघु बॉर्डर से टिकरी, टिकरी से शाहजहांपुर, गाजीपुर से पलवल और पलवल से गाजीपुर तक निकाला गया। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि हम सरकार को चेतावनी देने के लिए यह रैली निकाल रहे हैं। 26 जनवरी को हम ट्रैक्टर की परेड निकालेंगे। उन्होंने कहा कि हम मई, 2024 तक आंदोलन के लिए तैयार हैं। ट्रैक्टर मार्च को संबोधित करते हुए किसान नेता सतनाम सिंह पन्नू, सरवन सिंह पंढेर, स्वर्ण सिंह चटला, जसबीर सिंह पिडी ने कहा कि मोदी सरकार 133 करोड़ लोगों की आवाज सुने बिना विभिन्न षड्यंत्रों को अपना रही है। इस मुद्दे को सुलझाने के लिए किसान संगठनों के साथ बातचीत चल रही है और दूसरी तरफ, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल कह रहे हैं कि देश के किसान संगठन कृषि कानूनों के पक्ष में हैं। ऐसे बयान देकर केंद्र सरकार दोयम दर्जे का काम कर रही है।

केएमपी एक्सप्रेस-वे पर किसानों की ट्रैक्टर रैली शुरू हो गई है। सिंघु बॉर्डर से किसानों से का जत्था पलवल की ओर निकल पड़ा है। इस दौरान सैकड़ों ट्रैक्टर के साथ हजारों किसान मौजूद हैं। ट्रैक्टर मार्च के कारण 15 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई है।

भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि तीनों कृषि कानूनों को लेकर सरकार से कई दौर की वार्ता हो चुकी है। भाजपा सरकार जिद पर अड़ी है, क्योंकि उन्हें ये भ्रम है कि आज तक ये होता आया है कि प्रधानमंत्री ने जो कानून लागू किए हैं, वो वापस नहीं हुए हैं, लेकिन जिस देश की जनता सड़कों पर है और राजा को नींद आए तो समझ लेना चाहिए कि मामला गड़बड़ है। पत्रकारों से चढ़ूनी ने कहा कि सरकार किसानों की ताकत की परीक्षा ले रही है।

किसानों का कहना है कि सरकार ने मांगें नहीं मानीं तो 26 जनवरी को भी ट्रैक्टर परेड होगी। आज का मार्च उसी का ट्रेलर है। हरियाणा के किसान संगठनों ने हर गांव से 10 महिलाओं को 26 जनवरी के लिए दिल्ली बुलाया है। यही अपील क्क के किसानों ने की है। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर मार्च की अगुआई महिलाएं ही करेंगी। हरियाणा की करीब 250 महिलाएं ट्रैक्टर चलाने की ट्रेनिंग ले रही हैं।

किसानों और सरकार के बीच 4 जनवरी की मीटिंग बेनतीजा रही और अगली तारीख 8 जनवरी तय हुई। अगली मीटिंग में कृषि कानूनों को वापस लेने और एमएसपी पर अलग कानून बनाने की मांग पर बात होगी। यह 9वें दौर की बैठक होगी। इससे पहले सिर्फ 7वें दौर की मीटिंग में किसानों की 2 मांगों पर सहमति बन पाई थी, बाकी सभी बैठकें बेनतीजा रहीं।

एक महीने से अधिक समय से केंद्र के 3 कृषि कानूनों के विरोध में जारी किसान आंदोलन को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड 19 महामारी और किसान आंदोलन को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि किसानों का आंदोलन 2020 में दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में उत्पन्न हुई तबलीगी जमात जैसी स्थिति बना सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा है कि क्या आंदोलन में किसान कोरोना संक्रमण के प्रसार के खिलाफ एहतियाती कदम उठा रहे हैं।

ट्रंप समर्थकों का हुड़दंग

दुनियाभर के नेताओं ने की निंदा

तोक्यो, (एजेंसी)। अमेरिका में कैपिटल बिल्डिंग में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों के हंगामे और हिंसा की दुनिया भर के नेताओं ने निंदा की है। इसके साथ ही विभिन्न देशों के नेताओं ने शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता हस्तांतरण का आह्वान किया है। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेंसिंडा आर्डन ने कहा कि जो हो रहा है, वह गलत है। उन्होंने कहा, लोकतंत्र में लोगों के पास मतदान करने का, अपनी बात रखने और फिर उस फैसले को शांतिपूर्ण तरीके से मनवाने का अधिकार होता है। इस भीड़ द्वारा उलटा नहीं जाना चाहिए। अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थकों ने अमेरिकी लोकतंत्र के हृदयस्थल पर जिस तरह के अराजक दृश्य पैदा किए वे आम तौर पर उन देशों में दिखाई देते हैं, जहां लोक उभार से किसी तानाशाह का तख्तापलट होता है। अरब स्प्रिंग या चेकोस्लोवाकिया के मखमली क्रांति इसके मिसाल हैं।

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंतोनियो गुतारेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा, महासचिव वाशिंगटन डीसी के यूएस कैपिटल में हुई घटनाओं से दुखी हैं। उन्होंने कहा,ऐसी स्थिति में, यह महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक नेता अपने समर्थकों को हिंसा से दूर रहने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया और कानून के शासन में विश्वास करने के लिए राजी करें। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ट्वीट किया, अमेरिकी संसद परिसर में अशोभनीय दृश्य देखने को मिले। यह महत्वपूर्ण है कि सत्ता हस्तांतरण शांतिपूर्ण और तय प्रक्रिया के तहत उचित तरीके से हो। अमेरिका के अन्य सहयोगी देशों ने भी इस लोकतंत्र पर हमला बताया है। हालांकि, कुछ ने कहा है कि उन्हें भरोसा है कि अमेरिका की लोकतांत्रिक व्यवस्था इससे उबर आएगी। कुछ नेताओं ने निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तीखी आलोचना की। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने अमेरिका में हिंसा की घटनाओं को दुखद बताया। ये चिंताजनक है। अमेरिका में चीनी दूतावास ने भी अपने नागरिकों को हालात से सावधान किया है।

जर्मनी के विदेश मंत्री हीको मास ने लिखा, ट्रंप और उनके समर्थकों को अमेरिकी मतदाताओं का फैसला स्वीकार कर लेना चाहिए और लोकतंत्र पर हमला बंद करना चाहिए। नाइजीरिया के राष्ट्रपति के निजी सहायक बशीर अहमद ने ट्वीट किया, लोकतंत्र की खूबसूरती नाइजीरिया में आजादी के बाद कई बार तख्तापलट हो चुके हैं। वहां कई दशक बाद लोकतांत्रित तरीके से मुहम्मदू बुहारी के नेतृत्व में सरकार बनी है। चिली के राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा और कोलंबिया के राष्ट्रपति इवान ड्यूक उन लातीन अमेरिकी देशों के नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने प्रदर्शनकारियों की निंदा की। दोनों नेताओं ने भरोसा जताया कि अमेरिका में लोकतंत्र और कानून का शासन कायम रहेगा। इटली में भी लोगों ने हिंसा की घटना पर हैरानी जताकर कहा कि अमेरिका को हमेशा लोकतांत्रिक देश के मॉडल के तौर पर देखा जाता है।

रिया चक्रवर्ती के एफआईआर पर बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित

मुंबई, (एजेंसी)। बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिवंगत फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की बहनों के खिलाफ रिया चक्रवर्ती की शिकायत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसके अलावा कोर्ट ने सभी पार्टियों को अपना लिखित जवाब एक हफ्ते में दाखिल करने का भी आदेश दिया है। गुरुवार को इस मामले पर कोर्ट में सुनवाई हुई थी। बता दें रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की बहनों प्रियंका मीतू सिंह और डॉक्टर तरुण कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि सुशांत की बहन प्रियंका ने डॉक्टर से मिलकर सुशांत के लिए फर्जी प्रिस्क्रिप्शन लिखवाया था। सुशांत की मानसिक हालत जाने बिना उनके लिए दवाइंया लिख दी गई थीं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि सुशांत को 8 जून को यह दवाइयां प्रिस्क्राइब की गई थीं और 14 जून को एक्टर ने खुदकुशी कर ली थी। इसलिए तीनों पर खुदकुशी करने के लिए मजबूर करने का भी आरोप बनता है।

ज्ञात हो कि सुशांत सिंह राजपूत पिछले साल 14 जून को अपने मुंबई स्थित घर में खुदकुशी कर ली थी। सीबीआई, ईडी और एनसीबी इस केस की जांच में लगे हुए हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स एंगल आने के बाद रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया था। वह करीब 1 महीने तक जेल में रही थीं। जिसके बाद रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी।

प्रधानमंत्री ने लंबी कंटेनर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

रेवाडी, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पश्चिमी समर्पित मालवहन गलियारा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 306 किमी लंबे न्यू रेवाड़ी-न्यू मदार खंड को राष्ट्र को समर्पित किया। वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से आयोजित एक समारोह में प्रधानमंत्री ने न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़ के लिए विश्व के पहले डबल स्टैक लांग हॉल कंटेनर ट्रेन आपरेशंस1.5 किलोमीटर लंबी कंटेनर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इस अवसर पर रेल मंत्री पीयूष गोयल, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र और हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य के अलावा दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री क्रमशः अशोक गहलोत और मनोहर लाल खट्टर उपस्थित थे। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए चल रहे महायज्ञ ने आज एक नई गति हासिल की है। बीते दिनों आधुनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के मदद से किसानों के खातों में सीधे 18,000 करोड़ रुपये से ज्यादा ट्रांसफर किए गये हैं। जब नए साल में देश का आगाज अच्छा है। तो आने वाला समय भी शानदार और जानदार होना तय है। पीएम मोदी ने कहा कि न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़ तक 1.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ियों की शुरूआत के साथ भारत दुनिया के गिने चुने देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। दिन हरियाणा और राजस्थान के किसानों, उद्यमियों, व्यापारियों के लिए नए अवसर लाया है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर चाहे ईस्टर्न हो या वेस्टर्न ये सिर्फ मालगाड़ियों के लिए आधुनिक रुट नहीं हैं। ये देश के तेज विकास के कॉरिडोर हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ दिन ही पहले भारत ने कोरोना की दो मेड इन इंडिया वैक्सीन की स्वीकृति दी है। भारत की अपनी वैक्सीन ने देशवासियों में एक नया आत्मविश्वास पैदा किया है। आज हर भारतीय का आह्वान है कि न हम रुकेंगे, न हम थकेंगे, हम सब मिलकर और तेजी से बढ़ेंगें । पीयूष गोयल ने कहा कि लगभग 5,800 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित न्यू रेवाड़ी-न्यू मदार खंड के शुरू हो जाने से हरियाणा के प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल उद्योग, व राजस्थान के खनिज उद्योगों को एक बड़े राष्ट्रीय बाजार के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार भी उपलब्ध हो जायेगा उन्होंने कहा, यह गलियारा इन राज्यों से गुजरता हुआ वह धागा है जो इन्हें आपस में बांधते हुए इन क्षेत्रों के समुचित आर्थिक और सामाजिक विकास में योगदान करेगा और भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई गति प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि आने वाले अगले 100 दिनों में मदार को गुजरात के पालनपुर से जोड़ दिया जाएगा जिससे गुजरात के कांडला, पीपावाव और मुंद्रा बंदरगाह भी समर्पित मालवहन गलियारे के नेटवर्क से जुड़ जाएंगे।

केंद्र समूचे कृषक समुदाय का भरोसा खो चुका है : हरसिमरत

नई दिल्ली, (एजेंसी)। लोकसभा में तीनों कृषि कानून पारित होने के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वालीं शिरोमणि अकाली दल की नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कहा है कि केंद्र समूचे कृषक समुदाय का भरोसा खो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आंदोलनकारी किसानों के साथ सीधे वार्ता करनी चाहिए। किसानों की पीड़ा पर अपना दुख प्रकट करते हुए बादल ने कहा, यह अजीब है कि किसान कंपकंपा देने वाली ठंड में खुले में रातें गुजार रहे हैं और बहरे कानों तक उनकी आवाजें नहीं पहुंच पा रही है।

उन्होंने कहा, अब जो स्थिति पैदा हुई है और विरोध हो रहा है, इससे बचने के लिए मैं महीनों तक मंत्रिमंडल की बैठकों में या केंद्र सरकार के शीर्ष नेताओं के साथ सीधी वार्ता में यह कहती रही कि तीनों विधेयक लाने के पहले एक बार किसानों की बात सुन लीजिए क्योंकि वे देश के अन्नदाता हैं। अन्यथा आंदोलन होगा, लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। लेकिन बहरे कानों तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पायी।

कार्टून

गांगुली को अस्पताल से छुट्टी मिली

कोलकाता, (एजेंसी)। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) अध्यक्ष और पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को गुरुवार को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। गांगुली ने अस्पताल से बाहर आने के बाद कहा कि वो ठीक हैं और शीघ्र ही अपने काम में वापसी करेंगे। गांगुल को गत शनिवार को दिल का दौरा पड़ने के कारण यहां के वुडलैंड्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जिसके बाद उनकी एंजियोप्लास्टी हुई थी। वहीं अब घर पर ही गांगुली के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा।

अस्पताल से छुट्टी मिलने पर गांगुली ने कहा, हम अपनी जान बचाने के लिए अस्पताल आते हैं। यह सच साबित हुआ।मैं वुडलैंड्स अस्पताल और उत्कृष्ट देखभाल के लिए सभी डॉक्टरों को धन्यवाद देता हूं। मैं बिल्कुल ठीक हूं। उम्मीद है कि जल्द ही अपने काम में वापसी करूंगा।

गांगुली की शनिवार को ही एंजियोप्लास्टी की गई थी। अस्पताल के अनुसार गांगुली के दिल की नसों में बाकी ब्लॉकेज के लिए होने वाली अगली एंजियोप्लास्टी पर फैसला बाद में लिया जाएगा, क्योंकि वह पहले से काफी बेहतर हैं।

इससे पहले जाने-माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. देवी शेट्टी ने कहा था, गांगुली फिट हैं और अब वह फिर से सामान्य जीवन की ओर लौट सकते हैं, जैसा कि वह पहले थे। उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है। डॉ. शेट्टी वुडलैंड अस्पताल में गांगुली का उपचार कर रहे 13 डॉक्टरों से भी मिले थे। उन्होंने कहा, गांगुली जल्द स्वस्थ हो जाएंगे क्योंकि उनका हृदय उसी तरह काम कर रहा है जैसा कि 20 साल की उम्र में करता था। डॉ. शेट्टी ने कहा, यह कोई बड़ा दिल का दौरा नहीं था. इससे उनके हृदय को कोई क्षति नहीं पहुंची है, इससे भविष्य में उनके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वह सामान्य जीवन बिता सकते हैं।

लड़ना ही है तो अब संसद में आकर ही लड़ूंगा : वाड्रा

नई दिल्ली, (एजेंसी) कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा ने आयकर विभाग से कड़ी पूछताछ और किरकिरी के बाद राजनीति में उतरने और चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। वाड्रा ने आरोप लगाया कि उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया गया क्योंकि वह एक प्रमुख राजनीतिक परिवार से संबंधित हैं। गुरुवार को राबर्ट वाड्रा ने कहा कि मैं एक ऐसे परिवार से संबंधित हूं, जिसने पीढ़ियों से इस देश के लोगों की सेवा की है और देश के लिए शहीद भी हुए हैं। मैंने देखा है, सीखा है, अभियान चलाया है। देश के विभिन्न हिस्सों में समय बिताया और मुझे लगता है कि मुझे इसी शक्ति के साथ लड़ने के लिए संसद में रहना होगा।

रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि स्पष्ट रूप से अब मुझे लगता है कि मैंने बहुत लंबे समय तक बाहर लड़ाई लड़ी है। मैंने खुद को समझाया है, लेकिन यह लगातार हो रहा है कि वे मुझे परेशान करते हैं, क्योंकि मैं राजनीति में नहीं हूं। वाड्रा ने कहा कि वह उचित समय पर फैसला लेंगे। उन्होंने कहा, जब मैं एक ऐसी जगह देखूंगा, जहां लोग मुझे प्रतिनिधित्व करने के लिए वोट देंगे और मैं उस क्षेत्र के लोगों के जीवन में एक अंतर ला सकता हूं और अगर मेरा परिवार इसे स्वीकार करता है। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि पूरा परिवार विशेष रूप से प्रियंका उनके फैसलों का समर्थन करती हैं। उन्होंने कहा, प्रियंका हमेशा सपोर्टिव हैं। मैं पूरे परिवार के बारे में बात कर रहा हूं और जब वे इसे मंजूरी देंगे, तो मैं राजनीति में हो सकता हूं और राजनीतिक क्षेत्र में अपने मुद्दों के लिए लड़ सकता हूं।

वाड्रा ने रायबरेली और अमेठी में चुनाव प्रचार किया है और उनके समर्थन में मुरादाबाद में होर्डिंग्स लगाए गए हैं, क्योंकि उन्होंने दावा किया कि उन्होंने अपना बचपन उस जगह पर बिताया है और लोग चाहते हैं कि वे वहां रहें।

रॉबर्ट वाड्रा ने जोर देकर कहा कि वह राजनीति में नहीं होने के बिना भी वह राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं और उन्हें हर बार पंचिंग बैग के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जब भी सरकार बाध्य होती है। वाड्रा बेनामी संपत्ति के आरोप को खारिज करते हैं। उन्होंने कहा, ये सिर्फ अफवाहें हैं और मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं है। इसका कोई आधार नहीं है कि वे ऐसा कुछ भी कह सकते हैं। इस पर उनकी कोई स्पष्टता नहीं है।

रिपब्लिकन पार्टी ही ट्रंप को पद से हटाना चाहती है

वाशिंगटन, (एजेंसी)। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी के कैपिटल हिल में ट्रंप समर्थकों द्वारा की गई, हिंसा में महिला की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल भी हुए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ही हिंसा के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है क्योंकि न सिर्फ उन्होंने समर्थकों से संसद पर चढ़ाई का आह्वान कर कहा था कि वे किसी भी कीमत पर हार स्वीकार नहीं करुंगा। ट्रंप के भड़काऊ बयानों के मद्देनजर फेसबुक, ट्विटर और इन्स्टाग्राम ने उनका अकाउंट फिलहाल सस्पेंड कर दिया है। इसी बीच खबर है कि ट्रंप कैबिनेट के लोग ही उन्हें हटाने की तैयारी में हैं। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप कैबिनेट के सदस्यों ने हिंसा के बाद एक खुफिया बैठक की है, जिसमें संविधान के 25वें अमेडमेंट का इस्तेमाल कर ट्रंप को पद से हटाने पर भी चर्चा की गई है। ये खबरें हैं कि उपराष्ट्रपति माइक पेंस और ट्रंप के बीच पैदा हुए तनाव के बाद बाहर आ रही हैं। बता दें कि जब ट्रंप समर्थक संसद में घुसे,तब सत्र की अध्यक्षता पेंस ही कर रहे थे और वे ट्रंप समर्थकों के इस व्यवहार से काफी खफा भी नजर आए। उन्होंने न सिर्फ इस अमेरिकी इतिहास का काला दिन बताया, बल्कि ट्रंप समर्थकों से वापस चले जाने की अपील भी की। इसके बाद खबर है कि ट्रंप ने पेंस के चीफ आफ स्टाफ को व्हाइट हाउस से चले जाने का फरमान सुना दिया है।

खबरें आ रही हैं कि व्हाइट हाउस के कई स्टाफ मेंबर्स ने बीते दिनों ट्रंप की मानसिक स्थिति पर भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है लेकिन व्हाइट हाउस स्टाफ ने शिकायत की है कि ट्रंप न सिर्फ अकेले में बड़बड़ाते रहते हैं बल्कि चिल्लाने भी लगते हैं। खबर के मुताबिक ट्रंप कैबिनेट के सदस्यों और रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं ने भी ट्रंप की मानसिक स्थिति को लेकर चचाएं की हैं। कैपिटल हिल हिंसा के बाद रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर मिट रोमनी ने घटना के बाद कहा मैं इस घटना की निंदा करता हूं। मैं शर्मिंदा हूं कि हमारे राष्ट्रपति ने दंगाइयों को संसद में घुसने के लिए भड़काया। लोकतंत्र में जीत और हार को स्वीकारने की हिम्मत होनी चाहिए। मैं अपनी पार्टी के सहयोगियों से भी उम्मीद करता हूं कि वे लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे आएंगे। अमेरिकी कांग्रेस में बोलते हुए पेंस ने कहा, जिन लोगों ने भी कैपिटल में कहर बरपाने की कोशिश की, वहां जीत नहीं सकते। हिंसा के दौरान एक ट्वीट में पेंस ने लिखा था, शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करना हर अमेरिकी नागरिक का अधिकार है, लेकिन यूएस कैपिटल पर हमले को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जो भी इसमें शामिल हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कैपिटल हिंसा की निंदा की है. बुश ने कहा है, यह हंगामा, इस तरह का राजद्रोह एक पागलपन है और जो नजारे देखने को मिल रहे हैं, उनसे उन्हें तकलीफ पहुंची है।

उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयोग में एक पार्टी की एक कांग्रेस में भाग लेते हुए शीर्ष नेता किम जोंग उन।

बर्फ में तब्दील हुई टंढ़जा नदी पर हुए एक धार्मिक समारोह में एकत्र लोगों के बीच क्रॉस लेकर खड़ा हुआ एक बच्चा।

सीपीसी सदस्यों के लिए सख्त नियम, सार्वजनिक मतभेद जाहिर करने पर पाबंदी

बीजिंग, (एजेंसी)। चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी इस साल अपना 100वां स्थापना दिवस मनाने की तैयारियों में है और इसी बीच उसने अपने 9.2 करोड़ सदस्यों के लिए नियमों में बदलाव करते हुए मतभेदों को सार्वजनिक रूप से उजागर करने पर पाबंदी लगा दी है और साथ ही कहा है कि इस प्रकार की गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पार्टी के संशोधित नियमों के अनुसार अगर पार्टी के नेता अयोग्य पाए जाते हैं तो पार्टी कार्यकताओं को उन्हें हटाने की मांग करने का अधिकार दिया गया है। माओ-त्से तुंग द्वारा 1921 में स्थापित कम्युनिस्ट पार्टी आफ चाइना (सीपीसी) 1949 में सत्ता में आई और इस साल जुलाई में अपने शताब्दी वर्ष पर भव्य आयोजन की योजना बना रही है। सीसीपी एकदलीय प्रणाली में सबसे लंबे समय तक सत्ता में बनी रहने वाली मार्क्सवादी पार्टी है। संशोधित नियमों में सूचना प्राप्ति और आंतरिक शिकायतों के समाधान पर नया दिशा-निर्देश जारी किया गया है और इसे पार्टी के भीतर लोकतंत्र को बढ़ावा देने के रूप में दिखाया जा रहा है।

नए नियम में स्पष्ट किया गया है कि पार्टी अपने रैंक में किसी के मतभेद को बर्दाश्त नहीं करेगी, विशेष रूप से अगर सार्वजिक रूप से शिकायत की जाती है तो। पार्टी के सदस्य आलोचना करते हैं, खुलासा करते हैं या समाधान और सजा के लिए अनुरोध करते हैं, उन्हें संगठन के तंत्र का उपयोग करना चाहिए। उन्हें उसे स्वतंत्र रूप से इंटरनेट पर नहीं डालना चाहिए। तथ्यों को तोड़ना-मरोड़ना नहीं चाहिए, फर्जी तथ्य नहीं डालने चाहिए। नियम पुस्तिका के प्रावधान 16 में कहा गया है कि पार्टी के सदस्यों को ऐसे विचार सार्वजनिक मंच पर नहीं रखने चाहिए जो सीपीसी की केन्द्रीय समिति के विचार के अनुरुप ना हों।

बाइडन से एच-1बी वीजा प्रतिबंधों को कम करने का आग्रह किया

वाशिंगटन, (एजेंसी)। भारत केंद्रित एक शीर्ष अमेरिकी व्यापार पैरोकारी समूह ने बाइडन प्रशासन से आग्रह किया है कि वह एच-1बी वीजा पर प्रतिबंधों को कम करें और देश में आईटी पेशेवरों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त छात्रों को ग्रीन कार्ड दें। दरअसल अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 31 दिसंबर को सबसे अधिक मांग वाले एच-1बी वीजा के साथ ही दूसरे सभी तरह के विदेशी कार्य वीजा पर रोक को तीन महीनों के लिए 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया था, इस फैसले से बड़ी संख्या में भारतीय आईटी पेशेवर प्रभावित हुए। राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडन ने ट्रंप की आव्रजन नीतियों को क्रूर बताकर एच-1बी वीजा पर प्रतिबंधों को खत्म करने का वादा किया था।

अमेरिका-भारत रणनीतिक और साझेदारी मंच के अध्यक्ष मुकेश अघी ने बताया, यह एक कानूनी मसला है। हमारे द्वाराबाइडन प्रशासन से सिफारिश की है कि एच-1बी (वीजा) को आसान बनाएं, लेकिन साथ ही प्रत्येक स्टेम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) पीएचडी डिग्रीधारक को ग्रीन कार्ड देना चाहिए, ताकि वे यहां रह सकें और पहले दिन से करदाता के रूप में योगदान कर सकें। अघी ने कहा, हमारा पूरा समर्थन है और मुझे लगता है कि बाइडन प्रशासन की भावना भी ऐसी ही है। बाइडन 20 जनवरी को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालने वाले हैं।

वहीं अघी ने कहा कि हर साल जारी किए जाने वाले एच-1बी वीजा की संख्या को बाजार की मांगों के आधार पर तय किया जाना चाहिए। उन्होंने भारत में बने नए कृषि कानूनों का समर्थन करते हुए कहा कि तीनों कानून सही मकसद के लिए बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि तकनीक के इस युग में किसानों के पास अपनी उपज को मंडियों में बेचने या दूसरी जगह बेचने का विकल्प होना चाहिए। उन्होंने का कि कृषि कानून किसानों को यह विकल्प देते हैं।

ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन से कोहराम

लंदन, (एजेंसी)। कोविड-19 से अभी दुनिया को पूरी तरह निजात नहीं मिली और ब्रिटेन में कोरोना वायरस के दो-दो नए स्ट्रेन के आने के बाद हड़कंप मचा है और यहां हालात नियंत्रण के बाहर बताए जा रहे हैं। तेजी से फैल रहे संक्रमण को रोकने के लिए प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने देशव्यापी लॉकडाउन लागू किया हुआ है। उधर ब्रिटेन की मेट्रोपोलिटन पुलिस ने ऐलान किया है कि वह कोरोना वायरस लॉकडाउन का पालन कराने के लिए अब ज्यादा सख्ती बरतेगी। पुलिस ने बताया कि जो भी लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए पकड़े जाएंगे उनसे 10 लाख रुपये तक का तगड़ा जुमार्ना वसूला जाएगा। ब्रिटेन की पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे नियमों का पूरी तरह पालन करें। स्कॉटलैंड यार्ड ने कहा कि जो लोग प्रतिबंधों का उल्लंघन करेंगे, उन पर 200 पाउंड से 10,000 पाउंड (994751 रुपये) तक जुमार्ना लगाया जा सकता है। मेट्रोपोलिटन पुलिस ने कहा कि इसका अर्थ यह होगा कि पार्टी का आयोजन करने वालों, बिना अनुमति के संगीत समारोहों या अवैध सभाओं के आयोजकों ही नहीं बल्कि उनमें शामिल होने वाले लोगों पर भी जुमार्ना लग सकता है।

पुलिस ने कहा कि इसके अलावा मास्क नहीं लगाने पर भी जुमार्ना लग सकता है। मेट्रोपोलिटन पुलिस ने इस सप्ताह लंदन में एकत्र होने की योजना बना रहे प्रदर्शनकारियों को भी आगाह किया है कि वह लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर कार्रवाई करेगी। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए मेट्रोपोलिटन पुलिस की कार्रवाई का नेतृत्व कर रहे उप सहायक आयुक्त मैट ट्विस्ट ने कहा कि पुलिस अधिकारी के तौर पर हमारा पहला कर्तव्य जीवन की रक्षा करना है। उन्होंने कहा कि यदि लोग नियमों को तोड़ना जारी रखते हैं तथा स्वयं को, अपने परिवार को और अपने समुदायों को खतरे में डालते हैं, तो पुलिस अधिकारी कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। पुलिस फेडरेशन ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स ने भी लोगों से अपील की है कि वे लॉकडाउन लागू होने के मद्देनजर नियमों का पालन करें।

कोरोना वायरस के नए स्वरूप के कारण संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इसे देखते हुए ब्रिटेन ने सख्त लॉकडाउन लागू किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा था कि हमारे वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है कि वायरस का नया स्वरूप 50 से 70 प्रतिशत तक ज्यादा संक्रामक है... इसका अर्थ है कि इससे आपके संक्रमित होने और दूसरों को संक्रमित करने की आशंका बहुत-बहुत ज्यादा है। उन्होंने कहा था कि हमें राष्ट्रव्यापी सख्त लॉकडाउन लागू करना होगा ताकि वायरस के नए स्वरूप के मामलों को नियंत्रित कर सकें। इसका अर्थ है कि सरकार एक बार फिर आपको घर के भीतर रहने का निर्देश दे रही है। आप अनुमति के तहत सिर्फ कुछ ही कारणों से घर से बाहर निकल सकते हैं। जैसे कि जरुरी चीजों की खरीदारी के लिए, अगर आप घर से बिल्कुल काम नहीं कर पा रहे हों तो दफ्तर जाने के लिए, इलाज या जांच के लिए या फिर घरेलू हिंसा से बचने के लिए बाहर जा सकते हैं।

लड़कियों के कम्प्यूटर हैक मामले में भारतीय मूल के व्यक्ति को 11 साल की सजा

लंदन, (एजेंसी)। ब्रिटेन की एक अदालत ने भारतीय मूल के व्यक्ति को 574 से अधिक लड़कियों और महिलाओं के कम्प्यूटर में हैकिंग करने, धमकाने, ताक-झांक करने और साइबर अपराध का दोषी ठहराते हुए 11 साल जेल की सजा सुनाई है। यह हैकिंग उनका उत्पीड करने के इरादे से की गई थी। ब्रिटेन की क्राउन अभियोजन सेवा (सीपीएस) ने बताया कि आकाश सोंधी ने सैकडों सोशल मीडिया खातों में सेंधमारी की और 26 दिसंबर 2016 से 17 मार्च 2020 के बीच धमकी देने का अपराध किया। उन्होंने बताया कि दक्षिण-पूर्व इंग्लैंड के एक एसेक्स निवासी ने पीड़िताओं को धमकाया कि यदि वे उसे अपनी निर्वस्त्र तस्वीरें नहीं भेजेंगी तो वह उनकी अंतरंग तस्वीरें उनके दोस्तों एवं परिवार के सदस्यों को भेज देगा। सोंधी कम से कम छह महिलाओं को अपनी धमकी मनवाने में कामयाब रहा। सीपीएस से जुड़े एक वरिष्ठ अभियोजक ने कहा कि उसने युवा महिलाओं को भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक क्षति पहुंचाई है। सीपीएस के मुताबिक आरोपी के कृत्य के चलते पीड़िताओं को गंभीर मानसिक उत्पीड का सामना करना पड़ा, जिनमें से एक ने बाद में आत्महत्या तक का प्रयास किया।

सैन्य प्रशिक्षण में तकनीक का प्रयोग बढ़े : जिनपिंग

बीजिंग, (एजेंसी)। चीन में सशस्त्र बलों की शक्तियों का विस्तार करने वाले नए संशोधित कानून के इस साल से प्रभाव में आने के बीच राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने देश की सेना को आदेश दिया कि वे किसी भी सेकेंड कार्रवाई को तैयार रहें। शी जिनपिंग ने कहा पीपल्स लिब्रेशन आर्मी (पीएलए) को हर पल युद्ध के लिए तैयार रहन चाहिए। उन्होंने कहा अग्रिम टकरावों का इस्तेमाल अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए और प्रशिक्षण में टेक्नॉलजी का इस्तेमाल बढ़ाया जाना चाहिए।

सेंट्रल मिलिट्री कमीशन (सीएमसी) के पहले ऑर्डर में शी जिनपिंग ने वास्तविक युद्ध परिस्थितियों में प्रशिक्षण से सेना की मजबूती और जीतने की क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया। शी ने सेना से अपने युद्ध कौशल को और तराशने के लिए प्रशिक्षण को मजबूत करने एवं बिल्कुल चौकस रहने को कहा है। केंद्रीय सैन्य आयोग (सीएमसी) के साथ साथ सत्तारूढ़ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) के प्रमुख शी जिनपिंग (67) ने 2021 के लिए आयोग के पहले आदेश पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसमें पीएलए और पीपुल्स आर्म्ड पुलिस फोर्स के प्रशिक्षण में प्राथमिकताओं को सूचीबद्ध किया गया है।

सीएमसी 20 लाख सैन्यकर्मियों की सेना का हाईकमान है। इस नए आदेश में सशस्त्र बलों को नए युग में चीनी विशिष्टताओं के साथ शी जिनपिंग की समाजवादी सोच को अपने मार्गदर्शक सिद्धांत के तौर पर लेने तथा सेना एवं सैन्य रणनीतियों की मजबूती के संदर्भ में शी के विचारों पर चलने का निर्देश दिया गया है। सीसीपी सेना के प्रशिक्षण पर अपना मार्गदर्शन बढ़ाएगी तथा सेना से अपना युद्ध कौशल निखारने एवं अपने प्रशिक्षण तंत्र में सुधार जारी रखने पर ध्यान देने की भी अपील की गई है।

इससे पहले ऐसा आदेश जनवरी, 2018 में जारी किया गया था, जब शी ने उत्तरी चीन के एक शूटिंग रेंज में एक विशाल प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित किया था। सैन्यबलों द्वारा साल का पहला सैन्य प्रशिक्षण एवं अभ्यास शुरू किए जाने के बीच शी ने कहा कि पीएलए को किसी भी क्षण कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रशिक्षण एवं युद्धक तंत्र में नए औजार, नई ऊर्जाशक्ति को शामिल करना चाहिए।

व्हाइट हाउस की उप प्रेस सचिव ने दिया इस्तीफा

वाशिंगटन, (एजेंसी)। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों द्वारा कैपिटोल परिसर में हिंसा के बाद अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप की चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफनी ग्रीसम, व्हाइट हाउस की उप प्रेस सचिव सारा मैथ्यूज ने इस्तीफा दे दिया। ग्रीसम इससे पहले व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव के रूप में भी सेवा दे चुकी हैं। उनके बाद कैली मैकनेनी को अप्रैल में प्रेस सचिव बनाया गया। इस्तीफा देने वाली वह पहली व्यक्ति हैं। ग्रीसम ने ट्विटर पर एक बयान में कहा कि व्हाइट हाउस में सेवा देना, उनके लिए सम्मानजनक रहा और वह बच्चों की मदद करने के मेलानिया ट्रंप के मिशन का हिस्सा बनकर भी गौरवान्वित महसूस करती हैं तथा उन्हें इस प्रशासन की कई उपलब्धियों पर गर्व है। व्हाइट हाउस से इस्तीफा देने वाली वह पहली वरिष्ठ कर्मचारी हैं। मैथ्यूज ने भी इस्तीफा देने के बाद कहा कि संसद में काम करने वाले कर्मी के रूप में मैंने जो देखा, उससे बेहद दुखी हूं। मैं अपने पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे रही हूं। हमारे देश को शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता हस्तांतरण की जरूरत है। एबीसी न्यूज की खबर के मुताबिक व्हाइट हाउस की सामाजिक मंत्री रिकी निसेटा ने भी ट्रंप समर्थकों के हिंसक प्रदर्शन के मद्देनजर इस्तीफा दे दिया है। दरअसल जब नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन की जीत को प्रमाणित करने के लिए सांसद संसद के संयुक्त सत्र के लिए कैपिटोल परिसर के भीतर बैठे थे, तभी बुधवार को ट्रंप के समर्थक परिसर में घुस आए। इस दौरान पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई। हिंसा में कई लोगों के मरने और घायल होने की सूचना है।

हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक सदस्य एक पत्रकार वार्ता के दौरान देश भर में हुई गिरफ्तारियों पर विरोध व्यक्त करते हुए।

अभी भी जीवित हैं बॉन्ड गर्ल

लॉस एंजेलिस, (एजेंसी)। बॉन्ड गर्ल तान्या रॉबट्र्स की पब्लिसिटी का काम देखने वाले माइक पिंगल ने कहा है कि वह अभी भी जीवित हैं और अस्पताल में हैं। पिंगल ने कहा है, मुझे इसकी (रॉबट्र्स मौत की) पुष्टि की गई थी, लेकिन वह एक बहुत ही विचलित व्यक्ति (रॉबट्र्स के प्रेमी लांस ओब्रायन) ने की थी। आज सुबह 10 बजे अस्पताल ने यह कहने के लिए फोन किया था कि वह अभी जीवित है, लेकिन उनकी हालत ठीक नहीं लग रही है। उम्मीद है कि हम जल्दी जानकारी देंगे।

एक वीडियो इंटरव्यू में ओब्रायन को एक फोन आया जिसमें उन्हें बताया गया कि रॉबट्र्स की मौत नहीं हुई। इसमें वह कह रहे हैं कि अस्पताल ने मुझे बताया है कि वह जीवित है। यह फोन मुझे आईसीयू टीम से आया है। रॉबट्र्स को 1985 की फिल्म ए व्यू टू ए

किल में बॉन्ड गर्ल की भूमिका के लिए जाना जाता है। उन्होंने जॉन ग्लेन के निर्देशन में स्टेसी सटन का किरदार भी निभाया। छोटे पर्दे पर उन्होंने लोकप्रिय सीरीज चार्लीज एंजेल्स में एक एंजेल की भूमिका निभाई। इसके अलावा वह फैंटेसी आइलैंड और लव बोट के एपिसोड में भी दिखाई दी हैं। मालूम हो कि रविवार को पिंगल ने कहा था कि क्रिसमस की पूर्व संध्या पर अपने कुत्तों को टहलाने के दौरान रॉबट्र्स गिर गईं थीं। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

ठंड के साथ दिल्ली–एनसीआर में बढ़ेगा प्रदूषण का स्तर

नई दिल्ली, (संवाददाता)। झमाझम बारिश के कारण पिछले कई दिनों से दिल्ली-एनसीआर के प्रदूषण के स्तर में मिल रही राहत बुधवार को हवा होती दिखी। बारिश का दौर थमते ही प्रदूषण ने एक बार फिर सिर उठाना शुरू कर दिया है। प्रदूषक कणों की मात्रा में भी तेजी से इजाफा होने लगा है। बृहस्पतिवार सुबह से दिल्ली-एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में वायु गुणवत्ता स्तर में इजाफा हुआ है। वायु गुणवत्ता स्तर 250 के आसपास बना हुआ है। वहीं, सफर इंडिया के मुताबिक बारिश थमने और हवा की रफ्तार घटकर महज आठ किमी प्रतिघंटा रह जाने से प्रदूषक तत्व छंट नहीं पा रहे हैं। तापमान में गिरावट और उत्तर पश्चिमी हवा के साथ ठंडक आने के कारण आने वाले दिनों में प्रदूषण और बढ़ेगा। वहीं, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से जारी एयर बुलेटिन के मुताबिक, बुधवार को दिल्ली का एक्यूआइ (एयर क्वालिटी इंडेक्स) 226 रहा। जबकि, मंगलवार को यह 140 रहा था। एक दिन के भीतर ही इसमें 86 अंकों का इजाफा हुआ है। शाम को पांच बजे हवा में प्रदूषक कण पीएम 10 की मात्रा 134 रही, जबकि पीएम 2.5 कणों की मात्रा 90 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रही। मानकों के अनुसार हवा में पीएम 10 की मात्रा 100 और पीएम 2.5 की मात्रा 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर होनी चाहिए। एनसीआर के शहरों में फरीदाबाद का एक्यूआइ 203, गाजियाबाद का 234, ग्रेटर नोएडा का 239 और नोएडा का 200 दर्ज हुआ। इस श्रेणी की हवा को खराब श्रेणी में रखा जाता है। हालांकि, गुरुग्राम का एक्यूआइ बुधवार को भी मध्यम श्रेणी में यानी 175 ही दर्ज किया गया।

दिल्ली में मेडिकल कॉलेजों को फिर से खोलने का आदेश, जल्द शुरू होगी पढ़ाई

नई दिल्ली । कोरोना का संक्रमण कम होने के मद्देनजर दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल कालेजों को तत्काल प्रभाव से दोबारा खोलने का आदेश जारी किया है। इसलिए मौलाना आजाद मेडिकल कालेज (एमएएमसी), यूनिवर्सिटी कालेज ऑफ मेडिकल साइंस (यूसीएमएम) सहित दिल्ली सरकार के अस्पतालों से जुड़े सभी मेडिकल कालेज अब खुल जाएंगे और उनमें पठन पाठन का कार्य शुरू हो जाएगा। लेकिन मेडिकल के सभी छात्र एक साथ नहीं बुलाए जाएंगे। केंद्र व दिल्ली सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार की चारणबद्ध तरीके से छात्रों को बुलाना होगा।

विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि शुरुआत में एमबीबीएस प्रथम वर्ष के छात्र बुलाएं जाएंगे। कालेज खुलने के डेढ़ से दो माह में पाठ्यक्रम और प्रैक्टिकल पूरा करना होगा। इसके बाद एमबीबीएस अंतिम वर्ष के छात्र क्लास में आना शुरू करेंगे। सफल प्रशिक्षण के बाद एमबीबीएस अंतिम वर्ष के छात्र वार्षिक परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। परीक्षा में पास करने के बाद वे बतौर प्रशिक्षु सेवाएं दे सकेंगे।

इसके बाद एमबीबीएस द्वितीय वर्ष के छात्र व डेंटल के छात्र कालेज बुलाए जाएंगे। कॉलेज खोलने के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) व भारतीय दंत परिषद भी पिछले माह भी आदेश जारी कर चुके हैं। एम्स सहित केंद्र सरकार के अस्पतालों से जुड़े मेडिकल कालेज पहले से ही कक्षाएं संचालित कर रहे हैं। मौलाना आजाद मेडिकल कालेज के मेडिकल छात्र व रेजिडेंट डाक्टर भी जल्द कालेज व मेडिकल प्रशिक्षण शुरू करने की मांग कर रहे थे। क्योंकि वे अपने प्रशिक्षण को लेकर चिंतित थे।

बता दें कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण को देखते हुए मार्च 2020 को सरकार ने सभी स्कूलों व मेडिकल कॉलेजों को बंद करने का आदेश दिया था। तब से अभी तक राजधानी के स्कूल-मेडिकल कॉलेज बंद हैं। सरकार के इस आदेश के बाद अब दिल्ली सरकार के अस्पतालों से जुड़े मेडिकल कालेजों में पढ़ाई शुरू होगी।

बर्ड फ्लू का संक्रमण रोकने के कड़े एहतियाती कदम उठाएं : सिसोदिया

नई दिल्ली, (संवाददाता)। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में बर्ड फ्लू का संक्रमण रोकने के लिए कड़े एहतियाती कदम उठाने का निर्देश दिया है। आज सचिवालय में पशुपालन इकाई, विकास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने राज्य भर में सघन निगरानी का निर्देश दिया। उन्होंने बर्ड फ्लू के संबंध में मंडी वालों के लिए क्या करें, क्या न करें की गाइडलाइन तत्काल बनाकर कड़ाई से लागू कराने का निर्देश दिया। उन्होंने बड़े पैमाने पर नमूनों का संग्रह करके लगातार रिपोर्टिंग का भी निर्देश दिया। उल्लेखनीय है कि अब तक दिल्ली में बर्ड फ्लू का एक भी मामला सामने नहीं आया है। दिल्ली सरकार ने गत 28 अक्टूबर 2020 को ही राज्य के सभी डॉक्टर्स और संबंधित लोगों को अलर्ट जारी करके बर्ड फ्लू की निगरानी का निर्देश जारी कर दिया था। इसके बाद 4 जनवरी 2021 को भी सभी डॉक्टर्स को लगातार नमूना संग्रह करने तथा कड़ी निगरानी का दिशानिर्देश जारी किया गया। दिल्ली सरकार के पशुपालन इकाई, विकास विभाग के सभी 48 वेटनरी अस्पताल के डॉक्टर लगातार राज्य भर में बर्ड फ्लू की निगरानी कर रहे हैं। साथ ही, 11 रैपिड रिस्पॉन्स टीम बनाई गई है जो लगातार नमूनों का संग्रह कर रही है। अब तक 100 से ज्यादा नमूनों का संग्रह करके जालंधर भेजा गया है। सोमवार तक इनकी रिपोर्ट आने की संभावना है। इसके अलावा, विभिन्न जलाशयों में बतख की स्वास्थ्य जांच भी की जा रही है। बैठक में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अन्य राज्यों से आने वाली पोल्ट्री बर्ड पर भी कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया। उन्होंने प्रमुख बर्ड साइट्स खासकर पोल्ट्री मार्किट, जलाशय, जू इत्यादि में बर्ड्स पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया।

एमसीडी में भाजपा पूरी तरह से फेल : सौरभ भारद्वाज

नई दिल्ली, (संवाददाता)। आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नगर निगमों को चलाने में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। लिहाजा, भाजपा तत्काल एमसीडी को बर्खास्त करे और दोबारा चुनाव कराया जाए। एमसीडी में भाजपा के नेतृत्व का पदार्फाश हो गया है। भाजपा नेताओं ने हजारों करोड़ रुपए का घोटाला कर दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। दिल्ली सरकार से पूरा पैसा लेने, प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने और कई नए टैक्स लगाने के बावजूद एमसीडी कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। उन्होंने कहा कि एमसीडी चुनाव-2017 के दौरान भाजपा के तत्कालीन दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष व सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली वालों से पैसे की कमी नहीं होने देने और केंद्र से पैसा लेकर एमसीडी चलाने का वादा किया था। उन्होंने झूठे वादे कर दिल्ली के लोगों को गुमराह किया और केंद्र से एक रुपए नहीं लेकर आए। उन्हें दिल्ली का सांसद बने रहने का कोई अधिकार नहीं है और नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए।

आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और विधायक सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली नगर निगम में हुए घोटालों को लेकर पार्टी मुख्यालय में प्रेस कांफ्रेंस की।

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली नगर निगम के वे कर्मचारी, जो समाज का सबसे गरीब और मेहनती तबका होता है और जिन्होंने कोरोना महामारी में दिल्ली में जी-जान से काम किया। चाहे वह सफाई कर्मचारी हों, डॉक्टर हों, नर्स या अन्य स्वास्थ्य कर्मी हों या फिर नगर निगम के अन्य कर्मचारी हों। कोरोना काल में अहम योगदान निभाने वाले इन कर्मचारियों को जब कई महीनों तक वेतन नहीं दिया गया, तो वे दोबारा हड़ताल पर चले गए हैं। आज भी लगभग वही स्थिति बनी हुई है, जो अब से 5 साल पहले थी। भाजपा चाहती है कि दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी बार-बार हड़ताल पर जाएं, उनका वेतन रोका जाए, दिल्ली के अंदर एक बार फिर झाडू लगना और कूड़ा उठना बंद हो जाए। जगह जगह कूड़े के ढेर लग जाएं, मुख्य रास्तों पर कूड़ा डाला जाए और दिल्ली को पूरी दुनिया में बदनाम किया जाए।

उन्होंने कहा कि जो स्थिति आज से 5 साल पहले 2015 में थी, वही स्थिति आज 2021 में भी बनी हुई है। दिल्ली के लोगों का सिर्फ एक ही सवाल है कि अगर भाजपा से दिल्ली नगर निगम नहीं संभल रहा, अगर इनसे पैसों का रखरखाव नहीं होता, अगर यह दिल्ली के वित्तीय प्रबंधन को संभालने में सक्षम नहीं हैं, तो वे दिल्ली नगर निगम क्यों चला रहे हैं इन्हें नगर निगम से हट जाना चाहिए, क्योंकि यह स्थिति चुनाव जीतने के बाद एक बार फिर से उत्पन्न होगी। चुनाव जीतने के बाद यह लोग फिर से कहेंगे कि हमारे पास पैसा नहीं है। एक बार फिर से दिल्ली कूड़ा-कूड़ा हो जाएगी। एक बार फिर से नगर निगम के कर्मचारी अपने वेतन को लेकर हड़ताल और धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर कोई भी व्यक्ति किसी काम के लिए इनके पास जाता है, तो यह एक ही बात कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास बजट नहीं है।

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जब 2017 में एमसीडी चुनाव हुआ था, तो दिल्ली की जनता ने इनसे सवाल किया था कि जब पिछले पांच सालों में आपसे नगर निगम नहीं संभला, हर दूसरे दिन आप कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम वेतन नहीं दे पा रहे हैं, हम पेंशन नहीं दे पा रहे हैं, तो इस बार आप ऐसा क्या कर देंगे जिससे दिल्ली ही हालत अच्छी हो जाएगी और दिल्ली स्वच्छ बन जाएगी। तब भाजपा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी ने दिल्ली की जनता से वादा किया था कि हम दिल्ली नगर निगम के अंदर अब पैसों की कोई कमी नहीं होने देंगे। हम सीधे केंद्र सरकार से पैसा लेकर आएंगे। हम अच्छी तरह से दिल्ली नगर निगम को चलाएंगे। इस झूठे वादे का उन्होंने खूब प्रचार किया। 2017 में जनता ने एक बार फिर भाजपा पर विश्वास किया और नगर निगम में भाजपा की सरकार बनी।

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आज जब हम 2021 में हैं, आज नगर निगम में इनकी सरकार बने हुए 4 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी स्तिथि जस की तस है।

दिल्ली में पेट्रोल–डीजल के दाम बढ़े

नई दिल्ली, (संवाददाता)। सब्जी के दामों में हल्के इजाफे के बीच पेट्रोल-डीजल के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 9 महीने के दौरान दिल्ली में पेट्रोल के दामों में 14 रुपये से भी अधिक की बढ़ोतरी हुई है। लॉकडाउन में एक बारगी सब कुछ थम गया और अब अनलॉक के दौर में जब अर्थव्यवथा पटरी पर आने लगी है, तो इस बीच पेट्रोल ने जमकर फरार्टे भरे हैं। इस कड़ी में बुधवार को पेट्रोल के दामों ने रिकॉर्ड 83.97 रुपये प्रति लीटर दाम को भी छू लिया है, जबकि लाकडॉउन से अब तक इसने 14.34 रुपये की छलांग लगाई है। 24 मार्च को पहली बार लॉकडाउन लगा था। उसके एक दिन पहले 23 मार्च को दिल्ली में पेट्रोल के दाम 69.63 रुपये था। जून में यह 71.30 रुपये प्रति लीटर पर पहुंचा तो अक्टूबर 81.12 रुपये तो दिसंबर में यह 82.49 रुपये तक पहुंच गया।

गुरु रविदास मंदिर की तर्ज पर चांदनी चौक में हो प्राचीन हनुमान मंदिर का पुनर्निर्माण- विहिप

नई दिल्ली । विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) ने गुरु रविदास मंदिर की तर्ज पर चांदनी चौक में प्राचीन हनुमान मंदिर के पुनर्निर्माण की मांग की है। इसके लिए उसने दिल्ली सरकार से हाई कोर्ट से स्वीकृति लेने की मांग की है। चांदनी चौक में प्राचीन हनुमान मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए विहिप की उच्च स्तरीय बैठक बृहस्पतिवार को प्रान्त अध्यक्ष कपिल खन्ना के नेतृत्व में झंडेवालान देवी मंदिर स्थित संगठन के कार्यालय में आयोजित हुई। जिसमे पुनः मंदिर निर्माण के लिए निर्णय लिया गया कि विहिप आज ही उप राज्यपाल अनिल बैजल को पत्र लिखकर निवेदन करेगी कि आप गुरु रविदास मंदिर की तर्ज पर चांदनी चौक में प्राचीन हनुमान मंदिर निर्माण के लिए दिल्ली सरकार को आदेश करें। इसके लिए दिल्ली सरकार उच्च न्यायालय में आवेदन करें जिससे प्राचीन हनुमान मंदिर पुनर्निर्माण का कार्य उसी स्थान पर पुनः स्थापित हो सके। प्रान्त प्रचार प्रसार प्रमुख महेंद्र रावत ने बताया कि जब तक मंदिर निर्माण नहीं होता तब तक विहिप मंदिर पुर्ननिर्माण आंदोलन जारी रखेगा और आंदोलन की योजना भी तैयार की जा रही है। अगर मंदिर का अतिशीघ्र उस स्थान पर पुनर्निर्माण नही किया गया तो विहिप पूरे प्रदेश में प्रचण्ड प्रदर्शन को मजबूर होगा और इसकी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की होगी। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने हनुमान मंदिर को पुन- स्थापित करने मांग की है। बुधवार को चांदनी चौक में प्राचीन हनुमान मंदिर को तोड़े जाने के विरोध में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फव्वारा चौक के पासप्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता कटरा धुलिया के सामने स्थित मंदिर स्थल तक जाने की कोशिश में थे, लेकिन पुलिस व अर्धसैनिक बल के जवानों की भारी मौजूदगी और बैरिकेडिंग के कारण वे आगे नहीं बढ़ सके। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे दिल्ली कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष मुदित अग्रवाल ने आप और भाजपा पर मिलीभगत का आरोप लगाया।

नई दिल्ली में गुरुवार को विधायक आतिशी ने ऑनलाइन शिक्षा के लिए कालकाजी में दिल्ली सरकार के 9 वीं से 12 वीं कक्षा के छात्रों को स्मार्टफोन वितरित किए।

दिल्ली में जल्द खोले जा सकते हैं स्कूल, 17 जनवरी के बाद हो सकता एलान

नई दिल्ली । केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं की तिथि घोषित होने के बाद दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार ने भी स्कूलों जल्द ही खोलने के संकेत दे दिए हैं। इस बाबत उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का कहना है कि वैक्सीनेशन की तैयारियों की तरह ही हमें स्कूल खोलने की योजना भी बनानी होगी।

उन्होंने कहा कि कोविड-19 और स्कूल बंद होने के कारण बच्चों की शिक्षा बुरी तरह से प्रभावित हुई है। बुधवार को डिजिटल पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि इन्हीं सब पहलुओं पर विचार करने के लिए दिल्ली सरकार स्कूली शिक्षा पर एक अंतरराष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। 11 से 17 जनवरी तक आयोजित होने वाले इस सम्मेलन के लिए उन्होंने वेबसाइट भी लॉन्च की गई। इसमें भारत तथा छह अन्य देशों के 22 शिक्षा विशेषज्ञ स्कूली शिक्षा के विभिन्न विषयों पर विचार रखेंगे। इनमें भारत, फिनलैंड, इंग्लैंड, जर्मनी, सिंगापुर, नीदरलैंड और कनाडा के विशेषज्ञ शामिल होंगे। माना जा रहा है कि सहमति बनी तो इसका एलान भी किया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि इसमें बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप द्वारा विगत पांच साल में दिल्ली के शिक्षा सुधारों पर स्वतंत्र अध्ययन की रिपोर्ट भी जारी की जाएगी। इसके बाद लूसी क्रेहान का की-नोट लेक्चर होगा। उन्होंने पांच देशों की शिक्षा प्रणाली का गहन अध्ययन करके 'क्लेवर लैंड्स' नामक चर्चित पुस्तक लिखी है।

12 से 16 जनवरी 2021 तक प्रतिदिन दो घंटे का ऑनलाइन पैनल डिस्कशन होगा। इसमें शैक्षणिक पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र, शिक्षा प्रशासन के साथ ही शिक्षा की बुनियाद, शिक्षकों के व्यावसायिक विकास, स्कूल प्रबंधन और शिक्षा संबंधी अन्य विषयों पर चर्चा होगी। साथ ही नई शिक्षा नीति ने स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में कई सुधारों की सिफारिश की है। इसे ध्यान में रखते हुए हमें कोविड-19 के बाद के दौर में स्कूली शिक्षा में जरूरी सुधार पर गहन विचार करना होगा।

एनसीआर के कई इलाकों में किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च, आम जन की बढ़ी परेशानी

नई दिल्ली । तीनों केंद्रीय कानूनों के विरोध में चल रहा किसानों का प्रदर्शन बृहस्पतिवार को 43वें दिन में प्रवेश कर गया है। इसके चलते रोजाना लाखों लोगों को आवागमन के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच कृषि कानून के विरोध में दिल्ली-हरियाणा और उत्तर प्रदेश की कई सीमाओं पर किसान धरने पर बैठे हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत आदि शहरों में किसानों ने बृहस्पतिवार को ट्रैक्टर मार्च निकाला। इसके चलते वाहन चालकों का बुरा हाल है। वहीं, किसानों का कहना है कि ये तो महज 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाले ट्रैक्टर मार्च का अभ्यास भर है। किसानों ने केंद्र सरकार को चेताया है कि तीनों कानूनों को रद करने की मांगें नहीं मानीं गईं तो प्रदर्शनकारी 26 जनवरी को दिल्ली में ऐसे ही ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। वहीं, सुरक्षा को देखते हुए दिल्ली से सटे शहरों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कृषि कानून वापस कराने की मांग को लेकर नोएडा के सेक्टर-14 स्थित चिल्ला बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों ने बृहस्पतिवार को पेरिफेरल एक्सप्रेस वे एवं जिला मुख्यालय पर ट्रैक्टर रैली निकाली। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले ट्रैक्टर रैली नोएडा के महामाया फ्लाईओवर के नीचे एकत्र हुए। दोपहर में रैली पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे की तरफ कूच की। वहीं पुलिस प्रशासन ने पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर दोपहर 12 बजे से शाम पांच बजे तक डायवर्जन के लिए एडवाइजरी जारी की है। ऐसे में लोगों ने भी समझदारी दिखाते हुए इन रास्तों से यात्रा करने से परहेज किया। यूपी गेट से ट्रैक्टर यात्रा निकाल रहे भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) गुट के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि हम तो 2024 तक के लिए तैयार हैं। तीनों केंद्रीय कृषि कानून रद करवाकर ही वापस लौटेंगे।

दिल्ली में ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध बढ़ाया जाए, सीएम केजरीवाल ने की केंद्र से मांग

नई दिल्ली । दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ब्रिटेन से आने वाली उड़ानें पर 31 जनवरी तक प्रतिबंध को बढ़ाने की मांग की है। ब्रिटेन में कोरोना संक्रमण के गंभीर मामलों को देखते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने केंद्र से आग्रह किया है कि ब्रिटेन (यूके) से आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध बढ़ा दिया जाए। ताकि दिल्ली में कोरोना के नए स्ट्रेन (स्वरुप) से लोगों को बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन के मामले बढ़ रहे हैं लेकिन केंद्र ने वहां की उड़ानों पर प्रतिबंध हटा दिया है और ब्रिटेन की उड़ानें फिर शुरू करने का फैसला किया है।

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि बड़ी मुश्किल से लोगों ने कोरोना की स्थिति को नियंत्रण में लाया है। ब्रिटेन में कोरोना संक्रमण की स्थिति गंभीर है। अब, प्रतिबंध क्यों हटाएं और हमारे लोगों को जोखिम में डालें?।

दिल्ली में धीरे-धीरे कोरोना के नए स्वरूप (स्ट्रेन) से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। बुधवार को भी लोकनायक अस्पताल में भर्ती एक मरीज में नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई। इससे अब राजधानी में स्ट्रेन से संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 9 हो गई है। ये सभी मरीज लोकनायक अस्पताल के विशेष कोरोना वार्ड में भर्ती हैं। वहीं, दिल्ली सरकार के घर-घर जांच अभियान में श्रीलंका से लौटा एक और व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया है। इससे लोकनायक अस्पताल के विशेष वार्ड में भर्ती कोरोना संक्रमितों की संख्या 52 हो गई है।

ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों पर नजर

ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों को लेकर आइजीआइ एयरपोर्ट सतर्क है। एक अधिकारी ने बताया कि मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के मुताबिक सभी यात्रियों को गत 14 दिनों का यात्र इतिहास बताने के अलावा उन्हें स्व-घोषणा पत्र भरना होगा। वहीं, उड़ान के प्रस्थान से 72 घंटे पहले कोरोना जांच की रिपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट के पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। दिल्ली आने के बाद ब्रिटेन से आए यात्रियों का दोबारा से आरटी-पीसीआर परीक्षण कराना होगा।

दिल्ली नगर निगम के 1 लाख से अधिक कर्मचारी हड़ताल पर, कहा- नहीं लगाएंगे लोगों को कोरोना का टीका

नई दिल्ली । बकाया वेतन को लेकर कोरोना संकट के बीच राजधानी के तीनों निगमों (उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी) में बृहस्पतिवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू होगी। चिंताजनक बात यह है कि कोरोना के टीकाकरण अभियान में कार्य करने वाले स्वास्थ्यकर्मी भी हड़ताल पर रहेंगे। सफाई कर्मचारियों के साथ निगम के शिक्षक आनलाइन कक्षाएं भी नहीं लेंगे। वहीं, इंजीनियर के साथ निगम कार्यालयों में कार्य करने वाले कर्मी भी हड़ताल पर रहेंगे। निगम के महापौर और अधिकारियों के साथ कई चरण की बैठक में कोई ठोस आश्वासन न मिलने पर निगम कर्मियों ने हड़ताल का एलान किया है। इससे पूर्व शिक्षकों ने बुधवार को सिविक सेंटर के बाहर प्रदर्शन कर वेतन जारी करने की मांग की।

तीनों निगम में विभिन्न यूनियन के संयुक्त समूह कन्फेडरेशन आफ एमसीडी एम्प्लाइज यूनियंस के संयोजक एपी खान ने बताया कि हड़ताल की हमने पहले ही तीनों निगमों और मुख्यमंत्री कार्यालय में नोटिस दे दिया था। इसके बाद भी मुद्दा हल नहीं हुआ है। निगम के कर्मी पांच-पांच माह से बिना वेतन के कार्य कर रहे हैं। जब वेतन मिलना ही नहीं हैं तो फिर काम क्यों कराया जा रहा है।

खान ने बताया कि सभी कर्मचारी बृहस्पतिवार सुबह सिविल लाइंस जोन पर एकत्रित होकर राज निवास पर धरना देंगे। इसके बाद कोई भी कर्मी अपने-अपने दफ्तरों में कार्य नहीं करेगा। उन्होंने बताया कि तीनों निगम की विभिन्न विभागों की 21 से ज्यादा यूनियन हड़ताल के समर्थन में हैं। बृहस्पतिवार से निगम के दफ्तरों में कोई कार्य नहीं होगा।

नई दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर पर नए खेत कानूनों के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान किसानों ने एक ट्रैक्टर रैली निकालते हुए।

संपादकीय

बढ़ती ताकत से उभरता भारत

इसमें कोई संदेह नहीं कि पिछले एक दशक में भारत की अर्थव्यवस्था, विज्ञान-तकनीक, अंतरराष्ट्रीय समुदाय को प्रभावित करने की उसकी क्षमता और सुरक्षा व क्षेत्रीय अखंडता को सुनिश्चित करने की उसकी ताकत लगातार बढ़ी है। देश की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर बेशक 2019 में 5.02 फीसदी हो गई, मगर आज भी जीडीपी का करीब 10 फीसदी हिस्सा हम सामाजिक-आर्थिक पैकेज के तौर पर जरूरतमंदों के ऊपर खर्च करते हैं। भारत नियमित रूप से अंतरिक्ष अभियानों को अंजाम दे रहा है, और दक्षेस व तमाम देशों के लिए न सिर्फ उपग्रह लॉन्च कर रहा है, बल्कि उन्हें अपनी अंतरिक्ष सुविधाओं से फायदा भी पहुंचा रहा है। इससे हमारी आमदनी भी बढ़ी है। तकनीक और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तो 'ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स' के शीर्ष 50 देशों में हम पहली बार शामिल हुए हैं।

इन सबमें रक्षा क्षेत्र की तरक्की का जिक्र खास है। रक्षा खर्च के मामले में तीसरा बड़ा देश और सशस्त्र बल के मामले में चौथा बड़ा मुल्क भारत एक प्रमुख क्षेत्रीय ताकत, परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र, एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति और एक संभावित महाशक्ति है। 14 लाख से अधिक स्वैच्छिक और सक्रिय सैनिकों की तादाद के साथ यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सैन्य बल भी है। ग्लोबल फायरपावर रिपोर्ट, 2020 के मुताबिक, भारत के पास विश्व की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है। कारगिल युद्ध में सेना की कमान संभालने के दौरान मुझे यह एहसास हुआ था कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे सैनिकों और उनके नेतृत्व की बहादुरी, समर्पण और देशभक्ति है। परमाणु ताकत से संपन्न हमारा सशस्त्र बल लगातार आधुनिक बन रहा है।

इस साल हमने देखा है कि किस तरह रणनीतिक मामलों में हमारी राजनीतिक इच्छाशक्ति बदली है, ताकि विरोधी ताकतों से कहीं मजबूती से मुकाबला किया जा सके। सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट हवाई अभियान और जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद-विरोधी अभियानों में उल्लेखनीय सफलता इसका स्पष्ट प्रमाण है। भारत-चीन सीमा पर डोका ला और अब पूर्वी लद्दाख में भी हम इस रणनीतिक बदलाव को महसूस कर रहे हैं। इतना ही नहीं, भारत ने ऐसे अभियान की शुरुआत की है, ताकि रक्षा उपकरणों को देश में ही बनाया जा सके और इनके आयात पर हमारी निर्भरता कम हो। उल्लेखनीय है, रक्षा उपकरणों के सबसे बड़े आयातक देशों में एक भारत भी है।

भारत क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश है। भू-रणनीतिक रूप से यह दक्षिण एशिया और हिंद महासागर के आसपास के इलाकों में प्रभावी भूमिका में है। इसकी ताकत यहां की संसद, न्यायपालिका, चुनाव आयोग, मीडिया और सशस्त्र बल हैं। प्राचीन संस्कृति, पर्याप्त मात्रा में प्रतिभाशाली मानव संसाधन और विशाल प्राकृतिक संसाधन भी इसे खासा मजबूत बनाते हैं। ऐसे में, स्वाभाविक रूप से कुछ देशों की नजरों में हम चढ़े हुए हैं। चीन और पाकिस्तान ऐसे ही देश हैं, जो बार-बार हमारी राहों में मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश करते रहते हैं। साल 2019 को तो चीनी आक्रामकता और भारत की दृढ़ता के लिए विशेष रूप से याद किया जाएगा। केवल एक वर्ष नहीं, बल्कि गुजर रहे पूरे दशक में ये दोनों राष्ट्र हमारी चिंता के कारण रहे हैं। अब जब यह साल और दशक बदल रहा है, तब देश के आम लोगों के मन में यही सवाल है, क्या अगले दशक में भी हमें इनसे समान चुनौतियां मिलती रहेंगी?

मेरा मानना है कि अगले साल भी दोनों राष्ट्रों के साथ हमारी लंबी और विवादित सीमा, दोनों देशों की नीतियां चुनौती बनी रहेंगी। इसका अर्थ है, पाकिस्तान की जेहादी आतंकवादी नीतियां और चीन द्वारा भारतीय सीमा पर व हिंद महासागर में अपनाई जा रही विस्तारवादी नीतियां हमारे लिए मुश्किलें पेश करती रहेंगी। हालांकि, आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर भी हमें पूरा ध्यान देना होगा। देश के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग मत के राजनीतिक, अलगाववादी और राष्ट्र-विरोधी तत्व बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं।

जाहिर है, हमें सुरक्षा के मोर्चे पर खुद को और अधिक मजबूत बनाना होगा। अपनी रक्षा योजना में भी सुधार करना होगा। रक्षा क्षमताओं में बेहतरी के लिए हमें दीर्घकालिक प्रयास भी लगातार करने होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि जब हमारे सामने मुश्किलें आएं, तभी हम उनके समाधान की कोशिश करें। हमारा रक्षा आवंटन बहुत कम प्रतीत होता है, खासकर भविष्य की चुनौतियों के मद्देनजर। लिहाजा हमें अपनी रक्षा जरूरतों पर कुल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का तीन फीसदी हिस्सा खर्च करना चाहिए। यह देखना सुखद है कि सरकार ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ाए हैं, मगर इसे और गति देने की आवश्यकता है।

वैसे, इस दौर में कुछ सबक हम देशवासियों को भी सीखना चाहिए। राष्ट्र के साथ-साथ निजी विकास को लेकर भी काफी काम किए जाने की जरूरत है। हमें जो सीखने की जरूरत है, वह है अनुशासन, सकारात्मक सोच, कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ काम करने की इच्छाशक्ति। इसमें देश के नौजवानों से ढेर सारी उम्मीदें हैं। उन्हें एकजुटता दिखानी चाहिए और दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराना चाहिए।

कुछ प्रयास देशभक्ति बढ़ाने के भी होने चाहिए। 'वोट बैंक की राजनीति' हमारे समाज व मुल्क को न जाने किन-किन रूपों में बांटती रही है। हमारे सियासी रणनीतिकार 'सोशल इंजीनियरिंग' की दुहाई देते हैं। इसके बरअक्स, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय विकास पर कम ध्यान दिया जाता है। इसमें संतुलन आवश्यक है। हमारे बच्चों और नौजवानों में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ानी होगी और उन्हें राष्ट्र निर्माण के महत्व से परिचय करवाना होगा। एनसीईआरटी की किताबें व छात्र-छात्राओं के लिए राष्ट्रीय एकता कार्यक्रम हमारी स्कूली और कॉलेज शिक्षा को इस दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। एनसीसी और इसकी जैसी अन्य इकाइयां इसमें बहुत उपयोगी भूमिका निभा सकती हैं। इनको और प्रोत्साहित करने की जरूरत है। आगामी दशक में देश को सशक्त बनाने के लिए हमें राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीकों, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय उपलब्धियों को अधिक महत्व देना चाहिए। धार्मिक व क्षेत्रीय आयोजनों की तुलना में राष्ट्रीय कार्यक्रमों को अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए।

प्रवीण कुमार सिंह

कई चुनौतियों से सफलतापूर्वक निपटने वाली भाजपा के लिए अगला साल साबित हो सकता है और बेहतर

> बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में भगदड़ जैसी स्थिति है। उसके वरिष्ठ नेता जिस तरह भाजपा का दामन थाम रहे हैं उससे बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के पक्ष में माहौल बनता दिख रहा है। असम में भी भाजपा की राह आसान दिखती है। अरुणाचल में भी उसके लिए चुनौती नदारद है। हालांकि केरल में लंबे समय से पैठ जमाने में जुटी भाजपा को हालिया निकाय चुनाव से कुछ मायूसी मिली है, मगर पड़ोसी तमिलनाडु से उसकी उम्मीदें कायम हैं जहां वह जयललिता और करुणानिधि द्वारा रिक्त किए गए राजनीतिक निर्वात की पूर्ति के लिए प्रयासरत है।

जब पूरी दुनिया कोरोना से पीड़ित हो तो उसमें किसी देश और सरकार की सफलता इसी पैमाने से ही आंकी जाएगी कि उसने अपने देश को कैसे इस वायरस से महफूज रखा। कोरोना आपदा ने जहां दुनिया के कई विकसित देशों के साधन संपन्न स्वास्थ्य ढांचे की कलई खोल दी वहीं उनसे कहीं बड़ी आबादी और कम संसाधनों वाले भारत का प्रदर्शन बहुत बेहतर रहा। कोरोना का सामना करने में मोदी सरकार के सराहनीय प्रदर्शन के बावजूद हमारे विपक्षी दल उस पर हमलावर ही रहे। यह अफसोस की बात है कि जिस मसले पर एकजुटता दिखानी चाहिए थी उस पर भी विपक्ष राजनीति करने से बाज नहीं आया।

दरअसल पिछले आम चुनाव में जनता द्वारा लगातार दूसरी बार खारिज कर दिए जाने के बाद से तिलमिलाए विपक्षी दलों ने उसके तुरंत बाद से ही सरकार के निर्णायक राजनीतिक कदमों का विरोध शुरू कर दिया। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद ही मोदी सरकार अपने वादों पर अमल में जुट गई थी। उसने तीन तलाक और अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के जरिये राजनीतिक और सामाजिक जीवन को नई दिशा देना आरंभ ही किया था कि मोदी विरोधियों ने सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार शुरू कर दिया। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के कुछ महीनों बाद ही सीएए के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में उसे एक नए स्वरूप में चुनौती मिली। उसमें लोकतांत्रिक अधिकारों की आड़ में जनता के अधिकार और संसद के प्राधिकार को बंधक बनाया जा रहा था। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में उसे गलत करार दिया। अब इस साल के उतार पर वही दोहराने का प्रयास हो रहा है। स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निरंतर

बढ़ती लोकप्रियता को चुनौती देने के विपक्षी दलों के ऐसे प्रयास जारी रहेंगे। शाहीन बाग प्रदर्शन एक बड़ी चुनौती थी जिसका तंबू कोरोना की दस्तक के बाद ही उखड़ा। भाजपा ने शाहीन बाग को दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनाने का प्रयास किया, पर यह दांव चला नहीं। भाजपा दिल्ली चुनाव की हार से उबरी भी नहीं थी कि दिल्ली में भड़के दंगों ने मोदी सरकार पर हमले का एक नया मुद्दा दे दिया। यह बात अलग है कि गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में दंगों पर न सिर्फ रिकॉर्ड समय में काबू पाया गया, बल्कि उनकी साजिश का भी जल्द ही पर्दाफाश हुआ। परिणामस्वरूप दंगों के दोषी सलाखों के पीछे पहुंचाए गए। इससे भाजपा और मोदी सरकार दंगों के दाग से सही सलामत बचने में सफल रहे। उधर शाहीन बाग के सहारे भाजपा को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश में जुटी कांग्रेस मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बचाने में ही विफल रही। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत से राज्य में भाजपा न सिर्फ सरकार बनाने में सफल रही, बल्कि उपचुनाव में पर्याप्त संख्या में अपने प्रत्याशी जिताकर पूरे कार्यकाल की गारंटी भी सुनिश्चित कर ली। गुजरात और उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में तो भाजपा ने विपक्ष का सूपड़ा ही साफ कर दिया। वहीं तेलंगाना में मुख्यमंत्री केसीआर की प्रतिष्ठा से जुड़ी सीट जीतकर भाजपा ने राज्य में प्रमुख विपक्षी दल के रूप में अपनी दावेदारी पेश की। इस दावेदारी को ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में और मजबूत आधार मिला है।

राजनीतिक अश्वमेध के भाजपाई घोड़े को रोकने के लिए विपक्ष ने बिहार में 15 साल पुरानी नीतीश कुमार सरकार को निशाना बनाया। कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण प्रवासी मजदूरों की परेशानियों के साथ-साथ लालू यादव के जंगलराज के बाद पली-बढ़ी पीढ़ी को रोजगार का सब्जबाग दिखाकर राजग और खासकर नीतीश कुमार के खिलाफ जबरदस्त माहौल बनाया गया। मुस्लिम-यादव गठजोड़ के साथ अन्य जातियों के नाराज युवाओं को जोड़कर इस फॉर्मूले को अजेय साबित करने की कोशिश हुई। हालांकि जेपी नड्डा की अध्यक्षता में पहली बार विधानसभा चुनाव में उतरी भाजपा ने चुनावी पंडितों और एक्जिट पोल के आकलनों को धता बताते हुए न केवल सत्ता बचाई, बल्कि कम सीटों पर लड़कर भी राजद के बराबर सीटें लाकर साबित किया कि बिहार की जनता को भाजपा की विकास नीतियों में पूरा भरोसा है और वह अभी तक लालू यादव के जंगलराज को पूरी तरह नहीं भूली।

इस साल भाजपा को राज्यसभा में अपना संख्याबल बढ़ाने में भी सफलता मिली। राज्यसभा में अल्पमत के कारण ही सरकार सुधारों के एजेंडे पर अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ पा रही थी। इसके चलते उसे कई विधेयक मनी बिल के रूप में पारित कराने पड़े जिसकी आलोचना भी हुई। कई राज्यों में मिली मजबूती से राज्यसभा में दमदार हुई भाजपा को अब अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। वर्ष 2020 में भाजपा ने विपक्षी दलों को राजनीति का एक नया पाठ भी पढ़ाया। वह यह कि राजनीति के शिखर की सीढ़ी निचले पायदान से शुरू होती है। हैदराबाद का स्थानीय निकाय चुनाव इसकी मिसाल बना जहां पार्टी के तमाम दिग्गज नेता सक्रिय रहे।

इस वर्ष कई चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने के बाद अंत में भाजपा को कुछ किसान संगठनों की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। कुछ लोग इसकी तुलना शाहीन बाग से कर रहे हैं। यह सही नहीं, क्योंकि शाहीन बाग दिशाहीन आंदोलन था जबकि किसान आंदोलन को नेतृत्व प्राप्त है जो लगातार सरकार के साथ वार्ता में भी लगा है। साथ ही यह मूल रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ किसान संगठनों की ही मुहिम है। शेष भारत के किसान न केवल इस आंदोलन से दूर हैं, बल्कि वे कृषि कानूनों का समर्थन भी कर रहे हैं। सरकार भी सुधारों पर दृढ़ रहने के साथ ही उनमें संशोधन के लिए तैयार होकर लचीलापन दिखा रही है। इससे देर-सबेर गतिरोध का हल निकल ही जाएगा।

अगला साल भाजपा के लिए और बेहतर हो सकता है। बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में भगदड़ जैसी स्थिति है। उसके वरिष्ठ नेता जिस तरह भाजपा का दामन थाम रहे हैं उससे बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के पक्ष में माहौल बनता दिख रहा है। असम में भी भाजपा की राह आसान दिखती है। अरुणाचल में भी उसके लिए चुनौती नदारद है। हालांकि केरल में लंबे समय से पैठ जमाने में जुटी भाजपा को हालिया निकाय चुनाव से कुछ मायूसी मिली है, मगर पड़ोसी तमिलनाडु से उसकी उम्मीदें कायम हैं जहां वह जयललिता और करुणानिधि द्वारा रिक्त किए गए राजनीतिक निर्वात की पूर्ति के लिए प्रयासरत है।

विज्ञान और अर्थशास्त्र की कसौटी पर कोरोना वैक्सीन

बीत रहे इस वर्ष के प्रारंभ से ही एक भयानक महामारी से जूझते हुए विश्व में जहां इसका कोई इलाज नहीं सूझ पा रहा, वहीं कोरोना वैक्सीन को ही इस हेतु एकमात्र स्थायी समाधान माना जा रहा है। दरअसल एक प्रभावी वैक्सीन बीमारी से मुकाबला करने हेतु शरीर में एंटी बॉडी तत्वों के विकास में सहायता करती है, ताकि मनुष्यों को उस बीमारी से बचाया जा सके। यह महामारी चिकित्साशास्त्र के लिए भी एक चुनौती है। ऐसी बीमारी, जिसका संक्रमण अभूतपूर्व तेजी से फैलता है, उसके लिए वैक्सीन का निर्माण भी अत्यंत चुनौतीपूर्ण है। इस वैक्सीन के विकास के लगभग 200 से भी अधिक प्रयास दुनिया में चल रहे हैं। बड़ी संख्या में अब वैक्सीन विभिन्न देशों में स्वीकृति के लिए भी लाई जा रही है। इस बीच ब्रिटेन ने फाईजर कंपनी की वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की अनुमति भी प्रदान कर दी है। भारत में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की वैक्सीन कोवीशील्ड की निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट और भारतीय कंपनी भारत बायोटेक द्वारा निर्मित वैक्सीन ने भी आपातकालीन उपयोग की अनुमति मांगी है। एक ओर इससे लोगों में इस महामारी से निजात पाने में एक आशा की किरण तो जगी है, लेकिन साथ ही कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, जिनका समाधान प्राप्त करना भी बहुत जरूरी है। इस संबंध में पहला सवाल इस वैक्सीन की कीमत को लेकर है। करीब 135 करोड़ जनसंख्या के साथ भारत को अपनी संपूर्ण आबादी को यह वैक्सीन उपलब्ध करवाना एक बड़ी चुनौती है। हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट के प्रमुख ने एक ट्वीट कर सरकार द्वारा वैक्सीन हेतु बजट के बारे में भी चुनौती दी थी। यदि एक व्यक्ति को वैक्सीन देने की लागत एक हजार रुपये भी हो तो सभी देशवासियों को वैक्सीन देने की लागत एक लाख 35 हजार करोड़ रुपये होगी। वहीं वैक्सीन की कीमत 100 रुपये भी बढ़ने पर लागत में 13,500 करोड़ रुपये का अंतर पड़ेगा। हालांकि वैक्सीन आने की, उसके प्रभावी होने और दुष्प्रभावों के बारे में खबरें तो आ रही हैं, लेकिन अभी भी उसकी लागत को लेकर स्पष्टता की कमी है। फाइजर की वैक्सीन की कीमत 37 डॉलर प्रति डोज है, जिसका मतलब है भारत को 22.8 अरब डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। हालांकि फाइजर ने कहा है कि भारत में वे लागत को कम रखेंगे। दूसरी तरफ रूस की स्पुतनिक फाइव की लागत 10 डॉलर और भारत बायोटेक एवं केडिला वैक्सीन की लागत तीन से छह डॉलर के बीच रहने वाली है।

हालांकि वैक्सीन विकसित करने के अनेक प्रयास दुनिया भर में चल रहे हैं, लेकिन वैक्सीन के व्यावसायिक उत्पादन की क्षमता की दृष्टि से भारत का कोई सानी नहीं है। रूस की स्पुतनिक फाइव वैक्सीन हो या ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन, सभी भारत में ही उसके व्यावसायिक उत्पादन के लिए संपर्क साध रहे हैं। फाइजर कंपनी ने दावा किया है कि उनकी वैक्सीन औसतन 95 प्रतिशत प्रभावी है। विभिन्न आयुवर्गों में इसकी प्रभावी क्षमता 90 प्रतिशत से 100 प्रतिशत है। इसके दुष्प्रभावों के बारे में कंपनी का कहना है कि ये दुष्प्रभाव फ्लू की अन्य वैक्सीन के मुकाबले एक समान है। उधर भारत बायोटेक ने भी अपनी वैक्सीन के प्रभावी और सुरक्षित होने का दावा पेश किया है। रूस की वैक्सीन स्पुतनिक फाइव को विकसित करने वाले केंद्र का दावा है कि उनकी वैक्सीन 91 प्रतिशत प्रभावी होने के साथ कोविड संक्रमण से दो वर्ष तक सुरक्षा प्रदान करती है, जबकि फाइजर की वैक्सीन चार-पांच माह ही सुरक्षा प्रदान करेगी।

गौरतलब है कि रूस की वैक्सीन को बहुत पहले ही रूस में व्यावसायिक उपयोग की अनुमति दे दी गई थी। भारत समेत अन्य देशों में भी उसके ट्रायल अलग-अलग स्तर पर चल रहे हैं। वैक्सीन के उपयोग की अनुमति मिलते ही बड़ी चुनौती उसके वितरण की होगी। फाइजर की वैक्सीन हेतु माइनस 75 डिग्री का तापमान आवश्यक होगा। इसके लिए विशेष मशीनों की जरूरत होगी। हालांकि कंपनी का कहना है कि इस हेतु उसकी वैश्विक तैयारी है। लेकिन भारत जैसे देश जहां कोल्ड चेन के इंफ्रास्ट्रक्चर की खासी कमी है, यह आसान काम नहीं होगा। अन्य कंपनियों जिन्होंने अपनी वैक्सीन हेतु भारत सरकार से आपातकालीन उपयोग की अनुमति मांगी है, उन्हें इतने कम तापमान की जरूरत नहीं होगी। इसलिए माना जा रहा है कि फाइजर की वैक्सीन न केवल महंगी होगी, बल्कि इसके लिए कोल्ड चेन की उपलब्धता नहीं होने के कारण इसका वितरण अत्यंत कठिन रहेगा। देश में कोल्ड चेन के संदर्भ में भारतीय डेयरी सेक्टर से भी मदद मांगी जाने की बात आ रही है। सरकार ने वैक्सीन के वितरण हेतु काफी विस्तृत तैयारी की है। ऐसा माना जा रहा है कि देश में सबसे पहले डॉक्टरों, अन्य स्वास्थ्यकर्मियों, पुलिसकर्मियों और अध्यापकों को वैक्सीन दी जाएगी। ऐसे लोगों की संख्या लगभग तीन करोड़ होगी। उसके बाद वैक्सीन की सबसे ज्यादा जरूरत बुजुर्गों और उन लोगों को है जो ऐसी स्वास्थ्य स्थितियों में हैं, जैसे उच्च रक्तचाप, मधुमेह इत्यादि। यदि वैक्सीन वितरण का काम निजी क्षेत्र को दे दिया गया तो वैक्सीन उन जरूरतमंद वर्गों को मिलना कठिन होगा। निजी क्षेत्र के पैरोकारों का यह भी कहना है कि वैक्सीन पर कीमत नियंत्रण न लगाया जाए। लेकिन यदि देश की अधिकांश जनता को वैक्सीन उपलब्ध कराना होगा तो कंपनियों के लाभों को अंकुश में रखना भी जरूरी होगा।

नए संसद भवन की ओर

केंद्र सरकार के बहुचर्चित सेंट्रल विस्टा प्रॉजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिल जाने के बाद अब उम्मीद की जानी चाहिए कि इससे जुड़े विवादों पर विराम लगेगा और राष्ट्रीय राजधानी में नए संसद भवन के निर्माण का काम आगे बढ़ेगा। हालांकि इस प्रॉजेक्ट का भूमि पूजन पहले ही हो चुका है, लेकिन किसी भी तरह के निर्माण या तोड़फोड़ के कार्य पर कोर्ट का फैसला आने तक रोक थी। बहरहाल, इस प्रॉजेक्ट की जरूरत और इसके औचित्य को लेकर कई सवाल उठाए जाते रहे हैं। इनमें से कुछ प्रक्रियागत और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर कोर्ट में बहस भी हुई और उनपर कोर्ट की गाइडलाइंस आ गई हैं। बचे सवालों पर चर्चा जारी रह सकती है, लेकिन इस बात को लेकर कोई दो राय नहीं हो सकती कि देश को नए संसद भवन की जरूरत है। मौजूदा संसद भवन से देश की भावनाएं जुड़ी हुई हैं और इसे हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक माना जाता रहा है मगर इससे यह तथ्य नहीं बदल जाता कि यह इमारत अंग्रेजी शासनकाल में 1927 में बनाई गई थी। इस दौरान इसमें जरूरी मरम्मत वगैरह होती रही। इसका जितना विस्तार संभव है, वह भी किया जाता रहा।

बावजूद इसके, इस सचाई से आंखें मूंदे नहीं रहा जा सकता कि इस भवन को हमारी बदलती जरूरतों के अनुरूप ढाला नहीं जा सकता। कुछ ही वर्षों में परिसीमन के बाद सांसदों की बढ़ी हुई संख्या इसमें कैसे समाहित होगी यह सवाल तो है ही, इससे भी बड़ी बात यह है कि पिछले सौ वर्षों में जो तकनीकी विकास हुए हैं उनसे संसद भवन को वंचित क्यों रखा जाए। देश को तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस और हर तरह से सुरक्षित संसद भवन की जरूरत है, इसमें भला किसी तर्क-वितर्क की गुंजाइश कहां है? यह भी सही है कि ऐसे फैसले सिर्फ मौजूदा जरूरतों, अपेक्षाओं और चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए नहीं लिए जाते। आने वाले दौर के परिदृश्य का भी ख्याल रखना होता है। इसलिए अगर सरकार इस प्रॉजेक्ट को विश्वस्तरीय मानदंडों के अनुरूप आगे बढ़ाना चाहती है तो उसे अपना फलक बड़ा रखना होगा।

ध्यान रहे कि जब मौजूदा संसद भवन बन रहा था तब वह एक बड़े प्रॉजेक्ट का हिस्सा था। उसके साथ-साथ एक पूरा शहर भी बन रहा था। पूरी नई दिल्ली उस प्रॉजेक्ट के तहत खड़ी हुई जो समग्रता में राष्ट्रीय राजधानी का गरिमामय अहसास देती है।

सेंट्रल विस्टा प्रॉजेक्ट में भी हालांकि सिर्फ संसद भवन नहीं है। कई अन्य कार्यालयों के भवन भी बनाए जाने हैं। लेकिन फिर भी यह पूरी राजधानी का एक छोटा सा हिस्सा ही होगा। ऐसे में जरूरी है कि इसका डिजाइन तैयार करते समय बाकी पूरी राजधानी की डिजाइन का ध्यान रखा जाए। ऐसा न हो कि एक बेमेल सी आकृति पूरी राजधानी का लुक बिगाड़े और बाकी इमारतों के बीच संसद भवन खुद में अटपटी चीज नजर आए।

सरकार अकेले जीएसटी व्यवस्था में कमियों को ठीक नहीं कर सकती, इसमें जनता की भी सहभागिता चाहिए

> तीसरा, भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद के एरोल डिसूजा कहते हैं कि भ्रष्टाचार को रोकने में प्रेस, सिविल सोसायटी और न्यायालयों की अहम भूमिका है। जैसे यदि प्रेस को सुदृढ़ किया जाए तो वे भ्रष्ट अधिकारियों और मंत्रियों के कार्यों पर सवाल उठाते हैं। यदि अदालतों को सुदृढ़ किया जाए तो वे भ्रष्ट अधिकारियों और मंत्री दोनों पर अंकुश लगाते हैं। चूंकि इससे सरकारें स्वयं असुरक्षित हो जाती हैं इसलिए अक्सर देखा गया है कि वे प्रेस, सिविल सोसायटी और अदालतों को दबाती हैं जिससे मंत्रियों पर प्रश्न न उठाए जाएं।

उत्पाद शुल्क, बिक्री कर और चुंगी जैसी पुरानी व्यवस्था के कारण पनपी भ्रष्टाचार की समस्या पर काबू पाने के लिए देश में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को लागू किया गया। उम्मीद की गई कि इससे व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, लेकिन आज उस पर पानी फिर गया है। नंबर दो का कारोबार खुलेआम हो रहा है। देश में दो समानांतर व्यवस्थाएं बन गई हैं। एक व्यवस्था कागजी है जो कंप्यूटर में दिखती है। दूसरी कंप्यूटर के बाहर चल रही है। उद्यमी नंबर दो में कच्चा माल खरीदता है, नंबर दो में बिजली खरीदता है, नंबर दो में श्रमिकों को रखता है और नंबर दो में माल बेचता है। ट्रक वाला नंबर दो में माल दुकानदार को पहुंचाता है और दुकानदार भी नंबर दो में ग्राहकों को बेचता है।

हालांकि इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार ने ई-वे बिल की व्यवस्था बनाई, ताकि रास्ते में जांच हो सके कि माल पर टैक्स अदा किया गया है कि नहीं, लेकिन कुछ भ्रष्ट कारोबारियों ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है। आज एक ई-वे बिल पर कई बार माल का आवागमन हो रहा है। जैसे दिल्ली से फरीदाबाद के ई-वे बिल की मियाद 24 घंटे होती है। इस अवधि में चार बार माल की ढुलाई हो रही है। एक बार की ढुलाई जीएसटी देकर और तीन बार की ढुलाई नंबर दो में। अन्य दूसरे तरीकों से भी जीएसटी की चोरी हो रही है। जैसे-कई व्यापारी माल के कम मूल्य घोषित कर टैक्स बचा रहे हैं। कई जीएसटी की ऊंची दर पर कच्चे माल की खरीद दिखा उससे कम दर वाले तैयार माल की

बिक्री दिखा रहे हैं। जैसे 18 प्रतिशत जीएसटी वाले रबर की खरीद दिखाई और पांच प्रतिशत जीएसटी वाली हवाई चप्पल की बिक्री दिखाई और इनके बीच 13 प्रतिशत के जीएसटी के अंतर का रिफंड ले लिया।

इन तमाम फर्जी गतिविधियों को केवल तकनीक से नहीं रोका जा सकता है। यदि एक उद्यमी नंबर दो में कच्चा माल खरीदकर नंबर दो में बेचता है तो अधिकारी को ही मौके पर जाकर इसकी जांच करनी होगी। कंप्यूटर इसकी जांच नहीं कर सकता। यदि एक ई-वे बिल पर तीन बार माल ढुलाई की जा रही है तो ड्राइवर से पूछताछ करके ही अधिकारी इसका खुलासा कर सकता है। जीएसटी में व्याप्त ये खामियां इसलिए दूर नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि कुछ अधिकारियों की रुचि घूस लेने में ज्यादा है। इसी क्रम में सरकार ने मन बनाया है कि ई-वे बिल के साथ फास्टैग की व्यवस्था अनिवार्य कर दी जाए जिससे ट्रक कितनी बार बैरियर को पार करता है इसका आंकड़ा भी सरकार के पास उपलब्ध हो जाए, लेकिन ऐसा करने से बैरियर पर भी भ्रष्टाचार का एक रास्ता खुल जाएगा। अंततः जीएसटी चोरी रोकने के लिए सरकार को टैक्स अधिकारियों पर ही किसी तरह अंकुश लगाना होगा।

अच्छी बात है कि सरकार ने इस दिशा में कई कारगर कदम उठाए हैं। कई अधिकारियों को बर्खास्त किया गया है, लेकिन अन्य भ्रष्ट अधिकारियों को चिन्हित कर पाना सरकार के लिए कठिन हो रहा है। जाहिर है सरकार को इसके लिए नए तरीके से सोचना होगा। इस संबंध में कुछ अध्ययन मददगार साबित हो सकते हैं। पहला, यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के प्रोफेसर जॉन जोजफ वालिस ने बताया है कि अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने विशेष जोर जनता की आवाज को बुलंद करने पर दिया था। जैसे-जनता का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना, जनता की अधिकारियों और नेताओं तक पहुंच सुलभ करना, सरकार के कार्य में निष्पक्षता बनाए रखना इत्यादि। इसीलिए अमेरिकी नौकरशाही में भ्रष्टाचार कम है। उनका ध्यान ऊपर से सिस्टम को चलाने का नहीं, बल्कि नीचे से जनता द्वारा सिस्टम पर निगरानी को सुलभ बनाना था।

दूसरा, वर्ल्ड डेवलपमेंट पत्रिका ने अपने एक लेख में विश्व में भ्रष्टाचार निरोधी व्यवस्थाओं की समीक्षा की थी। उसमें पाया था कि भ्रष्टाचार निरोधी 'संस्थाएं' तो असफल हैं, पर भ्रष्टाचार 'ऑडिट' सफल है। दरअसल भ्रष्टाचार घूस लेने और देने वाले की आपसी सहमति से होता है। इसलिए भ्रष्टाचार निरोधी संस्थाएं तभी कारगर होती हैं जब दोनों में कुछ न कुछ अनबन हो जाए, लेकिन ऑडिट का अर्थ हुआ कि जांच अधिकारी संबंधित कंपनी के दफ्तर में जाकर जांच करे। चोर चोरी के सुराग तो छोड़ता ही है, लेकिन यह ऑडिट भी तभी सफल होगा जब सरकार बाहर के किसी ऑडिटर को नियुक्त करे।

तीसरा, भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद के एरोल डिसूजा कहते हैं कि भ्रष्टाचार को रोकने में प्रेस, सिविल सोसायटी और न्यायालयों की अहम भूमिका है। जैसे यदि प्रेस को सुदृढ़ किया जाए तो वे भ्रष्ट अधिकारियों और मंत्रियों के कार्यों पर सवाल उठाते हैं। यदि अदालतों को सुदृढ़ किया जाए तो वे भ्रष्ट अधिकारियों और मंत्री दोनों पर अंकुश लगाते हैं। चूंकि इससे सरकारें स्वयं असुरक्षित हो जाती हैं इसलिए अक्सर देखा गया है कि वे प्रेस, सिविल सोसायटी और अदालतों को दबाती हैं जिससे मंत्रियों पर प्रश्न न उठाए जाएं।

चौथा, पांचवें वेतन आयोग की संस्तुति में कहा गया था कि वेतन वृद्धि को उस हालत में ही लागू किया जाए जब साथ में समूह-ए अधिकारियों का प्रत्येक पांच वर्ष पर बाहरी मूल्यांकन किया जाए। चूंकि उन्हीं अधिकारियों को पांचवें वेतन आयोग को लागू करना था, लिहाजा उन्होंने वेतन वृद्धि की संस्तुतियों को तो लागू करा दिया, लेकिन बाहरी मूल्यांकन की संस्तुति को ठंडे बस्ते में डलवा दिया। इनका निष्कर्ष यही है कि सिर्फ सरकार व्यवस्था को ठीक नहीं कर सकती है, बल्कि इसके लिए ऊपर से सरकार और नीचे से जनता की भी सक्रिय सहभागिता चाहिए। नीचे से जनता की सहभागिता बढ़ेगी तो लोग सरकार से भी सवाल पूछेंगे। मंत्रियों को खुद उनका जवाब देना होगा। इससे व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होगा। अंततः इससे जीएसटी में फर्जीवाड़े पर भी अंकुश लगेगा।

गौरवशाली भारत के स्वामी प्रकाशक एवं मुद्रक प्रवीण कुमार सिंह द्वारा आला प्रिंटिंग प्रेस 3636 कटारा दिना बेग लाल कुआं, दिल्ली.... से मुद्रित एवं, ब्लॉक नं. 23 मकान नं. 399 त्रिलोकपुरी दिल्ली....91 से प्रकाशित संपादक -प्रवीण कुमार सिंह, टेलीफोन नं. 011.22786172 फैक्स नं. 011.22786172
RNI, No. DELHIN383334, E-mail: gauravashalibarat@gmail.com इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के पीआरबी एट के तहत

एक नजर

अजमेर निकाय चुनाव में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा सहित इन विधायकों की प्रतिष्ठा दांव पर

अजमेर । राजस्थान में अजमेर जिले में अजमेर नगर निगम, किशनगढ़ नगर परिषद तथा केकड़ी, सरवाड़ और बिजयनगर नगर पालिका के चुनाव होने हैं। मौजूदा समय में सिर्फ बिजयनगर को छोड़कर शेष चारों निकायों में भाजपा का कब्जा रहा है। निकाय चुनाव में क्षेत्रीय विधायक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यही वजह है कि केकड़ी व सरवाड़ में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के साथ किशनगढ़ में निर्दलीय विधायक सुरेश टाक तथा बिजयनगर में कांग्रेस के विधायक राकेश पारीक की प्रतिष्ठा दांव पर है तो वहीं अजमेर नगर निगम में उत्तर क्षेत्र के भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी तथा दक्षिण क्षेत्र की श्रीमती अनिता भदेल की प्रतिष्ठा दांव पर है। रघु शर्मा के केकड़ी विधानसभा क्षेत्र की तीन पंचायत समितियों के हाल ही के चुनाव में कांग्रेस को बुरी हार का सामना करना पड़ा। तीन में से दो पंचायत समितियों में कांग्रेस की हार हुई। ग्रामीण क्षेत्र के इन चुनावों को जीतने के लिए रघु शर्मा ने लगातार पांच दिनों तक गांव ढाणी तक में सभाएं की। इन सभाओं के बाद रघु शर्मा कोरोना वायरस से संक्रमित भी हो गए, लेकिन फिर भी कांग्रेस को जीत नहीं दिलवा सके। अब तो केकड़ी और सरवाड़ में शहरी मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे, ऐसे में रघु के सामने बड़ी राजनीतिक चुनौती है। मौजूदा समय में दोनों ही निकायों में भाजपा का कब्जा रहा है। रघु को अपने पुत्र की कार्यशैली की वजह से भी केकड़ी में विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। रघु के मंत्री बनने के बाद उनक समर्थकों ने जो बदले की कार्रवाई की उसका नुकसान भी निकाय चुनावों में उठाना पड़ेगा।

अजमेर शहर में भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी और अनिता भदेल की प्रतिष्ठा दांव पर है। नगर निगम के 80 वार्ड देवनानी के उत्तर और भदेल के दक्षिण क्षेत्र में विभाजित हैं। देवनानी और भदेल दोनों ही चौथी बार विधायक बने हैं, इसलिए दोनों की पकड़ अपने अपने क्षेत्र में मजबूत है। वार्ड उम्मीदवारों के चयन में भी दोनों विधायकों की राय को प्राथमिकता दी जा रही है। दोनों के लिए उम्मीदवारों का चयन भी चुनौतीपूर्ण है। चूंकि गत बार महेन्द्र सिंह रलावता ने उत्तर तथा हेमंत भाटी ने दक्षिण क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवर के तौर पर चुनाव लड़ा था, इसलिए कांग्रेस के उम्मीदवार इन दोनों नेताओं की राय से ही तय होंगे। किशनगढ़ नगर परिषद के चुनाव भी रौचक होंगे। भाजपा के सांसद भागीरथ चौधरी गत चुनावों में किशनगढ़ के भाजपा विधायक थे, लेकिन इस बार निर्दलीय विधायक सुरेश टाक किशनगढ़ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हालांकि टाक की राजनीतिक पृष्ठभूमि भाजपा की रही है, लेकिन मौजूदा समय में टाक प्रदेश की कांग्रेस सरकार को समर्थन दे रहे हैं। किशनगढ़ शहर में कांग्रेस की राजनीति खिचड़ी बनी हुई है। इस खिचड़ी में टाक भी अपना वजूद बनाए रखना चाहते हैं। बिजयनगर पालिक मसूदा विधानसभा क्षेत्र में आती हैं। मसूदा का नेतृत्व कांग्रेस के विधायक राकेश पारीक कर रहे हैं। पारीक के लिए यह सुखद स्थिति है कि निवर्तमान समय में भी पालिका पर कांग्रेस का ही कब्जा है। लेकिन बिजयनगर में दोबारा से कांग्रेस का बोर्ड बनवाना पारीक के लिए चुनौतीपूर्ण है। असल में जिले में कांग्रेस का संगठन बेहद कमजोर है। पारीक को अकेले ही मेहनत करनी होगी। भाजपा के लिए भी उम्मीदवारों का चयन करना आसान नहीं होगा।

लव जिहाद कानून के समर्थन में उतरे पाटीदार नेता, हार्दिक बोले दो वयस्क को विवाह का अधिकार

अहमदाबाद । पाटीदार आरक्षण आंदोलन में हार्दिक पटेल के साथी रहे सरदार पटेल ग्रुप के अध्यक्ष लालजी पटेल ने गुजरात में उत्तर प्रदेश की तरह लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की मांग की है। लालजी की मांग है कि 22 साल से कम उम्र की युवती की शादी के लिए माता-पिता की सहमति अनिवार्य हो। सरदार पटेल ग्रुप के अध्यक्ष लालजी पटेल का कहना है कि गुजरात के कई अभिभावकों की शिकायत रही है कि उनकी लड़कियों को मुस्लिम समुदाय के युवा परेशान करते हैं अथवा प्रेमजाल में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। लालजी का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर गुजरात में अंतरधार्मिक विवाह के लिए माता-पिता की मंजूरी को आवश्यक किया जाना चाहिए साथ ही इस तरह विवाह करने वाली युवती की उम्र 22 वर्ष से अधिक तथा विवाह के दौरान गवाहों की उम्र 35 वर्ष की रखी जानी चाहिए ताकि कम उम्र में अवयस्क लडकियां इस तरह की शादी के जाल में फंसने से बच जाए। पाटीदार नेता से कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बने हार्दिक पटेल के साथी रहे सतीश पटेल ने लव जिहाद के खिलाफ एक आंदोलन चलाकर जिला प्रशासन को कई जगह ज्ञापन भी सौंप चुके हैं। एक अन्य साथी जयेश पटेल का कहना है कि लवजिहाद के खिलाफ कानून बनाया जाना चाहिए लेकिन उनका यह भी कहना है कि पाटीदार आरक्षण आंदोलन समिति के एजेंडा में नहीं है, समिति आरक्षण के मुद्दे पर कार्य करती रहेगी।

गुजरात में वर्ष 2015 से 2017 तक चले पाटीदार आरक्षण आंदोलन के प्रमुख नेता हार्दिक पटेल सहित कई आंदोलनकारी जहां कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं वहीं चिराग पटेल, वरुण पटेल भाजपा में तो रेशमा पटेल एनसीपी से जुड़ चुकी हैं लेकिन इन सभी आरक्षण आंदोलन के नेताओं के अभिभावक रहे लालजी पटेल ने अब गुजरात में अंतरधार्मिक विवाह का विरोध करते हुए राज्य सरकार से इस पर कानून बनाने की मांग की है।

लव जिहाद कानून का समर्थन- गौरतलब है कि इससे पहले भाजपा सांसद मनसुख वसावा, भाजपा विधायक शैलेष सोट्टा व शशिकांत पंड्या भी इस तरह के कानून की मांग कर चुके हैं। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल का कहना है कि पाटीदार आरक्षण आंदोलन समिति के सदस्य लव जिहाद कानून के समर्थन में है, ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है। दो वयस्क युवक-युवती आपसी समझ से विवाह करना चाहते हों तो सरकार अथवा समाज को इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्हें अपने विवाह का फैसला करने का अधिकार है।

गुजरात में 11 जनवरी से खुल जाएंगे स्कूल-कॉलेज, नहीं होगी मास प्रमोशन

अहमदाबाद । गुजरात में स्कूल व कॉलेज आगामी 11 जनवरी से खुल जाएंगे। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया है। कक्षा 10वीं व 12वीं के छात्र-छात्राएं अपने माता-पिता से मंजूरी लेकर स्कूल आ सकेंगे। शिक्षामंत्री का कहना है कि जितना पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा उतने की ही परीक्षा होगी। सरकार ने इन छात्रों को मास प्रमोशन नहीं देने का भी निर्णय किया है।

शिक्षामंत्री भूपेंद्र सिंह चूडास्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री विजय रुपाणी व उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में कक्षा 10वीं, 12वीं, स्नातक व स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष की कक्षाएं 11 जनवरी से शुरु की जाएंगी। शिक्षामंत्री ने कहा है कि इन कक्षाओं के छात्रों को मास प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। छात्र-छात्राएं अनिवार्य रूप से अपने माता व पिता से स्वीकृति लेकर स्कूल कॉलेज आ सकेंगे। चूडास्मा ने बताया कि ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी तथा जितना पाढ्रयक्रम पढ़ाया जाएगा उतने की ही परीक्षा ली जाएगी। स्कूल कॉलेज में छात्र छात्राओं की हाजिरी अनिवार्य नहीं होगी। स्कूल कॉलेज संचालकों को छात्रों के बैठने की उचित व्यवस्था करनी होगी तथा तापमान जांचने के लिए थर्मल गन व सैनिटाइजर रखना होगा। अन्य कक्षाओं को शुरु करने पर भी राज्य सरकार विचार कर रही है इस पर जल्द फैसला किया जाएगा।

झारखंड के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुदेश महतो को धमकी देने वाला शख्स मुंबई से गिरफ्तार

मुंबई। झारखंड के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुदेश महतो को धमकी देने वाले व्यक्ति को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। व्यक्ति पर आरोप है कि उसने पिछले साल 14 अगस्त को झारखंड के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो को फोन पर जान से मारने की धमकी दी थी। धमकी देने वाले शख्स का नाम कमलेश पांडे है। इसे मंगलवार को शिवाजी नगर के बैंगनवाड़ी इलाके से गिरफ्तार किया गया था।

मिली जानकारी के अनुसार सुदेश महतो से इस शख्स ने फोन पर 15 लाख रुपये की मांग की थी और न देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। आरोपी ने सुदेश महतो से कहा था कि अगर पैसे नहीं दिए तो उनके घर में घुस कर गोली मार देंगे। धमकी मिलने के बाद महतो ने रांची के गोंडा पुलिस स्टेशन में शिकायत की और मामला दर्ज करवाया। इसके बाद झारखंड पुलिस ने उत्तर प्रदेश और मुंबई पुलिस से इस बारे में बात की और इस शख्स को गिरफ्तार करने की मांग की।

पांच राज्यों में बर्ड फ्लू, केंद्र ने राज्यों को किया सतर्क, अभी किसी व्यक्ति के प्रभावित होने का खतरा नहीं

नई दिल्ली । देश के पांच राज्यों में बर्ड फ्लू फैलने के बाद केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को इसके प्रसार को रोकने के लिए सतर्क कर दिया है। सर्दी का मौसम शुरू होने के साथ ही देश में आने वाले विदेशी प्रवासी पक्षियों के मार्फत बर्ड फ्लू के वायरस के पहुंचने की आशंका व्यक्त की गई है। केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश व हिमाचल प्रदेश में इसके वायरस के पहुंचने की पुष्टि हो चुकी है, जबकि हरियाणा में हजारों पक्षियों के मरने की सूचना के बाद वहां के सैंपल को जांच के लिए भेजा गया है।

किसी व्यक्ति के प्रभावित होने का खतरा नहीं – केंद्रीय पशुधन, डेयरी, पोल्ट्री व मस्त्य विभाग के सचिव अतुल चतुर्वेदी ने बताया कि बर्ड फ्लू से अभी किसी व्यक्ति के प्रभावित होने का खतरा नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पका हुआ चिकन व उबला अंडा खाने से बर्ड फ्लू नहीं फैलता है। यह पूरी तरह सुरक्षित है। उधर, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए पांच राज्यों में बर्ड फ्लू फैलने की बात कही है।

मंत्रालय ने सभी राज्यों को भेजे दिशानिर्देश में कहा है कि अपने यहां चिड़ियों व मुर्गियों की असामान्य रूप से मौत को गंभीरता से लें, ताकि बर्ड फ्लू की आशंका से निपटने में मदद मिले। चतुर्वेदी ने कहा कि 2006 के सितंबर से भारत बर्ड फ्लू मुक्त देश घोषित हो चुका था, उसके बाद यह पहली बार हुआ है।

कुल 12 जगहों पर हुई घटनाएं

पक्षियों की असामान्य मौत की घटनाएं कुल 12 स्थनों पर हुई हैं। इनमें राजस्थान के बारां, कोटा, झालावाड़ और मध्य प्रदेश के मंदसौर, इंदौर और मालवा क्षेत्र प्रमुख हैं, जहां कौवों की मौत हुई है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा क्षेत्र में प्रवासी पक्षियों के मरने की सूचना है। केरल के कोट्टायम व अलापुआ में मुर्गियों व बत्तख के प्रभावित होने की खबर है।

केंद्रीय नियंत्रण कक्ष स्थापित

एवियन इन्फ्लूएंजा की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने केंद्रीय नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर दी है, जहां से सभी प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी की जा रही है। चतुर्वेदी ने बताया कि वह खुद दिनभर में कम से कम दो बार राज्यों के सचिवों से इस बारे में विचार-विमर्श कर रहे हैं। राजस्थान व मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू के लिए गठित नेशनल एक्शन प्लान के दिशानिर्देशों के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश में वायरस के प्रसार को रोकने के बंदोबस्त करने को कहा गया है।

मनुष्य में फैलने की पुष्टि नहीं

केंद्रीय मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि बाहरी देशों से आने वाले प्रवासी पक्षियों के माध्यम से यह फैलता है, जो यहां सितंबर-अक्टूबर से लेकर फरवरी-मार्च माह तक आते-जाते हैं। बयान में कहा गया है कि देश में बर्ड फ्लू से प्रभावित मुर्गियों के खाने से मनुष्य में इसके फैलने की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने टीमें की नियुक्त

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बर्ड फ्लू के प्रकोप को देखते हुए सभी प्रभावित राज्यों में मल्टी डिस्प्लीनरी टीमें बनाकर लोगों के स्वास्थ्य पर नजर रखने को कहा है। इसके साथ ही हरियाणा के पंचकूला व केरल के कोट्टायम के लिए टीमें नियुक्त की हैं।

राजस्थान में बर्ड फ्लू का असर बढ़ गया है । प्रदेश में अब तक करीब 1200 पक्षियों की मौत हुई है, जिनमें 750 कौवे शामिल हैं। अब तक करीब 250 मुर्गियों की भी मौत हुई है। बढ़ते बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए सरकार ने दूसरे राज्यों से लगती सीमाओं पर सतर्कता बढ़ाने के साथ ही जयपुर में जांच लैब स्थापित करने का निर्णय लिया है ।

तेलंगाना में फ्लू के संकेत नहीं

तेलंगाना के पशुपालन मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि राज्य में बर्ड फ्लू का कोई संकेत नहीं मिला है। अलबत्ता, बचाव की दिशा में सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। बिहार, उत्तराखंड, पंजाब व झारखंड में अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र के ठाणे में कई पक्षियों की मौत के बाद सरकार सतर्क हो गई है।

अन्नाद्रमुक पदाधिकारी को पार्टी ने किया निष्कासित, यौन उत्पीड़न मामले में हुआ था गिरफ्तार

कोयंबटूर । तमिलनाडु के पोलाची में 2019 के सनसनीखेज यौन उत्पीड़न मामले में सीबीआइ ने सत्तारूढ़ अन्नाद्रमुक के पदाधिकारी के. अरुलानंदम समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। इस तरह इस मामले में गिरफ्तार लोगों की संख्या आठ हो गई है।

गिरफ्तारी के कुछ ही घंटों के भीतर अन्नाद्रमुक नेता और राज्य के मुख्यमंत्री एवं उपमुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी व ओ. पन्नीरसेल्वम ने अरुलानंदम को पार्टी से निष्कासित कर दिया। इसके बावजूद विपक्षी द्रमुक ने अन्नाद्रमुक पर निशाना साधा है।

पुलिस ने बुधवार को बताया कि गिरफ्तारी के बाद सीबीआइ ने तीनों आरोपितों को महिला अदालत में पेश किया जहां से उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

सीबीआइ ने यह मामला सीबी-सीआइडी से अपने हाथ में लिया था और मई, 2019 में आरोप पत्र दाखिल किया था। पोलाची में 19 वर्षीय युवती के कथित यौन उत्पीड़न मामले में सीबीआइ पहले ही पांच लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।

अरुलानंदम पोलाची कस्बे में अन्नाद्रमुक की छात्र इकाई का नेता है। उसके साथ गिरफ्तार दो अन्य लोग उसके दोस्त हैं। इस बीच, विभिन्न महिला संगठनों के करीब 50 सदस्यों ने अदालत के बाहर प्रदर्शन किया और मामले में त्वरित न्याय की मांग की।

यह मामला फरवरी, 2019 में सामने आया था जब 19 वर्षीय छात्रा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि चार व्यक्तियों ने कार में उसके कपड़े फाड़ने की कोशिश की, उसका वीडियो बनाया और उसे ब्लैकमेल किया। माना जाता है कि इस गैंग ने पोलाची में बड़ी संख्या में महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया था और उन्हें ब्लैकमेल किया था।

द्रमुक अध्यक्ष एमके स्टालिन ने कहा, यह घटना दर्शाती है कि तमिलनाडु में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। द्रमुक लंबे समय से दावा कर रही है कि इस मामले में अन्नाद्रमुक के पदाधिकारी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक सदस्य ने कोलकाता में राज्य सरकार के खिलाफ विरोध रैली के दौरान नारे लगाए।

केरल हाई कोर्ट ने दिया वालयार मामले में फिर मुकदमा चलाने का आदेश, घर में मृत मिली थीं दोनों नाबालिग बहनें

कोच्चि । केरल हाई कोर्ट ने वालयार मामले में पाक्सो अदालत के फैसले को न्याय की हत्या जैसा बताते हुए बुधवार को फिर मुकदमा चलाने का आदेश दिया। यह मामला 2017 में कथित यौन उत्पीड़न के बाद दो नाबालिगबहनों के अपने घर में मृत मिलने से जुड़ा है।

जस्टिस ए. हरिप्रसाद और जस्टिस एमआर अनिता की खंडपीठ ने राज्य सरकार और बच्चियों की मां की ओर से दायर अपील को मंजूर कर लिया और मामले में पांच आरोपितों को बरी करने के पाक्सो अदालत के आदेश को दरकिनार कर दिया। हाई कोर्ट ने आरोपितों को आगामी 20 जनवरी को निचली अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि जांच में गंभीर खामियां रहीं और समूचे मामले पर पुन- विचार किए जाने की आवश्यकता है। पीठ ने अभियोजन को मामले में आगे की जांच के लिए निचली अदालत से अनुमति मांगने की स्वीकृति भी दे दी।

हाई कोर्ट ने कहा कि मामले की जांच में शुरू में गंभीर खामियां रहीं और जांच अधिकारी छोटी लड़की की मौत के एक सप्ताह बाद भी कोई उचित वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने में

विफल रहा। पीठ ने मामले से निपटने में पाक्सो अदालत के तरीके पर भी असंतोष व्यक्त किया और पाक्सो अदालत के न्यायाधीशों को विशेष प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया। दोनों बहनों में से 13 वर्षीय बड़ी लड़की पलक्कड़ के वालयार स्थित अपने घर में 13 जनवरी, 2017 को फंदे से लटकी मिली थी, जबकि नौ वर्षीय उसकी छोटी बहन चार मार्च को मृत मिली थी। ये दोनों लड़कियां कथित रूप से यौन उत्पीड़न की शिकार हुई थीं।

पलक्कड़ स्थित विशेष पाक्सो अदालत ने हालांकि अक्टूबर, 2019 में साक्ष्यों के अभाव में पांचों आरोपितों को बरी कर दिया था। आरोपितों को बरी किए जाने के बाद सरकार ने 18 नवंबर को मामले को देखने वाले लोक अभियोजक को हटा दिया था। सरकार ने इसके बाद आरोपितों को बरी किए जाने के पाक्सो अदालत के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

कोरोना को लेकर 6 माह बाद आयी अच्छी खबर, नहीं हुई एक भी मौत

भुवनेश्वर । कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई में ओडिशा को बड़ी सफलता हाथ लगी है। प्रदेश में 6 महीने बाद एक भी संक्रमित मरीज की मौत नहीं हुई है। वहीं संक्रमण के मामले में भी लगातार गिरावट जारी है। बुधवार को प्रदेश में 231 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं। राज्य सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने ट्वीट कर इसके लिए कोरोना योद्धाओं के प्रति सम्मान प्रकट किया है।

राज्य सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक नए संक्रमित मरीजों में 133 क्वारंटाइन से हैं जबकि 98 स्थानीय लोग संक्रमित हुए हैं। इन्हें मिलाकर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 3 लाख 30 हजार 921 हो गई है। हालांकि इसमें से 3 लाख 26 हजार 778 संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। वर्तमान समय में राज्य सक्रिय मरीजों की संख्या 2203 है जिनका विभिन्न कोविड अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसी के साथ प्रदेश में कोरोना से मरने वाले मरीजों की संख्या 1887 पर स्थिर बनी हुई है।

आज संक्रमित पाए गए मरीजों में अनुगुल जिले से 21, बालेश्वर जिले से 8, बरगड़ जिले से 25, भद्रक जिले से 5, बलांगीर जिले से 11, बौद्ध जिले से 1, कटक जिले से 11, देवगड जिले से 2, ढेंकानाल जिले से 2, गजपति जिले से 3, गंजाम जिले से 4, जगतसिंहपुर जिले से 2, जाजपुर जिले से 12, झारसुगुडा जिले से 15, कालाहांडी जिले से 1, केन्द्रापड़ा जिले से 10, केन्दुझर जिले से 9, खुर्दा जिले से 11, कोरापुट जिले से 3, मयूरभंज जिले से 8, नवरंगपुर जिले से 2, नयागड़ जिले से 2, नुआपड़ा जिले से 1, पुरी जिले से 10, रायगड़ा जिले से 1, सम्बलपुर जिले से 14, सोनपुर जिले से 2, सुन्दरगड़ जिले से 32 कोरोना संक्रमित मरीज की पहचान हुई है।

2020 में इंटरनेट शटडाउन की वजह से भारत को हुआ करीब 204.89 अरब रुपये का नुकसान

नई दिल्ली । इंटरनेट जहां लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। वहीं आर्थिक प्रबंधन का बड़ा कारक भी साबित हुआ है। इसके उपयोग और प्रभाव को जानना है तो इन तथ्यों पर गौर फरमाइए। ब्रिटेन के डिजिटल प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी रिसर्च ग्रुप टॉप-10 वीपीएन की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत को 2020 में इंटरनेट शटडाउन की वजह से लगभग 2.8 बिलियन डॉलर (करीब 204.89 अरब रुपये) का नुकसान हुआ और8,927 घंटे तक इंटरनेट के इस्तेमाल पर लगी पाबंदी से 1.3 करोड़ उपभोक्ता प्रभावित हुए। इस मामले में यह आंकड़ा विश्व में

सर्वाधिक है।

सिर्फ प्रमुख जगह ही शामिल

बीते साल भारत में कुल 75 बार इंटरनेट शटडाउन किया गया। रिपोर्ट में मुख्य स्थानों को ही शामिल किया गया है, इसमें गांव और कस्बों इत्यादि का जिक्र नहीं है। इन्हें शामिल करने पर आर्थिक क्षति 204.89 अरब रुपये से ज्यादा हो जाएगी।

भारत उन 21 देशों में टॉप पर रहा जिन्होंने इंटरनेट पर पाबंदी लगाई। इन देशों में कुल 93 बार इंटरनेट शटडाउन किया गया। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर बेलारूस और तीसरे पर यमन हैं। विश्वभर में कुल इंटरनेट शटडाउन 27,165 घंटे का रहा जो बीते साल से 49 प्रतिशत ज्यादा था। इसके अलावा इंटरनेट मीडिया शटडाउन 5,552 घंटे रहा।

कश्मीर में बीते साल मार्च में इंटरनेट शटडाउन किया गया जो साल के अंत तक जारी रहा। इस प्रकार करीब सात महीने लोगों को बिना इंटरनेट के रहना पड़ा। इससे पहले अगस्त 2019 के बाद से कश्मीर के लोगों के लिए सिर्फ टूजी सेवा उपलब्ध कराई गई थी।

एक साल पहले की पाबंदियां रहीं जारी- रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में 2020 में 1,655 घंटों तक इंटरनेट ब्लैकआउट रहा और 7,272 घंटों की बैंडविथ प्रभावित हुई। यहां जो पाबंदियां 2019 में लगाई थीं वे 2020 में भी जारी रहीं और भारत को 2020 में इंटरनेट बंद होने से 2019 की तुलना में ज्यादा नुकसान हुआ। बीते साल महामारी के चलते चार बिलियन डॉलर (292 अरब रुपये) आर्थिक क्षति पहुंची। शटडाउन से भारत के अलावा म्यांमार सबसे ज्यादा प्रभावित रहा।

भारी बर्फबारी के चलते देश-दुनिया से कटा कश्मीर का संपर्क, सीआरपीएफ अधिकारी समेत दो की मौत

नई दिल्ली। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और बारिश आफत बन कर गिर रही है। इसमें सबसे अधिक प्रभावित जम्मू-कश्मीर है। बुधवार को लगातार चौथे दिन भी कश्मीर का शेष दुनिया से हवाई और सड़क संपर्क कटा रहा। वहीं मकान गिरने से सीआरपीएफ के एक अधिकारी समेत दो लोगों की मौत हो गई। जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग गुरुवार को भी बंद रहेगा। इस पर कई जगह भूस्खलन हुआ है। कश्मीर के विभिन्न जिलों में 200 से अधिक सड़कों पर भारी बर्फ पड़ी है। इससे यातायात ठप है।

कई जिलों में हिमस्खलन की चेतावनी-हिमपात से कश्मीर में ही सौ से अधिक मकानों को नुकसान पहुंचा है। बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। कश्मीर समेत जम्मू संभाग के पर्वतीय इलाकों में भारी हिमस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। कश्मीर में बर्फबारी का सिलसिला दोपहर को थम गया था।

श्रीनगर के हजरतबल इलाके में पूर्व विधायक मोहम्मद सईद आखून के घर की छत गिरने से सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर एचसी मुर्मू की मौत हो गई। बंगाल के मुर्मू सीआरपीएफ की 115 बटालियन के जवान थे और पूर्व विधायक की सुरक्षा में तैनात थे। कुपवाड़ा जिले में त्रेगाम इलाके के शाह मोहल्ला में घर की छत गिरने से 70 वर्षीय रहीमा बेगम की दबकर मौत गई। आपदा प्रबंधन विभाग की टीमों ने कुलगाम जिले में बर्फ में फंसे 30 परिवारों को सुरक्षित निकाल लिया है। जिले के कुंड क्षेत्र में ये परिवार सात फीट बर्फ गिरने से अपने घरों में ही बंद हो गए थे। इस इलाके में हिमस्खलन की चेतावनी जारी की गई है।

उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में जहां तड़के झमाझम बारिश से जन-जीवन अस्त-व्यस्त रहा तो पहाड़ों में भारी हिमपात ने दुश्वारियां बढ़ाई। उत्तरकाशी और चमोली के करीब चार दर्जन गांवों में बिजली आपूर्ति ठप रही। कई गांवों का संपर्क भी कट गया है। गंगोत्री हाईवे धराली के पास हिमखंड आने से छह घंटे बाधित रहा। उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में भारी हिमपात हुआ है।

बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड के साथ ही रुद्रप्रयाग के चोपता, उत्तरकाशी जिले के हर्षिल, चमोली के औली में एक से डेढ़ फीट तक बर्फ की चादर बिछ गई है। बदरीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री भी बर्फ से लकदक हैं।

हिमाचल प्रदेश में बर्फ के दीदार के लिए मंगलवार को सोलंगनाला गए करीब 1500 पर्यटकों को रात वाहनों में ही काटनी पड़ी। रातभर रेस्क्यू अभियान चलता रहा, लेकिन बर्फबारी और पर्यटक वाहनों की संख्या ज्यादा होने के कारण लंबा जाम लग गया। पुलिस कर्मचारी रातभर वाहनों को निकालने में जुटे रहे। बुधवार दोपहर तक पर्यटक वाहनों को मनाली पहुंचाने का कार्य जारी रहा। कुछ पर्यटक जो टैक्सी में गए थे वे तो आधी रात तक मनाली पहुंच गए, लेकिन अधिकतर पर्यटक अपनी गाड़ियां छोड़ने को तैयार नहीं थे। दो सौ से अधिक पर्यटक वाहन सोलंगनाला से पलचान के बीच फंसे रहे।

हर सरकारी स्कूल में बनवाए जाएंगे किचन गार्डन

पोषण वाटिकाओं (किचन गार्डन) का नाम होगा माँ की बगिया

मुख्यमंत्री ने किया ने 2500 किचन शेड एवं 7100 पोषण वाटिकाओं का लोकार्पण

भोपाल (एजेंसी)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मनरेगा के माध्यम से हर शासकीय स्कूल में पोषण वाटिका (किचन गार्डन) बनवाए जाएंगे। स्कूलों में जगह न होने पर गांव में अन्य स्थान पर भी पोषण वाटिका बनाई जा सकती है। श्री चौहान ने कहा कि अब पोषण वाटिका का नाम'माँ की बगिया'होगा। स्कूल की स्वच्छता एवं माँ की बगिया के विकास एवं संरक्षण में विद्यार्थियों का पूरा योगदान लिया जाए।मुख्यमंत्री गुरुवार को यहां प्रदेश में निर्मित 2500 किचन शेड और 7100 पोषण वाटिकाओं के लोकार्पण के बाद संबोधित कर रहे थे।

सीएम ने इनसे किया वर्चुअल संवाद: मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कार्यक्रम में बालाघाट जिले के ग्राम जंगलटोला की सरपंच श्रीमती गुणवंता बिसेन, ग्वालियर जिले के ग्राम उटीला (मुरार) के शिक्षक पालक संघ के अध्यक्ष देवेन्द्र बघेल तथा गायत्री देवी से वर्चुअल संवाद किया। मुख्यमंत्री ने अच्छा किचन शेड निर्माण के लिए उन्हें बधाई दी।

हम तो अपने स्कूल में झाड़ू लगाते थे

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पहले बच्चे अपने स्कूल में स्वच्छता तथा स्कूल की तरक्की में अपना पूरा योगदान देते थे। हम तो अपने स्कूल में झाड़ू लगाते थे। स्कूल की स्वच्छता आदि के काम में कोई शर्म नहीं है। विद्यार्थियों को यह काम करना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि भोजन हितभुक अर्थात शरीर के लिए लाभदायी, मितभुक अर्थात सीमित मात्रा में तथा ऋतुभुक अर्थात मौसम के अनुरूप होगा, तभी हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। स्कूल में पोषण वाटिका बनाने का उद्देश्य है कि बच्चों को ताजी व अच्छी सब्जियां मध्यान्ह भोजन के लिए मिल सकें।

मैं सीएम हाउस के किचन गार्डन का नाम भी मां की बगिया रखूंगा

मुख्यमंत्री श्री चौहान को भोपाल जिले के फंदा की प्राथमिक शाला, सिंकदराबाद की स्व-सहायता समूह की रसोइया श्रीमती सुनीता मारन ने बताया कि उन्होंने स्कूल में बनाई गई पोषण वाटिका का नाम'माँ की बगिया'रखा है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उपयुक्त नाम है। अब प्रदेश की सभी पोषण वाटिकाओं को'माँ की बगिया'कहा जाएगा। मैं सीएम हाऊस के किचन गार्डन का नाम भी माँ की बगिया रखूंगा।

बर्ड फ्लू के रोकथाम व नियंत्रण की पूरी तैयारी रखें: एसीएस

कलेक्टरों को दिशा निर्देश जारी

भोपाल (एजेंसी)। मध्यप्रदेश में बर्ड फ्लू की रोकथाम और नियंत्रण के लिए कलेक्टरों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अपर मुख्य सचिव पशुपालन जेएन कंसोटिया ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को बर्ड फ्लू की रोकथाम और नियंत्रण करने के उद्देश्य से दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

उन्होंने सभी कलेक्टरों को पशुपालन, वन, स्वास्थ्य, स्थानीय निकाय और अन्य संबंधित विभागों के साथ बैठक कर किसी इमरजेंसी से निपटने की पूर्ण तैयारी की समीक्षा करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने सभी को सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। यहां जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि पशु चिकित्सा विभाग के जिला कार्यालय में कंट्रोल रूम की स्थापना के साथ ही पीपीई किट की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। सैंपल एकत्र और डिस्पोजल के समय विभागीय अमला अनिवार्य रूप से पीपीई किट पहने।

जिलों में पदस्थ पशु चिकित्सा विभाग के उप संचालक प्रतिदिन संचालनालय पशुपालन भोपाल को निर्धारित फारमेट में रिपोर्टिंग करेंगे। मुर्गियों, कौवों और प्रवासी पक्षियों आदि की असामान्य मृत्यु- बीमारी की सूचना मिलते ही उस स्थान को तुरंत सेनिटाइज कराएं। कलेक्टरों से कहा गया है कि कुक्कुट पालक और जनसामान्य को बर्ड फ्लू रोग से बचाव की जानकारी अभियान चलाकर दें। पशुपालन विभाग और अन्य समन्वयक विभाग जिले में संपूर्ण सतर्कता और सावधानी सुनिश्चित करें।

प्रदेश में कोरोना वेक्सिनेशन के ड्राई रन की सभी तैयारियां पूरी

डॉ. चौधरी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन को दी जानकारी

भोपाल (एजेंसी)। लोक स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन से कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सतत निगरानी में प्रदेश के सभी 52 जिलों में कोराना वेक्सिनेशन की तैयारियां पूरी कर ली गई है। डॉ. चौधरी गुरुवार को वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय ड्राय रन तैयारियों संबंधी आयोजित वर्चुअल बैठक में भाग ले रहे थे। उन्होंने कहा कि वेक्सिनेशन के लिए तैयार कोविन प्लेटफार्म बहुत अच्छा है।

डॉ. चौधरी ने बताया कि प्रदेश में कोविड-19 के लिए वेक्सिनेशन के पूर्व रिहर्सल के तौर पर तैयारियों को परखने भोपाल में दो जनवरी के सफल आयोजन के बाद अब आठ जनवरी को प्रदेश के शेष 51 जिलों में ड्राई रन का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में चार स्थानों भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और इंदौर में कोल्ड चैन स्टोर तैयार किया है। पहले इन स्टोर में स्वीकृत वैक्सीन का भंडारण होगा। यहां से वैक्सीन को संभाग, संभाग से जिलों और जिलों से पीएचसी में बनाए गए कोल्ड चैन स्टोर में भेजा जाएगा। यहां से वैक्सीन सीधे टीकाकरण केंद्र पर पहुंचाई जाएगी, जहां पर पहले से रजिस्टर्ड व्यक्तियों का टीकाकरण किया जाएगा। पहले चरण में सभी हेल्थ वर्कर का टीकाकरण होगा।

51 जिलों में ड्राई रन आज

प्रदेश में कोविड-19 के लिए वेक्सिनेशन के पूर्व रिहर्सल के तौर पर तैयारियों को परखने आठ जनवरी को रायसेन सहित प्रदेश के 51 जिलों में ड्राई रन का आयोजन किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी ने ड्राय रन के लिए रायसेन में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर का गुरुवार को निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने ड्राय रन के लिए वैक्सीन केरियर से वैक्सीन को टीकाकरण केंद्र तक पहुंचाने, टीकाकरण तथा इस दौरान कोविड-19 टीकाकरण के सभी प्रोटोकॉल का पालन किए जाने के संबंध में निर्देश दिए।

बानसुजारा योजना से 120 ग्रामों में मिलेगा पेयजल

भोपाल (एजेंसी)। छतरपुर जिले के बड़ामलहरा विकासखंड के 120 ग्रामों में रहने वाले परिवारों को आगामी मार्च 2021 के उपरांत नल कनेक्शन से पेयजल उपलब्ध करवाए जाने की तैयारी है।

मप्र जल निगम मर्यादित द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिले के विकासखंड के लिए 210.85 करोड़ रुपए की लागत से बानसुजारा (बड़ामलहरा) समूह जल प्रदाय योजना का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस समूह जलप्रदाय योजना का करीब 97 प्रतिशत कार्य हो चुका है और योजना के कमिशनिंग कार्य, फिनिशिंग कार्य, बाउंड्री बाल तथा टेस्टिंग कार्य को मार्च 2021 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है। कोरोना संक्रमण के चलते हुए लॉकडाउन के कारण कार्य में गतिरोध आया था जिसे त्वरित गति से अब पूरा किए जाने के प्रयास जारी हैं। बानसुजारा समूह जलप्रदाय योजना के पूर्ण होते ही एक लाख 58 हजार 564 ग्रामीण आबादी को जलापूर्ति की जा सकेगी। इस समूह जलप्रदाय योजना के अन्तर्गत बांध में इंटेक वेल, जल शोधन संयंत्र क्षमता 21.56 मिलियन लीटर प्रतिदिन, टंकियों का निर्माण एवं 614 किलो मीटर पाईप लाइन बिछाकर घरेलू नल कनेक्शन दिए जाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं।

शिवराज, सिंधिया और भार्गव ने राजगढ़ पहुंचकर शोकाकुल सोनी परिवार को दी सांत्वना

भोपाल । मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को राजगढ़ पहुंचकर राष्ट्रवादी विचारक सुरेश सोनी से भेंट की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सुरेश सोनी की माताजी श्रीमती कंचन बेन सोनी के निधन पर परिवार को सांत्वना प्रदान की। श्री चौहान के साथ सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव भी राजगढ़ पहुंचे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सोनी परिवार के राजगढ़ स्थित निवास पहुंचकर सुरेश सोनी जी के अलावा अन्य परिजन से भी भेंट की। सीएम श्री चौहान, सांसद श्री सिंधिया और मंत्री श्री भार्गव ने स्व. श्रीमती कंचन बेन सोनी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। यहां बता दें कि गत एक जनवरी को श्रीमती कंचन बेन का देहावसान हो गया था।

मुख्यमंत्री ने समाधान ऑनलाइन में किया समस्याओं का त्वरित निराकरण

योजनाओं के प्रदाय में विलंब किया तो होगी कार्रवाई

लोगों को मोबाइल पर सेवाएं देने वाला मप्र पहला राज्य

भोपाल (एजेंसी)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में सुशासन के लिए जनता को शासकीय योजनाओं का समय पर लाभ दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। यदि उन्हें इनका लाभ मिलने में विलंब होता है तो विलंब के लिए जिम्मेदार शासकीय अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत विद्यार्थियों को ऑनलाइन राशि समय पर अंतरित किए जाना सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन 181 के अंतर्गत मोबाइल के माध्यम से स्थानीय निवासी एवं जाति प्रमाण-पत्र एक ही दिन में दिए जाने की सुविधा प्रदान करने वाला मप्र देश का पहला राज्य है। **सीएम हैल्पलाइन में नागरिक अब अपनी शिकायतें व्हॉटसएप नंबर 7552555582 पर भी दर्ज करवा सकते हैं।**

फसल बीमा की राशि सभी किसानों को मिले

मुख्यमंत्री श्री चौहान को शाजापुर जिले के आवेदक श्री मनोज राजपूत ने बताया कि उसे फसल बीमा की राशि नहीं मिली है। इस पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि फसल बीमा योजना का लाभ हर प्रभावित किसान को दिलाना सुनिश्चित किया जाए। बड़वानी जिले के आवेदक बद्री ने सीएम को बताया कि जिला प्रशासन ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए उसे जमीन का पट्टा दिलवाया है। सीएम ने आवेदक की समस्या समझने तथा त्वरित कार्रवाई कर उसे पट्टा देने के लिए जिला प्रशासन को बधाई दी।

सहायता में न हो विलंब: मुख्यमंत्री को रायसेन जिले के जय सिंह बंजारा ने बताया कि बेटे की मृत्यु के उपरांत उन्हें सहायता मिलने में बहुत विलंब हुआ। अब उन्हें सहायता मिल गई है। मुख्यमंत्री ने कार्य में विलंब के लिए संबंधित पंचायत सचिव को निलंबित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री को रीवा जिले के किसान श्री भगवत सिंह ने बताया कि उन्हें बाणसागर परियोजना में भूमि अधिग्रहण का मुआवजा मिलने में देरी हुई है। कलेक्टर ने बताया कि लंबित सभी प्रकरणों का निराकरण करते हुए 194 किसानों को मुआवजा दिला दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विलंब के संबंध में संबंधित एस.डी.एम. से कारण पूछे जाने के निर्देश दिए।

पूरी राशि एक साथ दी जाए: इंदौर जिले में बैंक ऑफ इंडिया की एक शाखा द्वारा स्ट्रीट वेण्डर योजना के अंतर्गत 10 हजार के स्थान पर 05-05 हजार रूपए दिए जाने की शिकायत पर संबंधित बैंक मैनेजर ने बताया कि दस्तावेजों के पूरे न होने के कारण दो किश्तों में राशि दी जा रही है। इस पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि योजना के अंतर्गत पूरी राशि 10 हजार रूपए एक साथ प्रदाय की जाए।

उच्च प्रदर्शन वाले जिलों की सराहना की: श्री चौहान ने सीएम हेल्पलाइन में समस्याओं के निराकरण में अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिले सिवनी, सिंगरौली, छिंदवाड़ा, छतरपुर, देवास, बुरहानपुर, होशंगाबाद, डिंडौरी, झाबुआ तथा रतलाम की सराहना करते हुए कलेक्टर्स को बधाई दी। वहीं खराब प्रदर्शन वाले जिलों रायसेन, मुरैना, भिंड, इंदौर, शिवपुरी, शाजापुर, खरगौन, बड़वानी, धार तथा आगर-मालवा को कार्य सुधारने के निर्देश दिए गए।

सीएमओ और लिपिक को निलंबित करें

मुख्यमंत्री ने शिवपुरी जिले के एक प्रकरण में शासकीय योजना की किश्त देने में हितग्राही (दामोदर प्रसाद) को विलंब किए जाने की शिकायत पर तत्कालीन सीएमओ और लिपिक को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए।

दोषी पुलिस अधिकारियों को निलंबित करें

मुख्यमंत्री श्री चौहान को मंडला जिले के आवेदक श्री देवेन्द्र ने बताया कि उसकी बहन 2018 से लापता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रकरण को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए तुरंत उसे ढूंढने की कार्रवाई करने तथा दोषी पुलिस अधिकारियों को निलंबित करने के निर्देश दिए।

छात्रवृत्ति की राशि नहीं मिली, प्राचार्य को निलंबित करें

मुख्यमंत्री श्री चौहान को दतिया की कुमारी श्रद्धा पिता राधेश्याम ने बताया कि उसे गांव की बेटी योजना के अंतर्गत प्रथम व द्वितीय वर्ष की छात्रवृत्ति की राशि नहीं मिली है। इस पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि कार्य में लापरवाही करने पर महाविद्यालय के प्राचार्य के निलंबन की कार्रवाई करें।

शिकायतों के निवारण में अव्वल अधिकारियों को बधाई दी

सीएम द्वारा सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में प्रदेश में अव्वल आने वाले पांच अधिकारियों जितेन्द्र सिंह रघुवंशी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी इंदौर, एनके सोनार सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी नीमच, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण सीहोर, अमरजीत कुमार कनिष्ठ अभियंता ऊर्जा विभाग मंडला तथा संजय कुलश्रेष्ठ नगरीय विकास एवं आवास विभाग उज्जैन को बधाई दी।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शर्मा से मिले सांसद सिंधिया

गुरुवार को भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा से उनके निवास पर पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सौजन्य भेंट की।

किसान आंदोलन राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष शर्मा ने कमलनाथ पर साधा निशाना

भोपाल (एजेंसी)। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ द्वारा प्रदेश में किसान सम्मेलन का आयोजन करने की बात को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की स्थिति बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी है और वे अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए किसान आंदोलन कर रहे हैं।

श्री शर्मा ने कहा कि कमलनाथ को अब किसान आंदोलन की याद आ रही है, लेकिन जब कांग्रेस ने मध्यप्रदेश में किसान आंदोलन का आह्वान किया था तब कमलनाथ आंदोलन से गायब थे। आज सिर्फ अपना राजनैतिक अस्तित्व बचाने के लिए कमलनाथ जी किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं। मप्र का किसान पीएम नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। किसान आंदोलन के नाम पर कांग्रेस सिर्फ अपनी राजनीति चमकाना चाहती है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश के किसान नए केंद्रीय कानूनों को समर्थन देने लगे हैं, इसलिए कांग्रेस नेता घबड़ाए हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी छिंदवाड़ा में किसान सम्मेलन करवा रहे हैं। श्री शर्मा ने बताया कि श्री कमलनाथ ने ही कहा था कि उन्होंने छिंदवाड़ा में सबसे पहले कांटेक्ट फार्मिंग शुरू की थी, लेकिन अब इसका विरोध किया जा रहा है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने मीडिया से कई मुद्दों पर की विस्तार से चर्चा

मैं मध्यप्रदेश में ही रहूंगा, कहीं नहीं जा रहा : कमलनाथ

भोपाल (एजेंसी)। मैं मध्यप्रदेश में ही रहूंगा, कहीं नहीं जा रहा, यह कहना था कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का। गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने इस कयास पर विराम लगाया कि वे दिल्ली जा रहे हैं। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, पीसी शर्मा, जीतू पटवारी एवं अन्य पार्टी पदाधिकारी मौजूद थे।

श्री कमलनाथ ने कहा कि वे स्पष्ट करना चाहते हैं कि उनका शेष जीवन भी इसी प्रदेश में कटेगा और वे कहीं नहीं जा रहे हैं। उन्होंने प्रतिप्रश्न करते हुए कहा 'क्या वे आराम करने लायक दिखते हैं।' एक से अधिक पदों पर बने रहने संबंधी सवालों के जवाब में कमलनाथ ने कहा कि उन्होंने कभी भी किसी भी पद के लिए आवेदन नहीं दिया था। केंद्रीय नेतृत्व ने जो भूमिका तय की, वह जिम्मेदारी निभाई और आगे की जिम्मेदारी भी केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा।

श्री कमलनाथ ने ई-टेंडर घोटाला, आयकर छापों के बाद केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की रिपोर्ट संबंधी मामलों से जुड़े सवालों के जवाब में कहा कि वे इस पक्ष में हैं कि सभी मामलों की जांच होना चाहिए, लेकिन जांच राजनैतिक नहीं होकर निष्पक्ष हो। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने अपने 15 माह के शासनकाल के दौरान बदले की भावना से जांच कराने का कार्य नहीं किया। उनकी प्राथमिकता प्रदेश की तस्वीर बदलने की रही और जांच के कार्य भी चलते रहे।

प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी का गठन जल्द

प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी के गठन संबंधी सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस संबंध में उनकी प्रदेश के नेताओं के अलावा केंद्रीय नेताओं से चर्चा चल रही है। इस मुद्दे को लेकर अलग-अलग मत भी आए हैं। फिर भी इस पर जल्दी ही निर्णय होने की संभावना उन्होंने जताई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के आसपास एक माह से अधिक समय से जारी किसान आंदोलन और देश तथा मध्यप्रदेश के संदर्भ में किसानों तथा कृषि की दशा पर उन्होंने विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि अब प्रदेश कांग्रेस राज्य के किसानों को इन मुद्दों पर जागरूक करने के लिए अभियान चलाएगी।

आगामी कार्यक्रमों की दी जानकारी: प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष चंद्रप्रभाष शेखर ने बताया कि आज से 15 जनवरी तक विभिन्न जिलों में कांग्रेस कमेटियों की ओर से एक दिन का धरना, प्रदर्शन और बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद 15 जनवरी को दोपहर में किसानों द्वारा चक्काजाम विभिन्न इलाकों में किए जाएंगे। इसी क्रम में 20 मार्च को मुरैना जिला मुख्यालय पर किसान महापंचायत आयोजित की जाएगी। इसके बाद 23 जनवरी को किसानों द्वारा राजधानी भोपाल में राजभवन का घेराव किया जाएगा।

फेथ ग्रुप,जोशी दंपती की आयकर द्वारा अटैच संपत्ति का एग्रीमेंट

अब विभाग ले रहा कानूनी सलाह

भोपाल (एजेंसी)।

बर्खास्त आईएएस दंपती अरविंद जोशी, टीनू जोशी एवं फेथ ग्रुप की आयकर विभाग द्वारा बेनामी संपत्ति जिसको विभाग ने अटैच कर लिया था का एग्रीमेंट कर लिया गया है। अब विभाग इस मामले में कानूनी सलाह ले रहा है।

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (मप्र-छग) आरके पालीवाल ने बताया कि फेथ ग्रुप के मालिक राघवेंद्र सिंह तोमर और बर्खास्त आईएएस दंपती अरविंद व टीनू जोशी की भोपाल में अटैच की गई प्रॉपर्टी के ही एग्रीमेंट कर लिए जबकि इनकी खरीद-फरोख्त पर रोक है। इसमें क्रिकेट स्टेडियम की जमीन समेत अन्य संपत्तियां शामिल बताई जा रही हैं। इससे जुड़े दस्तावेज आयकर विभाग के हाथ लगे हैं। बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट के प्रावधानों से छेड़छाड़ को देखते हुए विभाग अब कानूनी सलाह लेने जा रहा है। दरअसल, आईटी ने पिछले साल अगस्त में फेथ ग्रुप समेत अन्य पर छापा मार कार्रवाई की थी। पड़ताल में ग्रुप के तार बर्खास्त आईएएस दंपती अरविंद व टीनू जोशी से जुड़े होने की बात सामने आई थी। जोशी के रिश्तेदार ने इनकी प्रॉपर्टी में बड़ा निवेश किया था। मिली जानकारी के अनुसार क्रिकेट अकादमी व ग्राउंड की 20 से 30 फीसदी जमीन जोशी की बेनामी संपत्ति का हिस्सा है। यह जमीन जोशी के पिता के नाम पर बताई जा रही है।

100 करोड़ की प्रॉपर्टी राजसात करने की मिली मंजूरी

जोशी दंपती की 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बेनामी है। दंपत्ति ने अपने माता-पिता, बहन और करीबी सीमांत कोहली के परिवार के नाम पर यह खरीदी थी। इसमें फेथ क्रिकेट अकादमी की दस एकड़ जमीन समेत 220 एकड़ भूमि और आवासीय भूखंड, फ्लैट आदि शामिल बताए जा रहे हैं। भोपाल, सीहोर, रायसेन, मंडला सहित अन्य स्थानों पर यह संपत्ति हैं। आयकर विभाग सभी बेनामी प्रॉपर्टी सीज (राजसात) करेगा। एडजुडिकेटिंग अर्थॉरिटी (अधिनिर्णय प्राधिकारी) से विगत वर्ष इसकी मंजूरी मिल चुकी है।

तीन साल में अटैच की 500 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी

आयकर विभाग ने विगत तीन वर्ष में 800 बेनामी संपत्तियां अटैच की है। इनकी खरीदी-बिक्री पर रोक भी लगी हुई है। इसमें 600 संपत्तियां भोपाल, इंदौर, जबलपुर समेत प्रदेश के अन्य शहरों और 200 प्रॉपर्टी छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर व दूसरे शहरों में है। वर्ष 2016-17 से अटैच की गई संपत्तियों का वर्तमान मूल्य करीब 500 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। हालांकि, खरीदी के समय इनकी कीमत 100 करोड़ रुपए के आसपास रही होगी। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नीलामी की प्रक्रिया होने पर ही प्रॉपर्टी का सही मूल्य सामने आ सकेगा। श्री पालीवाल के मुताबिक मौजूदा वित्तीय वर्ष में दिसंबर में ही 115 संपत्तियां अटैच की गई हैं। इसमें 80 प्रॉपर्टी मप्र और 35 छत्तीसगढ़ में हैं।

कैसे हुई थी बॉलीवुड में शाहरुख खान की फिल्म से दीपिका की एंट्री

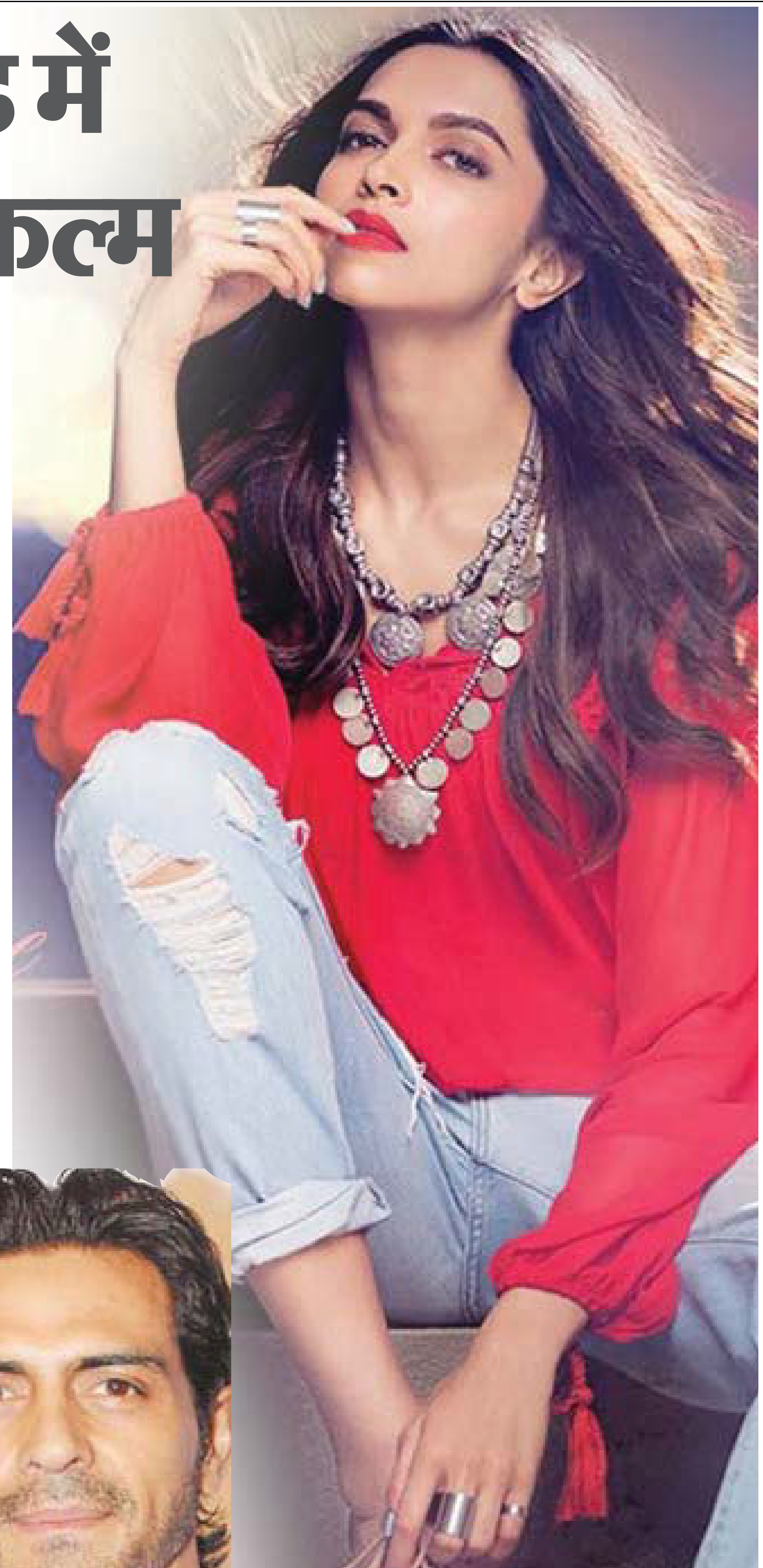

बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण आज अपना 35वां जन्मदिन मना रही है। इस समय दीपिका पादुकोण अपने पति रणवीर सिंह के साथ राजस्थान के रथंमभौर के जंगलों में नये साल का जश्म मना रही हैं। दीपिका पादुकोण ने साथ 2020 के अंत में 31 दिसंबर के दिन अचानक अपने सोशल मीडिया के सारे पोस्ट डिलीट कर दिए। 1 जनवरी 2021 के दिन उन्होंने एक ऑडियो डायरी शेयर करते हुए अपने फैंस को नये साल की बधाई दी।

साल 2020 दीपिका पादुकोण के लिए काफी ज्यादा बुरा साबित हुआ। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड में ड्रग्स एंगल का खुलासा हुआ जिसके बाद एक-एक करके कई बड़े नाम ड्रग्स केस से जुड़ते नजर आये जिसमें से एक दीपिका पादुकोण का था। एनसीबी ने दीपिका पादुकोण से पूछताछ की। दीपिका का नाम ड्रग्स केस से जुड़ने के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया गया।

आज दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की हाई पेड एक्ट्रेस में से एक हैं। अपनी मेहनत और लगन से दीपिका ने कम समय में बॉलीवुड में बड़ा नाम कमाया है। दीपिका की पहली फिल्म ओम शांति ओम थी। इस फिल्म में दीपिका पादुकोण ने शाहरुख खान के साथ काम किया था। दीपिका ने अपनी पहली फिल्म से ही शाहरुख खान को पछाड़ते हुए सारी लाइम लाइट बटोर ली। फिल्म में दीपिका के काम को बहुत पसंद किया गया। फिल्म ओम शांति ओम साल 2007 का सुपरहिट फिल्म थी।

आखिर फरहा खान को दीपिका पादुकोण कैसे मिली?

फिल्म ओम शांति ओम के लिए निर्देशक फरहा खान को दीपिका पादुकोण का नाम मलाइका अरोड़ा ने सजेस्ट किया था। दीपिका पादुकोण की मुलाकाल मलाइका से मॉडलिंग करने के दौरान हुई थी। तब मलाइका दीपिका से काफी इम्प्रेस हुई थी। फरहा खान को अपनी फिल्म के लिए नये चेहरे की तलाश थी ऐसे में दीपिका को फिल्म के लिए सलेक्ट कर लिया गया। फिल्म ओम शांति ओम सुपरहिट हुई।

फिर सवालों में घिरी उर्मिला मातोंडकर, चुनाव फंड से बचे पैसों का राहत काम में किया इस्तेमाल

अभिनेत्री से नेता बनीं उर्मिला मातोंडकर अब राजनीति में अपनी पकड़ बना रही है। महाराष्ट्र में उर्मिला मातोंडकर ने 2019 में कांग्रेस पार्टी का दामन थाम कर चुनाव लड़ा था जिसमें वह बुरी तरह हार गयी थी। कुछ समय कांग्रेस में रहने के बाद उर्मिला मातोंडकर ने 2020 में शिवसेना का हाथ थाम लिया। खबरों के मुताबिक कांग्रेस के पार्टी फंड से उर्मिला मातोंडकर को चुनाव लड़ने के लिए 50 लाख की धन राशि दी गयी थी। जिसमें से चुनाव के दौरान 30 लाख खर्च हुए थे। 20 लाख बाकी रह गये थे। उर्मिला मातोंडकर ने बचे हुए धन को कोरोना राहत में दान कर दिया था।

कुछ समय पहले कांग्रेस छोड़ने के बाद उर्मिला मातोंडकर शिवसेना में शामिल हो गईं। 2019 के लोकसभा चुनाव में, उर्मिला मातोंडकर मुंबई उत्तर से कांग्रेस की उम्मीदवार थीं, जो भाजपा के गोपाल शेट्टी से हार गईं थी। भारत निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार, उर्मिला मातोंडकर ने सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक की कांदिवली शाखा में चुनाव खर्च के लिए एक संयुक्त खाता खोला था। कांग्रेस महासचिव अशोक सुथराले संयुक्त खाताधारक थे।

ईसीआई के मानदंडों के अनुसार, प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा खर्च पर 70 लाख रुपये की कैप थी। महाराष्ट्र कांग्रेस ने अप्रैल 2019 में इस खाते में 50 लाख रुपये स्थानांतरित किए। खाता विवरण के अनुसार, 2019 में चुनावी मौसम के दौरान लगभग 30 लाख रुपये का उपयोग किया गया था और जुलाई 2020 तक शेष राशि के रूप में 20.4 लाख रुपये अभी भी खाते में शेष थे। जुलाई में, उर्मिला मातोंडकर ने बचे हुए पैसों को पार्टी को नहीं लौटाया बल्कि उन्होंने उन पैसों को मुख्यमंत्री राहत कोष में उसी खाते से 20 लाख रुपये का दान किया गया था।

इस बारे में बात करते हुए एमपीसीसी के कोषाध्यक्ष सुरेश शेट्टी ने कहा फ्रचुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को पैसा दिया जाता है। वह पैसा पार्टी का है। यदि किसी भी पैसे को छोड़ दिया जाता है, तो उसे पार्टी को वापस कर दिया जाना चाहिए। सामान्य व्यवहार के अनुसार, इस मामले में भी ऐसा ही होना चाहिए था।

उर्मिला मातोंडकर ने कहा कि यह दान राज्य कांग्रेस प्रमुख बालासाहेब थोरात की अनुमति से किया गया था। फ्रयह दान एमपीवी के अध्यक्ष थोरात साब की अनुमति के साथ कोविद -19 कार्य के लिए लॉकडाउन के बीच में एमवीए सरकार की ओर से किया गया था। कुछ कुख्यात लोग कहानी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने इसका इस्तेमाल महामारी में महाराष्ट्र के लोगों के कल्याण के लिए किया है।

क्या 'नेल पॉलिश' के लिए मिलेगा अर्जुन रामपाल को नेशनल अवॉर्ड? निर्देशक का बयान

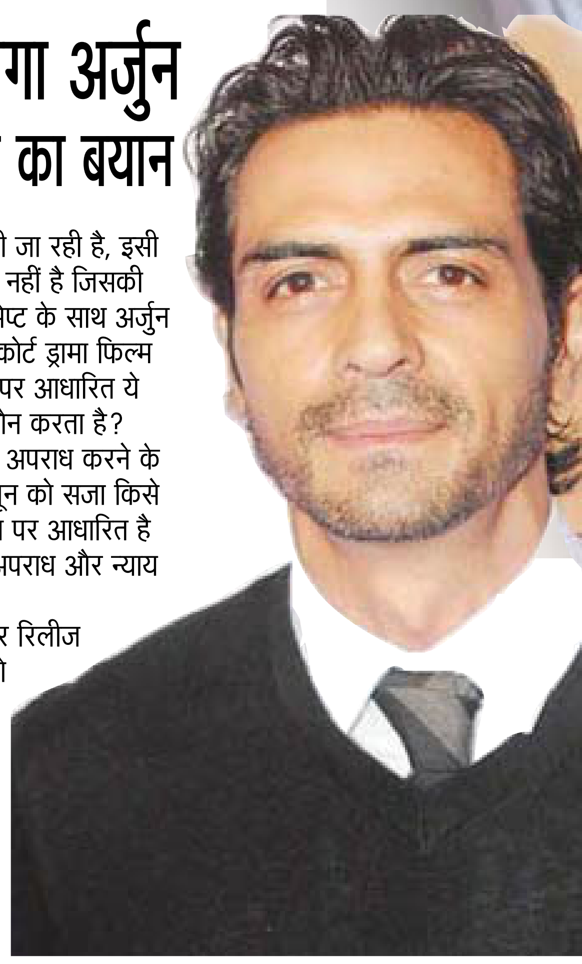

बॉलीवुड में कुछ सालों से बायोपिक और और रीमेक फिल्में ही बनायी जा रही है, इसी कारण लंबे समय से बॉलीवुड की कोई फिल्म इतनी इफेक्टिव भी नहीं है जिसकी क्रिटिक्स तारीफ कर सके। सालों बाद बॉलीवुड में एक नये कॉन्सेप्ट के साथ अर्जुन रामपाल और मानव कौल की फिल्म नेल पॉलिश रिलीज हुई है। कोर्ट ड्रामा फिल्म नेल पॉलिश की कहानी और कास्ट बेहद ही शानदार है। अपराध पर आधारित ये फिल्म आपको सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर अपराध कौन करता है?

क्या अपराध इंसान का शरीर करता है या उसका दिमाग? दिमाग ही अपराध करने के लिए निर्देश देता है शरीर तो बस निर्देश का पालन करता है। कानून को सजा किसे देनी चाहिए शरीर को या फिर दिमाग को? कुछ इसी मनोवितज्ञान पर आधारित है मानव कौल की फिल्म नेल पॉलिस। पहली बार बॉलीवुड में एक अपराध और न्याय पर आधारित ऐसी फिल्म रिलीज हुई है।

अर्जुन रामपाल की फिल्म नेल पॉलिस को आटीटी प्लेटफॉर्म ँद्ब्र5 पर रिलीज किया गया है। नेल पॉलिश में अर्जुन रामपाल और मानव कौल को उनके प्रदर्शन के लिए प्रशंसा मिल रही है। निर्देशक बग्स भार्गव कृष्णा का मानना है कि अभिनेताओं को नेल पॉलिश में उनके प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल सकता है। अर्जुन रामपाल कोर्ट रूम ड्रामा में एडवोकेट सिड जयसिंग की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। वह एक्स इंटेलीजेंस ऑफिसर मानव कौल (वीर सिंह) का केस लड़ रहे हैं। इसके अलावा आनंद तिवारी और रजित कपूर भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं।

राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर ने कॉमेडी फिल्म 'बधाई दो' की शूटिंग की शुरू

अभिनेता राजकुमार राव और अभिनेत्री भूमि पेडणेकर की अगली कॉमेडी फिल्म 'बधाई दो'की शूटिंग मंगलवार को शुरू हो गयी। यह फिल्म 'बधाई हो' की सीक्वल है। पेडणेकर ने इंस्टाग्राम पर उत्तराखंड के देहरादून में शूटिंग के पहले दिन की तस्वीरें साझा की है। अदाकारा ने लिखा है, ''नयी शुरुआत के लिए पूरी टीम को बधाई दो।'' 'बधाई दो' का निर्देशन हर्षवर्धन कुलकर्णी कर रहे हैं। उन्होंने इससे पहले फिल्म 'हंटर' (2015) का निर्देशन किया था। 'बधाई हो' की कहानी लिखने वाले सुमन अधिकारी और अक्षत घिल्डियाल ने ही इस फिल्म की भी कहानी लिखी है। 'बधाई हो' में आयुष्मान खुराना, सुरेखा सिकरी और सान्या ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी और इसका निर्देशन रवींद्रनाथ शर्मा ने किया था।

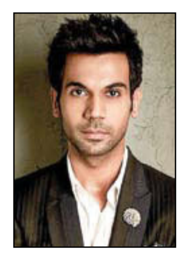

जैसलमेर में शुरू हुई अक्षय कुमार अभिनीत 'बच्चन पांडे' की शूटिंग

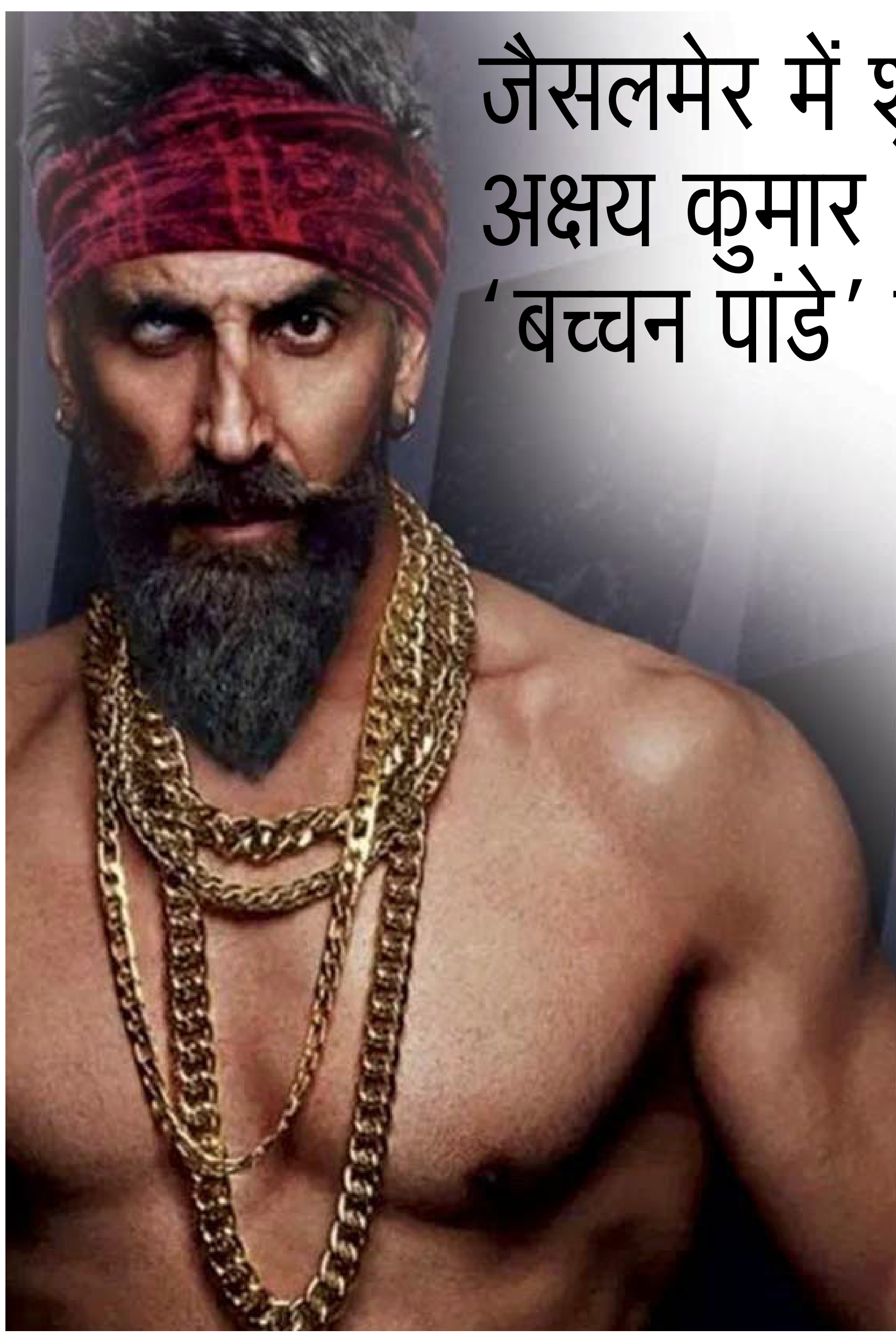

अभिनेता अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म ''बच्चन पांडे'' की शूटिंग बुधवार को जैसलमेर में शुरू हो गयी। फिल्मकारों ने यह घोषणा की। निर्माता साजिद नाडियाडवाला फिल्म के कलाकारों एवं अन्य सहयोगियों के साथ अपनी आगामी एक्शन-कॉमेडी फिल्म की शूटिंग के लिए पिछले सप्ताह शहर पहुंचे। फिल्म में कृति सैनन, पंकज त्रिपाठी और अरशद वारसी भी हैं। 'नाडियाडवाला ग्रैंडसन' ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया, ''मुहुर्त शॉट के साथ साजिद नाडियाडवाला की फिल्म 'बच्चन पांडे' की शूटिंग शुरू हो गयी।''

'बच्चन पांडे' का निर्देशन 'हाउसफुल 4' के निर्देशक फरहाद शामजी कर रहे हैं। फिल्म में अक्षय कुमार एक ऐसे गैंगस्टर की भूमिका निभा रहे हैं जो अभिनेता बनना चाहता है। कृति सैनन फिल्म में पत्रकार बनी हैं जो निर्देशक बनना चाहती हैं और अरशद वारसी एक संघर्षरत अभिनेता बने हैं। फिल्मकारों ने फिल्म के अन्य कलाकारों की घोषणा नहीं की है। 'बच्चन पांडे' इस साल रिलीज होने वाली है।

फिल्म 'सुल्तान' के निर्देशक अली अब्बास जफर ने रचाई शादी

फिल्मकार अली अब्बास जफर शादी के बंधन में बंध गए हैं। अब्बास ने अपनी पत्नी एलिशिया जफर के साथ इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा, '' 1400 साल पहले, इमाम अली ने फातिमा अल-जहरा से कहा था कि तुम्हारा चेहरा देखते ही मेरे सारे दुख और दर्द गायब हो जाते हैं। मुझे तुम्हें देखकर ऐसा ही महसूस होता है।''

फिल्म 'सुल्तान' के निर्देशक ने कुछ दिन पहले भी एक तस्वीर साझा की थी, जिसमें दोनों ने एक-दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। तस्वीर साझा करते हुए उन्होंने लिखा था, ''बिस्मिल्लाह''।

टाइगर श्रॉफ के दूसरे सॉन्ग 'कैसनोवा' का फर्स्ट लुक रिलीज

अभिनेता टाइगर श्रॉफ ने 'कासानोवा' गाने का पहला लुक बुधवार को जारी किया। पिछले साल अभिनेता ने गायन की दुनिया में 'अनबिलिवेबल' से दस्तक दी थी। श्रॉफ ने ट्विटर पर 'कासानोवा' का 15 सेकेंड का टीजर पोस्ट करते हुए उत्साहवर्धन के लिए अपने प्रशंसकों का शुक्रिया अदा किया।

अभिनेता ने लिखा कि वह दूसरे गाने का पहला लुक साझा करते हुए उत्साहित हैं। श्रॉफ विकास बहल की फिल्म 'गणपत' में नजर आएंगे, जिसकी शूटिंग इस साल शुरू होने की संभावना है।

संक्षिप्त समाचार

डकार रैली के दौरान भारतीय राइडर संतोष गंभीर रूप से घायल

नई दिल्ली, (एजेंसी)। सऊदी अरब में जारी डकार रैली में भाग ले रही भारतीय रेसर सीएस संतोष हादसे में गंभीर रुप से घायल होन के बाद कोमा में हैं। संतोष को एयर एंबुलेंस के जरिये रियाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी रैलियों में से एक में 37 साल के संतोष हीरो मोटोस्पार्ट्स टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। संतोष की बाइक दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण उन्हें 24 घंटे निरीक्षण में रखा गया है। हीरो मोटोस्पोर्ट्स ने एक ट्वीट में कहा, दुर्भाग्यपूर्ण घटना में संतोष को डकार रैली 2021 के चौथे चरण में आज हादसे का सामना करना पड़ा। उन्हें रियाद के अस्पताल में ले जाया गया है। शुरूआती आकलन में उनकी स्थिति स्थिर लग रही है। हमें उनके जल्द उबरने की उम्मीद है।

दर्शकों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य : हेजार्ड

सिडनी, (एजेंसी)। न्यू साउथ वेल्स के स्वास्थ्य मंत्री ब्रैड हेजार्ड ने कहा है कि सिडनी क्रिकेट मैदान (एससीजी) में आने वाले सभी दर्शकों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है। इसलिए सभी इस नियम का पालन करें।। सिडनी में कोविड-19 मामलों के बढ़ने के बाद भी लगभग 10,000 प्रशंसकों को टेस्ट देखने की अनुमति मिली है। वहीं इससे पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न क्रिकेट मैदान पर खेले गये बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच दौरान एक दर्शक के कोविड-19 की चपेट में आने बाद अब मास्क को लेकर कोई ढ़ील नहीं देने का फैसला किया गया है। हेजार्ड ने कहा कि क्रिकेट के लिए कोविड-19 के असर वाला दिन और इसका मतलब है कि आपको मास्का लगाना ही होगा। आप मास्क तभी हटा सकते है जब आप कुछ खा रहे हों। उन्होंने कहा कि हम वास्तव में क्रिकेट से प्यार करते हैं पर इस मौके पर हम यह नहीं चाहते कि प्यार के कारण कोरोना वायरस की चपेट में आ जाए। कुछ उपनगरीय इलाके को उस सूची में डाला गया है जहां कोरोना वायरस का प्रभाव है और वहां के प्रशंसकों को स्टेडियम आने की अनुमति नहीं होगी।

मैनचेस्टर सिटी इंग्लिश लीग के खिताबी मुकाबले में पहुंची

लंदन, (एजेंसी)। मैनचेस्टर सिटी इंग्लिश फुटबॉल लीग के खिताबी मुकाबले में पहुंच गयी है। सिटी ने अपने परंपरागत प्रतिद्वंद्वी मैनचेस्टर यूनाईटेड को 2-1 से हराकर फाइनल में स्थान बनाया। इस मैच में सिटी की ओर से दूसरे हॉफ में जॉन स्टोन्स और फर्नाडिन्हो ने गोल किये। अब फाइनल में उसका मुकाबला टोटैनहैम क्लब से होगा। फाइनल मैच 25 अप्रैल को वेम्बले स्टेडियम में खेला जाएगा। फाइनल को सिटी के मैनेजर पेप गार्डियलो का अपने प्रतिद्वंद्वी कोच जोस मारिन्हो से एक और मुकाबला माना जा रहा है। इसके साथ ही मारिन्हो टोटैनहैम का पिछले 13 साल से ट्राफी नहीं जीतने का इंतजार समाप्त करना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर सिटी भी लगातार चौथा और पिछले आठ सत्रों में छठा खिताब जीतने का प्रयास करेगा।

इंटर मिलान का खिताब जीतने का सपना टूटा

रोम, (एजेंसी)। फुटबॉल क्लब इंटर मिलान का एक दशक से अधिक समय में पहला सिरी ए फुटबॉल खिताब जीतने का सपना टूट गया है। इंटर मिलान को सेम्पडोरिया के हाथों 1-2 से हार झेलनी पड़ी है। इस जीत साथ ही सेम्पडोरिया ने इंटर मिलान के लगातार आठ जीत के अभियान पर भी विराम लगा दिया। इस मैच में अहम बात यह रही की सेम्पडोरिया की ओर से दागे गये दोनों गोल इंटर मिलान के पूर्व खिलाड़ियों ने ही किये हैं। एंटोनियो केंड्रेवा ने पेनल्टी पर गोल दागकर सेम्पडोरिया को 1-0 की बढ़त दिलाई। वहीं इसके बाद केइटा बाल्डे डियाओ ने मध्यांतर से पहले एक गोल कर टीम को 2-0 से बढ़त दिला दी। स्टीफन डि व्रिज ने 65वें मिनट में हैडर से गोल दागकर इंटर को वापसी दिलाने का प्रयास किया पर वह सफल नहीं हो पाये।

मेसी के दो गोलों से बार्सिलोना जीता

बार्सिलोना, (एजेंसी)। स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी के दो शानदार गोलों की सहायता से बार्सिलोना ने स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लिगा में एथलेटिक बिलबाओ को 3-2 से हरा दिया। बिलबाओ को इस मैच की शुरूआत में ही इनाकी विलियम्स ने गोल कर बढ़त दिला दी थी पर इसके बाद बार्सिलोना की तरफ से पेड्रो गोंजालेज ने 14वें मिनट में गोल कर स्कोर 1-1 से बराबरी पर ला दिया। इसके बाद मेसी ने 38वें और 62वें मिनट में गोल दागकर जीत दिलाने के साथ ही बार्सिलोना को अंकतालिका में तीसरे स्थान पर पहुंचाया। बार्सिलोना के अब 17 मैचों में 31 अंक हो गए हैं। वहीं एटलेटिको ला लिगा तालिका में शीर्ष पर है पर कोपा डेल रे प्रतियोगिता में उसे कोनेली से 1-0 से हार का सामना करना पड़ा है। एटलेटिको के ला लिगा में अभी 15 मैचों में 38 अंक हैं और वह शीर्ष पर बना हुआ है। उसके बाद रीयाल मैड्रिड के 17 मैचों में 36 अंक है वहीं 31 अंको के कसाथ बार्सिलोना तीसरे नंबर पर है।

सिडनी में तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वार्नर को आउट करने के बाद उत्साहित टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मो सिराज।

लाबुशेन और पोकोवस्की के अर्धशतकों से ऑस्ट्रेलिया संभला, 166/2

सिडनी, (एजेंसी)। अपना पहला ही मैच खेल रहे युवा बल्लेबाज विल पोकोवस्की और मार्नस लाबुशेन के अर्धशतकों की सहायता से मेजबान ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भारत के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन अपनी पहली पारी में 2 विकेट के नुकसान पर 166 रन बनाये। दिन का खेल समाप्त होने के समय अनुभवी बल्लेबाज स्टीव स्मिथ 31 और लाबुशेन 67 रनों पर खेल रहे थे। इस मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी मेजबान ऑस्ट्रेलियाई टीम की शुरूआत धीमी रही। लाबुशेन के उतरने के बाद हालांकि रन गति में तेजी आई। पहले दिन के खेल का आकर्षण पदार्पण कर रहे बल्लेबाज पोकोवस्की की बल्लेबाजी रही। पोकोवस्की नवदीप सैनी की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हुए। पोकोवस्की ने 110 गेंदें खेलते हुए 4 चौकों की मदद से 62 रन बनाए। इसके साथ ही लाबुशेन ने भी 9वां अर्धशतक लगाया और टीम की रनगति बनाये रखी। आज सुबह खेल शुरू होने के कुछ समय बाद ही बारिश के कारण खेल रोकना पड़ा। उस समय तक आस्ट्रेलिया ने 7.1 ओवर में एक विकेट पर 21 रन बनाए थे। अनुभवी सलामी बल्लेबाज ओपनर डेविड वार्नर की वापसी अच्छी नहीं रही और वह 8 गेंदें खेलते हुए केवल 5 रन बनाकर सिराज का शिकार बने। इस मैच में भारत ने उमेश यादव की जगह नवदीप सैनी जबकि मयंक अग्रवाल की जगह रोहित शर्मा का उतरा है। वहीं मेजबान टीम ने पुकोवस्की को शामिल किया।

भारत के पास सीरीज जीतने का अच्छा अवसर : गंभीर

नई दिल्ली, (एजेंसी)। पूर्व भारतीय बल्लेबाज गौतम गंभीर ने कहा है भारतीय टीम के बापस बॉर्डर गावस्कर ट्राफी जीतने का अच्छा अवसर है। गंभीर के अनुसार इसका कारण ऑस्ट्रेलिया का बल्लेबाजी लाइन-अप का कमजोर होना है।

गंभीर ने कहा, हमारे पास ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीतने का अच्छा मौका है। अगर आप दुनिया के शीर्ष चार बल्लेबाजी क्रम को देखें, मुझे लगता है कि इस बार यह सबसे कमजोर बैटिंग लाइन अप है। ऑस्ट्रेलिया से बेहतर इंग्लैंड है। न्यूजीलैंड भी ऑस्ट्रेलिया से बेहतर और भारत तो ऑस्ट्रेलिया से कहीं ज्यादा बेहतर है।उन्होंने आगे कहा, मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह का बल्लेबाजी लाइन अप कभी नहीं देखा है। यह काफी आलोचनात्मक है जबकि वह भारत के मुख्य गेंदबाजी आक्रमण को नहीं खेल रहे हैं।

विराट कोहली ने जो किया, वो अन्य कोई कप्तान नहीं कर सकता बोल ट्रोल हुए रवि शास्त्री

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही श्रंखला का तीसरा टेस्ट मैच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (एससीजी) में खेला जा रहा है। सिडनी टेस्ट से पहले भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच रवि शास्त्री ने एक बयान दिया है, जिसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है। शास्त्री ने एक किताब के लॉन्च के मौके पर कहा कि विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया को उसके घर और बाहर हराने की जो उपलब्धि हासिल की है, वह किसी भारतीय कप्तान के हासिल कर पाना काफी लंबे समय तक मुश्किल होगा। शास्त्री के इस बयान पर फैन्स अपने रिएक्शन दे रहे हैं।

एक रिपोर्ट के मुताबिक, कोच रवि शास्त्री ने पिछले 71 साल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई टेस्ट सीरीज पर अधारित एक किताब लॉन्च के मौके पर विराट कोहली की तारीफों के पुल बांधे। शास्त्री ने कहा, 71 साल के दिल टूटने के बाद ऑस्ट्रेलिया में भारत की पहली सीरीज जीतने में मिली संतुष्टि बहुत ज्यादा थी। मैं विराट की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घर और बाहर दोनों में जीत की उपलब्धि को बहुत लंबे समय तक किसी अन्य भारतीय कप्तान द्वारा दोहराता नहीं देख रहा हूं।

बता दें कि विराट कोहली की कप्तानी में 2018-19 में 71 साल बाद भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में टेस्ट सीरीज में 2-1 से हराया था। शास्त्री उस वक्त भी टीम इंडिया के कोच थे। इसी के साथ विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया को पहली बार उसके घर में टेस्ट सीरीज में हराने वाले पहले एशियाई कप्तान बने थे।

कोच रवि शास्त्री ने आगे कहा, ऑस्ट्रेलिया में सफलता से लेकर सबसे अच्छी बात यह है कि यह आसानी से नहीं आती है। एक पेशेवर खिलाड़ी के रूप में, आप जानते हैं कि जब आप कठिन तरीके से जीतते हैं, तो आप सम्मान का आदेश देते हैं। भारतीय टीम ने (21 वीं) शताब्दी के बाद से ऑस्ट्रेलिया में शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन तब उनके पास तेज गेंदबाजी में गहराई नहीं थी। इसलिए यह वाली भारतीय टीम ने सम्मान कमाया है।

बता दें कि इससे पहले मेलबर्न टेस्ट जीतने पर अजिंक्य रहाणे की तारीफ करते हुए कोच रवि शास्त्री ने अजिंक्य रहाणे को चालाक कप्तान बताते हुए कहा था कि उनका शांत स्वभाव विराट कोहली से बिल्कुल उलट है, जो हमेशा जोश और जुनून से भरे रहते हैं। शास्त्री ने मेलबर्न में मिली 8 विकेट की जीत के बाद कहा था, वह काफी चालाक कप्तान हैं और खेल को बखूबी पढ़ते हैं। उनके शांत स्वभाव से नए खिलाड़ियों और गेंदबाजों को मदद मिलती है। उमेश के नहीं होने के बावजूद वह परेशान नहीं हुए।

उन्होंने आगे कहा, रहाणे जब बल्लेबाजी के लिए उतरे तो हमारे दो विकेट 60 रन पर गिर चुके थे। इसके बाद उन्होंने छह घंटे तक बल्लेबाजी की। यह आसान नहीं था। उन्होंने अद्भुत धैर्य दिखाया। उनकी यह पारी मैच का टर्निंग प्वॉइंट थी।

राष्ट्रीय गान के दौरान रोने लगे सिराज, जाफर ने शेयर किया

मुम्बई, (एजेंसी)। ऑस्ट्रेलिया के साथ तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के शुरू होने के पहले टीम इंडिया के युवा तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज भावुक होकर रोने लगे। अपने करियर का दूसरा टेस्ट मैच खेल रहे सिराज की रोते हुए की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ट्विटर पर वायरल हो रही इस तस्वीर में सिराज रोते हुए और अपनी आंखें साफ करते हुए दिखाई दिए। सिराज की इस तस्वीर को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) के साथ ही भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज क्रिकेटर वसीम जाफर ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। इस तस्वीर को शेयर करते हुए जाफर ने लिखा, यहां तक कि अगर आपका उत्साह बढ़ाने के लिए बहुत कम या कोई भीड़ ना हो तो भी भारत के लिए खेलने से बेहतर कोई प्रेरणा नहीं है। एक लीजेंड ने एक बार कहा था, आप लोगों के लिए नहीं खेलते, आप देश के लिए खेलते हैं।

जाफर द्वारा शेयर की गई सिराज की इस तस्वीर और उनके लिए लिखी गई इन बातों को लोगों ने काफी सराहा है और इस ट्वीट को 25 हजार से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है। वहीं 2 हजार से ज्यादा लोगों ने इस फोटो को रीट्विट भी किया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू से पहले सिराज के पिता की मौत हो गई थी और वह आखिरी बार अपने पिता को देख भी नहीं सके थे। तब बीसीसीआई ने सिराज से वापस जाने के लिए कहा था पर पिता के देश की ओर से खेलने के सपने को पूरा करने के लिए सिराज ऑस्ट्रेलिया में ही रूके रहे । ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में खेले गए दूसरे टेस्ट और अपने डेब्यू मैच में सिराज ने शानदार गेंदबाजी की थी।

इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर जॉन लुईस बांग्लादेश टीम के बल्लेबाजी कोच बने

ढाका, (एजेंसी)। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर जॉन लुईस बांग्लादेश टीम के बल्लेबाजी कोच बनाए गए हैं। बीसीबी ने यह जानकारी दी है। बांग्लादेश ने वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली आगामी दो द्विपक्षीय श्रृंखलाओं के लिए जॉन लुईस को बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने यह जानकारी दी। श्रीलंका क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच रह चुके इंग्लैंड के 50 साल के लुईस नील मैकेंजी की जगह लेंगे जिन्होंने पारिवारिक कारणों से पिछले साल अगस्त में पद छोड़ दिया। बीसीबी के क्रिकेट संचालन चेयरमैन अकरम खान ने कहा, वह (लुईस) एक या दो दिन में आ रहा है, जिसके बाद हम निजी रूप से उनके साथ बात करेंगे। हमारी सूची में तीन या चार कोच थे लेकिन हमने उनके अनुभव पर गौर किया। छांटे गए उम्मीदवारों के बारे में आपस में बात करने के बाद, जिसमें मुख्य कोच भी शामिल थे, हमने उन्हें चुनने का फैसला किया। महामारी के कारण कोई भी दीर्घकालीन अनुबंध नहीं करना चाहता। हम कुछ श्रृंखलाओं में उनका प्रदर्शन देखेंगे और फिर देखेंगे कि हम उन्हें लंबे समय तक रख सकते हैं या नहीं। लगभग दो दशक के करियर में 16 प्रथम श्रेणी शतक जड़ने वाले लुईस की अगुआई में डरहम ने 2013 से 2016 के बीच तीन खिताब जीते। बांग्लादेश 20 जनवरी से 15 फरवरी के बीच वेस्टइंडीज की मेजबान करेगा। दोनों देशों के बीच तीन एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय और दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला होगी जिसके बाद टीम मार्च में न्यूजीलैंड दौरे पर जाएगी जहां उसे तीन एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय और तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय खेलने हैं।

मैनचेस्टर में इंग्लिश लीग कप फुटबॉल में गोल दागते हुए फर्नाडिंहों।

हवाई में चैम्पियंस गोल्फ मुकाबले में भाग लेते हुए डस्टिन जोनसन।

बीडब्ल्यूएफ पर भड़की साइना, ट्रेनर और कोच से मिलने पर रोक हटायें

बैंकॉक, (एजेंसी)। भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने थाइलैंड में होने वाले आगामी टूनार्मेंटों से पहले (ट्रेनर) और फिजियो से मिलने की अनुमति नहीं दिये जाने पर नाराजगी व्यक्त की है। साइना ने कहा है कि कोविड-19 से जुड़े सभी टेस्ट में निगेटिव आने के बाद भी बैडमिंटन महासंघ (बीडब्ल्यूएफ) का इस प्रकार का रवैया हैरान करने वाला है। साइना ने कहा है कि उन्हें इस कारण अभ्यास में परेशानी आ रही है। साइना ने बीडब्ल्यूएफ द्वारा कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत लगाए गए प्रतिबंधों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कई ट्वीट किए। साइना ने ट्वीट किया, जांच में सभी के नेगेटिव आने के बाद भी फिजियो और प्रशिक्षक हम से नहीं मिल सकते। ऐसे में हम चार सप्ताह तक खुद को फिट कैसे रखेंगे। इसलिए इस मामले का हल निकालें। साइन के अनुसार ओलिंपिक क्वॉलिफिकेशन के लिए उनके पास मार्च तक का समय है, ऐसे में प्रशिक्षण की कमी से उनके प्रदर्शन पर असर पड़ सकता है। विश्व की इस पूर्व नंबर एक खिलाड़ी ने इस मामले को लेकर बीडब्ल्यूएफ से संपर्क किया है पर उन्हें कोई जवाब नहीं मिला है। साइना ने कहा, पूरी टीम को अभ्यास के लिए सिर्फ एक घंटे का समय मिल रहा है। एक ही समय पर जिम करना है। ओलिंपिक क्वॉलिफिकेशन के लिए मार्च तक का समय है ऐसे में फिटनेस के लिए यह अच्छा नहीं है। गौरतलब है कि भारत का पूरा दल बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर फाइनल्स के दो सुपर 1000 प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आजकल थाइलैंड में है।

आईपीएल से लाभ मिला : राजा

चेन्नई , (एजेंसी)। यूएई के कप्तान अहमद राजा ने कहा है इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में विराट कोहली जैसे शीर्ष स्तर के खिलाड़ियों के साथ अभ्यास से हमें लाभ हुआ है। राजा के अनुसार इसका लाभ उनकी टीम को अबुधाबी में होने वाली एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला में आयरलैंड से मुकाबले में मिलेगा। राजा और स्पिनर कार्तिक मयप्पन ने पिछले साल सितंबर में यूएई में आईपीएल के दौरान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के साथ अभ्यास किया था थी जबकि तेज गेंदबाज जहूर खान ने मुंबई इंडियन्स टीम के साथ समय बिताया था।

राजा ने आठ जनवरी से शुरू हो रही श्रृंखला से पहले कहा, आईपीएल बहुत बड़ा टूनार्मेंट था। विराट कोहली, एबी डिविलियर्स जैसे बल्लेबाजों के साथ अभ्यास करके जो अनुभव मिला और उन्हें गेंदबाजी करना शानदार था। हमने महसूस किया कि जब हम आईपीएल से गए तो हमें काफी फायदा हुआ। उन्होंने कहा, इसे शब्दों में बताना मुश्किल है लेकिन आप अलग महसूस करना शुरू कर देते हैं और आपका रवैया भी बदल जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस दौरान हमने जो सीखा उसे इस श्रृंखला में दिखा पाएंगे। वहीं दूसरी ओर आयरलैंड के कप्तान एंड्रयू बॉलबिर्नी ने उम्मीद जताई कि उनके देश के खिलाड़ियों को भी आईपीएल अनुबंध मिलेंगे लेकिन उन्होंने कहा कि इस लुभावनी लीग में खेलने के लिए उन्हें लगातार अच्छा प्रदर्शन करना होगा।उन्होंने कहा, आईपीएल दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टी20 लीग है जिसमें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी खेलते हैं। आईपीएल में आपको दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों, सर्वश्रेष्ठ कोचों से बात करने का मौका मिलता है। और खिलाड़ियों को जो अनुभव मिलता है वह बेजोड़ है। आयरलैंड के किसी खिलाड़ी का आईपीएल फ्रेंचाइजी के साथ अनुबंध नहीं है।

संक्षिप्त समाचार

डकार रैली के दौरान भारतीय राइडर संतोष गंभीर रूप से घायल

नई दिल्ली, (एजेंसी)। सऊदी अरब में जारी डकार रैली में भाग ले रही भारतीय रेसर सीएस संतोष हादसे में गंभीर रुप से घायल होन के बाद कोमा में हैं। संतोष को एयर एंबुलेंस के जरिये रियाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी रैलियों में से एक में 37 साल के संतोष हीरो मोटोस्पाट्र्स टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। संतोष की बाइक दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण उन्हें 24 घंटे निरीक्षण में रखा गया है। हीरो मोटोस्पोर्ट्स ने एक ट्वीट में कहा, दुर्भाग्यपूर्ण घटना में संतोष को डकार रैली 2021 के चौथे चरण में आज हादसे का सामना करना पड़ा। उन्हें रियाद के अस्पताल में ले जाया गया है। शुरूआती आकलन में उनकी स्थिति स्थिर लग रही है। हमें उनके जल्द उबरने की उम्मीद है।

दर्शकों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य : हेजार्ड

सिडनी, (एजेंसी)। न्यू साउथ वेल्स के स्वास्थ्य मंत्री ब्रैड हेजार्ड ने कहा है कि सिडनी क्रिकेट मैदान (एससीजी) में आने वाले सभी दर्शकों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है। इसलिए सभी इस नियम का पालन करें।। सिडनी में कोविड-19 मामलों के बढ़ने के बाद भी लगभग 10,000 प्रशंसकों को टेस्ट देखने की अनुमति मिली है। वहीं इससे पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न क्रिकेट मैदान पर खेले गये बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच दौरान एक दर्शक के कोविड-19 की चपेट में आने बाद अब मास्क को लेकर कोई ढ़ील नहीं देने का फैसला किया गया है। हेजार्ड ने कहा कि क्रिकेट के लिए कोविड-19 के असर वाला दिन और इसका मतलब है कि आपको मास्का लगाना ही होगा। आप मास्क तभी हटा सकते है जब आप कुछ खा रहे हों। उन्होंने कहा कि हम वास्तव में क्रिकेट से प्यार करते हैं पर इस मौके पर हम यह नहीं चाहते कि प्यार के कारण कोरोना वायरस की चपेट में आ जाए। कुछ उपनगरीय इलाके को उस सूची में डाला गया है जहां कोरोना वायरस का प्रभाव है और वहां के प्रशंसकों को स्टेडियम आने की अनुमति नहीं होगी।

मैनचेस्टर सिटी इंग्लिश लीग के खिताबी मुकाबले में पहुंची

लंदन, (एजेंसी)। मैनचेस्टर सिटी इंग्लिश फुटबॉल लीग के खिताबी मुकाबले में पहुंच गयी है। सिटी ने अपने परंपरागत प्रतिद्वंद्वी मैनचेस्टर यूनाईटेड को 2-1 से हराकर फाइनल में स्थान बनाया। इस मैच में सिटी की ओर से दूसरे हॉफ में जॉन स्टोन्स और फर्नांडिन्हो ने गोल किये। अब फाइनल में उसका मुकाबला टोटैनहैम क्लब से होगा। फाइनल मैच 25 अप्रैल को वेम्बले स्टेडियम में खेला जाएगा। फाइनल को सिटी के मैनेजर पेप गार्डियलो का अपने प्रतिद्वंद्वी कोच जोस मारिन्हो से एक और मुकाबला माना जा रहा है। इसके साथ ही मारिन्हो टोटैनहैम का पिछले 13 साल से ट्राफी नहीं जीतने का इंतजार समाप्त करना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर सिटी भी लगातार चौथा और पिछले आठ सत्रों में छठा खिताब जीतने का प्रयास करेगा।

इंटर मिलान का खिताब जीतने का सपना टूटा

रोम, (एजेंसी)। फुटबॉल क्लब इंटर मिलान का एक दशक से अधिक समय में पहला सिरी ए फुटबॉल खिताब जीतने का सपना टूट गया है। इंटर मिलान को सेम्पडोरिया के हाथों 1-2 से हार झेलनी पड़ी है। इस जीत साथ ही सेम्पडोरिया ने इंटर मिलान के लगातार आठ जीत के अभियान पर भी विराम लगा दिया। इस मैच में अहम बात यह रही की सेम्पडोरिया की ओर से दागे गये दोनों गोल इंटर मिलान के पूर्व खिलाड़ियों ने ही किये हैं। एंटोनियो केंड्रेवा ने पेनल्टी पर गोल दागकर सेम्पडोरिया को 1-0 की बढ़त दिलाई। वहीं इसके बाद केइटा बाल्डे डियाओ ने मध्यांतर से पहले एक गोल कर टीम को 2-0 से बढ़त दिला दी। स्टीफन डि व्रिज ने 65वें मिनट में हैडर से गोल दागकर इंटर को वापसी दिलाने का प्रयास किया पर वह सफल नहीं हो पाये।

मेसी के दो गोलों से बार्सिलोना जीता

बार्सिलोना, (एजेंसी)। स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी के दो शानदार गोलों की सहायता से बार्सिलोना ने स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लिगा में एथलेटिक बिलबाओ को 3-2 से हरा दिया। बिलबाओ को इस मैच की शुरूआत में ही इनाकी विलियम्स ने गोल कर बढ़त दिला दी थी पर इसके बाद बार्सिलोना की तरफ से पेड्रो गोंजालेज ने 14वें मिनट में गोल कर स्कोर 1-1 से बराबरी पर ला दिया। इसके बाद मेसी ने 38वें और 62वें मिनट में गोल दागकर जीत दिलाने के साथ ही बार्सिलोना को अंकतालिका में तीसरे स्थान पर पहुंचाया। बार्सिलोना के अब 17 मैचों में 31 अंक हो गए हैं। वहीं एटलेटिको ला लिगा तालिका में शीर्ष पर है पर कोपा डेल रे प्रतियोगिता में उसे कोनेली से 1-0 से हार का सामना करना पड़ा है। एटलेटिको के ला लिगा में अभी 15 मैचों में 38 अंक हैं और वह शीर्ष पर बना हुआ है। उसके बाद रीयाल मैड्रिड के 17 मैचों में 36 अंक है वहीं 31 अंको के कसाथ बार्सिलोना तीसरे नंबर पर है।

सिडनी में तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वार्नर को आउट करने के बाद उत्साहित टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मो सिराज।

लाबुशेन और पोकोवस्की के अर्धशतकों से ऑस्ट्रेलिया संभला, 166/2

सिडनी, (एजेंसी)। अपना पहला ही मैच खेल रहे युवा बल्लेबाज विल पोकोवस्की और मार्नस लाबुशेन के अर्धशतकों की सहायता से मेजबान ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भारत के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन अपनी पहली पारी में 2 विकेट के नुकसान पर 166 रन बनाये। दिन का खेल समाप्त होने के समय अनुभवी बल्लेबाज स्टीव स्मिथ 31 और लाबुशेन 67 रनों पर खेल रहे थे। इस मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी मेजबान ऑस्ट्रेलियाई टीम की शुरूआत धीमी रही। लाबुशेन के उतरने के बाद हालांकि रन गति में तेजी आई। पहले दिन के खेल का आकर्षण पदार्पण कर रहे बल्लेबाज पोकोवस्की की बल्लेबाजी रही। पोकोवस्की नवदीप सैनी की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हुए। पोकोवस्की ने 110 गेंदें खेलते हुए 4 चौकों की मदद से 62 रन बनाए। इसके साथ ही लाबुशेन ने भी 9वां अर्धशतक लगाया और टीम की रनगति बनाये रखी। आज सुबह खेल शुरू होने के कुछ समय बाद ही बारिश के कारण खेल रोकना पड़ा। उस समय तक आस्ट्रेलिया ने 7.1 ओवर में एक विकेट पर 21 रन बनाए थे। अनुभवी सलामी बल्लेबाज ओपनर डेविड वार्नर की वापसी अच्छी नहीं रही और वह 8 गेंदें खेलते हुए केवल 5 रन बनाकर सिराज का शिकार बने। इस मैच में भारत ने उमेश यादव की जगह नवदीप सैनी जबकि मयंक अग्रवाल की जगह रोहित शर्मा का उतरा है। वहीं मेजबान टीम ने पुकोवस्की को शामिल किया।

भारत के पास सीरीज जीतने का अच्छा अवसर : गंभीर

नई दिल्ली, (एजेंसी)। पूर्व भारतीय बल्लेबाज गौतम गंभीर ने कहा है भारतीय टीम के बापस बॉर्डर गावस्कर ट्राफी जीतने का अच्छा अवसर है। गंभीर के अनुसार इसका कारण ऑस्ट्रेलिया का बल्लेबाजी लाइन-अप का कमजोर होना है।

गंभीर ने कहा, हमारे पास ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीतने का अच्छा मौका है। अगर आप दुनिया के शीर्ष चार बल्लेबाजी क्रम को देखें, मुझे लगता है कि इस बार यह सबसे कमजोर बैटिंग लाइन अप है। ऑस्ट्रेलिया से बेहतर इंग्लैंड है। न्यूजीलैंड भी ऑस्ट्रेलिया से बेहतर और भारत तो ऑस्ट्रेलिया से कहीं ज्यादा बेहतर है।उन्होंने आगे कहा, मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह का बल्लेबाजी लाइन अप कभी नहीं देखा है। यह काफी आलोचनात्मक है जबकि वह भारत के मुख्य गेंदबाजी आक्रमण को नहीं खेल रहे हैं।

विराट कोहली ने जो किया, वो अन्य कोई कप्तान नहीं कर सकता बोल ट्रोल हुए रवि शास्त्री

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही श्रंखला का तीसरा टेस्ट मैच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (एससीजी) में खेला जा रहा है। सिडनी टेस्ट से पहले भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच रवि शास्त्री ने एक बयान दिया है, जिसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है। शास्त्री ने एक किताब के लॉन्च के मौके पर कहा कि विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया को उसके घर और बाहर हराने की जो उपलब्धि हासिल की है, वह किसी भारतीय कप्तान के हासिल कर पाना काफी लंबे समय तक मुश्किल होगा। शास्त्री के इस बयान पर फैन्स अपने रिएक्शन दे रहे हैं।

एक रिपोर्ट के मुताबिक, कोच रवि शास्त्री ने पिछले 71 साल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई टेस्ट सीरीज पर अधारित एक किताब लॉन्च के मौके पर विराट कोहली की तारीफों के पुल बांधे। शास्त्री ने कहा, 71 साल के दिल टूटने के बाद ऑस्ट्रेलिया में भारत की पहली सीरिज जीतने में मिली संतुष्टि बहुत ज्यादा थी। मैं विराट की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घर और बाहर दोनों में जीत की उपलब्धि को बहुत लंबे समय तक किसी अन्य भारतीय कप्तान द्वारा दोहराता नहीं देख रहा हूं।

बता दें कि विराट कोहली की कप्तानी में 2018-19 में 71 साल बाद भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में टेस्ट सीरीज में 2-1 से हराया था। शास्त्री उस वक्त भी टीम इंडिया के कोच थे। इसी के साथ विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया को पहली बार उसके घर में टेस्ट सीरीज में हराने वाले पहले एशियाई कप्तान बने थे।

कोच रवि शास्त्री ने आगे कहा, ऑस्ट्रेलिया में सफलता से लेकर सबसे अच्छी बात यह है कि यह आसानी से नहीं आती है। एक पेशेवर खिलाड़ी के रूप में, आप जानते हैं कि जब आप कठिन तरीके से जीतते हैं, तो आप सम्मान का आदेश देते हैं। भारतीय टीम ने (21 वीं) शताब्दी के बाद से ऑस्ट्रेलिया में शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन तब उनके पास तेज गेंदबाजी में गहराई नहीं थी। इसलिए यह वाली भारतीय टीम ने सम्मान कमाया है।

बता दें कि इससे पहले मेलबर्न टेस्ट जीतने पर अजिंक्य रहाणे की तारीफ करते हुए कोच रवि शास्त्री ने अजिंक्य रहाणे को चालाक कप्तान बताते हुए कहा था कि उनका शांत स्वभाव विराट कोहली से बिल्कुल उलट है, जो हमेशा जोश और जुनून से भरे रहते हैं। शास्त्री ने मेलबर्न में मिली 8 विकेट की जीत के बाद कहा था, वह काफी चालाक कप्तान हैं और खेल को बखूबी पढ़ते हैं। उनके शांत स्वभाव से नए खिलाड़ियों और गेंदबाजों को मदद मिलती है। उमेश के नहीं होने के बावजूद वह परेशान नहीं हुए।

उन्होंने आगे कहा, रहाणे जब बल्लेबाजी के लिए उतरे तो हमारे दो विकेट 60 रन पर गिर चुके थे। इसके बाद उन्होंने छह घंटे तक बल्लेबाजी की। यह आसान नहीं था। उन्होंने अद्भुत धैर्य दिखाया। उनकी यह पारी मैच का टर्निंग प्वॉइंट थी।

राष्ट्रीय गान के दौरान रोने लगे सिराज, जाफर ने शेयर किया

मुम्बई, (एजेंसी)। ऑस्ट्रेलिया के साथ तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के शुरू होने के पहले टीम इंडिया के युवा तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज भावुक होकर रोने लगे। अपने करियर का दूसरा टेस्ट मैच खेल रहे सिराज की रोते हुए की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ट्विटर पर वायरल हो रही इस तस्वीर में सिराज रोते हुए और अपनी आंखें साफ करते हुए दिखाई दिए। सिराज की इस तस्वीर को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) के साथ ही भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज क्रिकेटर वसीम जाफर ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। इस तस्वीर को शेयर करते हुए जाफर ने लिखा, यहां तक कि अगर आपका उत्साह बढ़ाने के लिए बहुत कम या कोई भीड़ ना हो तो भी भारत के लिए खेलने से बेहतर कोई प्रेरणा नहीं है। एक लीजेंड ने एक बार कहा था, आप लोगों के लिए नहीं खेलते, आप देश के लिए खेलते हैं।

जाफर द्वारा शेयर की गई सिराज की इस तस्वीर और उनके लिए लिखी गई इन बातों को लोगों ने काफी सराहा है और इस ट्वीट को 25 हजार से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है। वहीं 2 हजार से ज्यादा लोगों ने इस फोटो को रीट्विट भी किया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू से पहले सिराज के पिता की मौत हो गई थी और वह आखिरी बार अपने पिता को देख भी नहीं सके थे। तब बीसीसीआई ने सिराज से वापस जाने के लिए कहा था पर पिता के देश की ओर से खेलने के सपने को पूरा करने के लिए सिराज ऑस्ट्रेलिया में ही रूके रहे । ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में खेले गए दूसरे टेस्ट और अपने डेब्यू मैच में सिराज ने शानदार गेंदबाजी की थी।

इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर जॉन लुईस बांग्लादेश टीम के बल्लेबाजी कोच बने

ढाका, (एजेंसी)। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर जॉन लुईस बांग्लादेश टीम के बल्लेबाजी कोच बनाए गए हैं। बीसीबी ने यह जानकारी दी है। बांग्लादेश ने वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली आगामी दो द्विपक्षीय श्रृंखलाओं के लिए जॉन लुईस को बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने यह जानकारी दी। श्रीलंका क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच रह चुके इंग्लैंड के 50 साल के लुईस नील मैकेंजी की जगह लेंगे जिन्होंने पारिवारिक कारणों से पिछले साल अगस्त में पद छोड़ दिया। बीसीबी के क्रिकेट संचालन चेयरमैन अकरम खान ने कहा, वह (लुईस) एक या दो दिन में आ रहा है, जिसके बाद हम निजी रूप से उनके साथ बात करेंगे। हमारी सूची में तीन या चार कोच थे लेकिन हमने उनके अनुभव पर गौर किया। छांटे गए उम्मीदवारों के बारे में आपस में बात करने के बाद, जिसमें मुख्य कोच भी शामिल थे, हमने उन्हें चुनने का फैसला किया। महामारी के कारण कोई भी दीर्घकालीन अनुबंध नहीं करना चाहता। हम कुछ श्रृंखलाओं में उनका प्रदर्शन देखेंगे और फिर देखेंगे कि हम उन्हें लंबे समय तक रख सकते हैं या नहीं। लगभग दो दशक के करियर में 16 प्रथम श्रेणी शतक जड़ने वाले लुईस की अगुआई में डरहम ने 2013 से 2016 के बीच तीन खिताब जीते। बांग्लादेश 20 जनवरी से 15 फरवरी के बीच वेस्टइंडीज की मेजबान करेगा। दोनों देशों के बीच तीन एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय और दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला होगी जिसके बाद टीम मार्च में न्यूजीलैंड दौरे पर जाएगी जहां उसे तीन एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय और तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय खेलने हैं।

मैनचेस्टर में इंग्लिश लीग कप फुटबॉल में गोल दागते हुए फर्नांडिंहों।

हवाई में चैम्पियंस गोल्फ मुकाबले में भाग लेते हुए डस्टिन जोनसन।

बीडब्ल्यूएफ पर भड़की साइना, ट्रेनर और कोच से मिलने पर रोक हटायें

बैंकॉक, (एजेंसी)। भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने थाइलैंड में होने वाले आगामी टूनार्मेंटों से पहले (ट्रेनर) और फिजियो से मिलने की अनुमति नहीं दिये जाने पर नाराजगी व्यक्त की है। साइना ने कहा है कि कोविड-19 से जुड़े सभी टेस्ट में निगेटिव आने के बाद भी बैडमिंटन महासंघ (बीडब्ल्यूएफ) का इस प्रकार का रवैया हैरान करने वाला है। साइना ने कहा है कि उन्हें इस कारण अभ्यास में परेशानी आ रही है। साइना ने बीडब्ल्यूएफ द्वारा कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत लगाए गए प्रतिबंधों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कई ट्वीट किए। साइना ने ट्वीट किया, जांच में सभी के नेगेटिव आने के बाद भी फिजियो और प्रशिक्षक हम से नहीं मिल सकते। ऐसे में हम चार सप्ताह तक खुद को फिट कैसे रखेंगे। इसलिए इस मामले का हल निकालें। साइन के अनुसार ओलिंपिक क्वॉलिफिकेशन के लिए उनके पास मार्च तक का समय है, ऐसे में प्रशिक्षण की कमी से उनके प्रदर्शन पर असर पड़ सकता है। विश्व की इस पूर्व नंबर एक खिलाड़ी ने इस मामले को लेकर बीडब्ल्यूएफ से संपर्क किया है पर उन्हें कोई जवाब नहीं मिला है। साइना ने कहा, पूरी टीम को अभ्यास के लिए सिर्फ एक घंटे का समय मिल रहा है। एक ही समय पर जिम करना है। ओलिंपिक क्वॉलिफिकेशन के लिए मार्च तक का समय है ऐसे में फिटनेस के लिए यह अच्छा नहीं है। गौरतलब है कि भारत का पूरा दल बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर फाइनल्स के दो सुपर 1000 प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आजकल थाइलैंड में है।

आईपीएल से लाभ मिला : राजा

चेन्नई , (एजेंसी)। यूएई के कप्तान अहमद राजा ने कहा है इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में विराट कोहली जैसे शीर्ष स्तर के खिलाड़ियों के साथ अभ्यास से हमें लाभ हुआ है। राजा के अनुसार इसका लाभ उनकी टीम को अबुधाबी में होने वाली एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला में आयरलैंड से मुकाबले में मिलेगा। राजा और स्पिनर कार्तिक मयप्पन ने पिछले साल सितंबर में यूएई में आईपीएल के दौरान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के साथ अभ्यास किया था थी जबकि तेज गेंदबाज जहूर खान ने मुंबई इंडियन्स टीम के साथ समय बिताया था।

राजा ने आठ जनवरी से शुरू हो रही श्रृंखला से पहले कहा, आईपीएल बहुत बड़ा टूनार्मेंट था। विराट कोहली, एबी डिविलियर्स जैसे बल्लेबाजों के साथ अभ्यास करके जो अनुभव मिला और उन्हें गेंदबाजी करना शानदार था। हमने महसूस किया कि जब हम आईपीएल से गए तो हमें काफी फायदा हुआ। उन्होंने कहा, इसे शब्दों में बताना मुश्किल है लेकिन आप अलग महसूस करना शुरू कर देते हैं और आपका रवैया भी बदल जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस दौरान हमने जो सीखा उसे इस श्रृंखला में दिखा पाएंगे। वहीं दूसरी ओर आयरलैंड के कप्तान एंड्रयू बॉलबिर्नी ने उम्मीद जताई कि उनके देश के खिलाड़ियों को भी आईपीएल अनुबंध मिलेंगे लेकिन उन्होंने कहा कि इस लुभावनी लीग में खेलने के लिए उन्हें लगातार अच्छा प्रदर्शन करना होगा।उन्होंने कहा, आईपीएल दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टी20 लीग है जिसमें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी खेलते हैं। आईपीएल में आपको दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों, सर्वश्रेष्ठ कोचों से बात करने का मौका मिलता है। और खिलाड़ियों को जो अनुभव मिलता है वह बेजोड़ है। आयरलैंड के किसी खिलाड़ी का आईपीएल फ्रेंचाइजी के साथ अनुबंध नहीं है।